दैनिक जागरण

द्वेष, ईर्ष्या, चिंता और क्रोध तन-मन को बीमार बनाते हैं

बड़ा खतरा है घुसपैठ

दैनिक जागरण की ओर से आयोजित नरेन्द्र मोहन स्मृति व्याख्यान एवं साहित्य सृजन सम्मान के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के कारणों पर प्रकाश डालते हुए जो विचार व्यक्त किए, उनसे यही पता चलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से होने वाली घुसपैठ क्यों एक गंभीर समस्या बनी हुई है? उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इस नाते घुसपैठ रोकना उनका दायित्व है, लेकिन इसी के साथ यह प्रश्न भी किया कि आखिर घुसपैठिये जाते कहां हैं और उन्हें शरण कौन देता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर दुर्गम स्थलों के कारण घुसपैठ होती रहती है, लेकिन घुसपैठिये सीमावर्ती क्षेत्रों में ही इसलिए अपना ठिकाना बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहां शरण मिलती है। इतना ही नहीं, उनके लिए फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम किया जाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह बड़ी संख्या में घुसपैठिये राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार बनवा लेते हैं। यह संभव नहीं कि राज्यों का शासन इससे अनभिज्ञ हो।

यह चिंताजनक है कि कुछ राज्य सरकारें घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देखती हैं। यही कारण है कि बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में किसी थाने में घुसपैठियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं होती। घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देखना और उन्हें शरण देना देश की सुरक्षा के साथ जानबूझकर किया जाने वाला खिलवाड़ है। घुसपैठिये शरणार्थी नहीं हैं। दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। अब यह स्पष्ट है कि कुछ राज्य सरकारें घुसपैठ रोकने को लेकर गंभीर नहीं और उलटे जब कभी घुसपैठियों को निकालने के प्रयत्न होते हैं, तो वे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जाना चाहिए कि बंगाल और झारखंड के साथ-साथ पूर्वोत्तर के कई राज्यों में वोट बैंक की संकीर्ण राजनीति के कारण ही घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। कई सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने न केवल सामाजिक तानेबाने को बदल दिया है, बल्कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इस घंटी को सभी राजनीतिक दलों को दलगत हित से ऊपर उठकर सुनना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब घुसपैठ को रोकने के मामले में राजनीतिक आम सहमति दिखनी चाहिए, तब उसके साथ-साथ मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की चुनाव आयोग की प्रक्रिया का भी विरोध किया जाता है। ऐसे में, यह और जरूरी है कि देश भर में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

जान के दुश्मन

उत्तर प्रदेश में भी हर साल पटाखों के भंडारण में चूक के कारण कोई न कोई बड़ा हादसा हो जाता है और यह सब तंत्र की अनदेखी के कारण होता है। प्रशासन और पुलिस द्वारा पटाखों की बिक्री और भंडारण के जितने मानक गढ़े जाते हैं, वह सब कागजी प्रक्रिया का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ताजा प्रकरण कानपुर के मेस्टन रोड के मिश्री बाजार का है। बुधवार शाम हुए विस्फोट ने प्रशासनिक पकड़ के दावे में भी पलीते लगा दिए। आश्चर्य है कि यहां कपड़ों और प्लास्टिक सामान की दुकानों में भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। सरकार हर साल पटाखों की बिक्री और उसके गोदाम के लिए लाइसेंस जारी करती है। यह देखा जाता है कि गोदाम आबादी से दूर रहे। खुले में बिक्री की शर्त पर ही लाइसेंस दिए जाते हैं या उनका नवीकरण किया जाता है। फिर कानपुर में बीच बाजार में यह सब आखिर कैसे हो रहा था? अभी भले ही जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, पर जरूरी है कि कोर्ट में जरूरी साक्ष्य देकर उन सब को सजा दिलाई जाए, जिन्होंने इस प्रकार के अवैध भंडारण का साहस किया। थोड़ी कमाई के लोभ में लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य जिलों में भी तत्काल जांच कर ऐसी जानलेवा प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस-प्रशासन को इसके लिए सक्रियता दिखानी चाहिए।

थोड़ी कमाई के लोभ में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए

संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत का स्मरण

सीपी राधाकृष्णन

लोकनायक जेपी का जीवन यही प्रेरणा देता है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें, परिवर्तन लाने की जनशक्ति अद्भुत और असाधारण होती है

अवधेश राजपूत

धर्म, संस्कृति और ज्ञान की भूमि बिहार में गंगा और घाघरा नदियों के संगम पर सिताबदियारा गांव में 11 अक्टूबर, 1902 को लोकतंत्र के पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। इस वर्ष हम संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार की 123वीं जन्म-जयंती मना रहे हैं। जेपी के नाम से विख्यात जयप्रकाश नारायण जी राजनेता से बढ़कर राष्ट्रनेता थे, जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि देश के गरीबों को हमेशा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 'लोकनायक' की उपाधि उन्हें किसी महान व्यक्ति ने नहीं दी थी। यह उपाधि उन्हें 5 जून, 1974 को पटना के गांधी मैदान में एकत्रित भारत के लाखों लोगों ने प्रेमपूर्वक प्रदान की थी। उनके असाधारण जीवन की नींव सिताबदियारा की साधारण पृष्ठभूमि में ही पड़ गई थी। साधारण परिवार में परवरिश ने उन्हें गरीबों की जीवनशैली और उनकी समस्याओं से जुड़े रहने में मदद की। इंटरमीडिएट की शिक्षा के दौरान ही देश में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे अहिंसक और असहयोग आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने सभी से स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया। बिहार में आरंभिक शिक्षा के बाद अमेरिका में सात वर्षों तक शिक्षा के लिए रहे। इस दौरान वे मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। हालांकि, भारत लौटने पर उन्होंने मार्क्सवादी दर्शन को भारतीय परिदृश्य के अनुरूप ढालने की व्यवहार्यता का पता लगाया और महसूस किया कि लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वोदय ही भारत की समस्याओं का समाधान हैं। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे किसी विचारधारा के अनुयायी न होकर समाज में परिवर्तनकारी सुधार और बदलाव चाहने वाले राष्ट्रनेता थे।

वर्ष 1952 में उन्होंने विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन तथा सर्वोदय के दर्शन को साथ मिलकर भारत में भूमि संबंधी समस्याओं के एक व्यावहारिक समाधान की कल्पना की। 1954-1973 के दौरान चंबल के दुर्दांत डाकुओं के पुनर्वास और अहिंसक संपूर्ण क्रांति जैसे उनके प्रयासों को दुनिया भर में सराहा गया। वे संपूर्ण मानव जाति और विशेष रूप से भारत के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और शांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहे। 'श्रम की गरिमा' से जुड़ी जेपी की समझ एवं संकल्पना सैद्धांतिक न होकर व्यक्तिगत अनुभवों से उपजी थी। अमेरिका में अध्ययन के दौरान उन्हें कई छोटी-मोटी नौकरियों के माध्यम से खुद को आर्थिक सहारा देना पड़ा। 'सीखते हुए कमाई' के अनुभव ने उन्हें श्रमिक वर्ग से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ दी, जिससे उनका यह विश्वास और दृढ़ हुआ कि सभी श्रमिक सम्मान, उचित वेतन और मानवीय कार्य परिस्थितियों के हकदार हैं। वे इसी दृढ़ विश्वास के साथ भारत लौटे कि एक न्यायपूर्ण समाज की नींव श्रमिक वर्ग के कल्याण पर टिकी होनी चाहिए। इसी क्रम में 1947 में उन्हें अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय डाक एवं तार निम्न श्रेणी कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय आयुध निर्माणी श्रमिक संघ जैसे तीन प्रमुख कर्मचारी संघों का अध्यक्ष चुना गया।

उनकी यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन तक ही सीमित नहीं रही। वे कभी सत्ता प्राप्ति के मोह में नहीं रहे। उनकी तत्परता सदैव जनसेवा के लिए रही। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही भीषण सूखे की विभीषिका से जूझ रहे बिहार को राहत देने के लिए जयप्रकाश नारायण जी भूदान आंदोलन के अपने साथियों के साथ राहत कार्यों में जुटे रहे। 'बिहार राहत समिति' के राहत कार्यों से जुड़े रहने के दौरान ही उन्हें आरएसएस के स्वयंसेवकों के 'राष्ट्रसेवा दृष्टिकोण' का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ और वे इससे प्रभावित हुए। जब लोगों का लोकतंत्र की संस्थाओं से विश्वास उठ रहा था, तब उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति में लोगों की आशा और विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया। इस आंदोलन का लक्ष्य आदर्श समाज का मानवतावादी संस्करण था। तत्कालीन राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी आवाज ने लोकतंत्र में जनशक्ति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए जनता को प्रेरित करने और जन आक्रोश को दिशा देने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय थी। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि लोकतंत्र का अर्थ जनता पर शासन करना नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनना है।

उसी कालखंड में एक 19 वर्षीय युवा के रूप में कोयंबटूर जिला संगठन सचिव के रूप में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में योगदान देना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात थी। भारत के इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर मिले अनुभव ने मुझे एक सक्षम, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से जागरूक नेता के रूप में परिवर्तित किया। इस आंदोलन ने मेरे भीतर परिपक्वता, नैतिक निर्णय और नागरिक चेतना जैसे नेतृत्व के आवश्यक गुणों को पोषित किया। लोकनायक जेपी का जीवन और शिक्षा यह है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें, परिवर्तन लाने की जनशक्ति अद्भुत और असाधारण होती है। उनकी शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर देती है, जहां समानता, न्याय और शांति का सर्वोपरि हो।

क्रांति को अक्सर हिंसा का पर्याय माना जाता है, लेकिन जेपी के नेतृत्व वाली संपूर्ण क्रांति विशुद्ध अहिंसा पर आधारित थी। एक अहिंसक जनांदोलन के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी, जो व्यवस्था और समाज के भीतर मानवतावाद और नैतिकता के मूल्यों पर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आज 11 अक्टूबर को जब हम इस महान नेता को श्रद्धापूर्वक याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें तो हम उस लोकतंत्र के सजग संरक्षक बने रहने का संकल्प भी लें। इस दिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने अंतरात्मा को जागृत करें और निस्वार्थ भाव, सेवा और सत्य के साथ देश की बेहतरी के लिए कार्य करें। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। वे भारत के सच्चे रत्न थे।

(लेखक भारत के उपराष्ट्रपति हैं)
response@jagran.com

अनेक प्रश्नों के उत्तर देगा बिहार

अवधेश कुमार

राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रचंड शोर के बावजूद बिहार में तथाकथित वोट चोरी मुद्दा बिल्कुल नहीं है

बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की दृष्टि लगी हुई है। बिहार के जमीनी हालात बताते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रचंड शोर के बावजूद धरातल पर तथाकथित वोट चोरी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। बिहार में तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रहे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। चुनाव प्रबंधक होने के कारण उन्हें मतदाता सूचियों, चुनाव की प्रवृत्तियों और परिणाम की अन्य अनेक नेताओं से ज्यादा अधिकृत जानकारी है। उनके एसआइआर के प्रति निरपेक्ष भाव का संदेश लोगों में यही गया कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या महागठबंधन के उनके अन्य साथी जानबूझकर चुनाव आयोग के साथ भाजपा के विरुद्ध लोगों के अंदर आक्रोश पैदा करने की रणनीति पर चल रहे हैं। इसकी हानि विपक्ष को इस रूप में हुई कि चुनाव पूर्व के एक महत्वपूर्ण काल में बिहार सरकार के विरुद्ध संभावित मुद्दे भी उभर नहीं सके। राजद और तेजस्वी यादव को इसका भान हुआ तो उसके बाद वह बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। इसमें उन्होंने सामान्य मुद्दे अवश्य उठाए। वोटर अधिकार यात्रा के बारे में राजद की प्रमुखता वाले महागठबंधन के समर्थकों की टिप्पणी यही है कि जितनी ऊर्जा, संसाधन उसमें लगाए गए उससे वास्तव में राजग को ही लाभ हुआ।

कुछ समय से भारत के लोगों के अंदर राजनीतिक निर्णय को लेकर सतर्कता बढ़ी है। नेपाल की हिंसक उथल-पुथल से बिहार चुनाव बिल्कुल अप्रभावित नहीं हो सकता। कुछ लोग भारत के अंदर ऐसे ही करने के प्रयास करते दिख रहे हैं। इसके कारण बहुत बड़ा वर्ग शांति, स्थिरता, विकास और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील नजर आने लगा है। आपरेशन सिंदूर और उसके बाद कुछ देशों के भारत विरोधी रवैये से भी देश में राष्ट्रवाद का भाव प्रखर हुआ है। बिहार क्षेत्रवाद के सोच से राजनीतिक व्यवहार करने वाला राज्य अब नहीं रहा। पूरे देश में हिंदुत्व के आधार पर भाजपा का एक ठोस वोट बैंक बन चुका है और चुनावों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वक्फ संशोधन कानून पर कुछ संगठनों के साथ राजद, कांग्रेस आदि के खड़ा होने तथा इस्लामिक कट्टरपंथ की घटनाओं पर उनकी चुप्पी के विरुद्ध गैर मुसलमानों के बड़े वर्ग में प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के कारण विपक्ष जहां एसआइआर में फंसा रहा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और केंद्र सरकार ने आपरेशन सिंदूर से लेकर, अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाने के अभियान चलाए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से लोगों को सीमा के साथ धार्मिक और नागरिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति सचेत करते हुए सुदर्शन चक्र की योजना रखी। सरकार जीएसटी में कटौती कर बड़ा टैक्स सुधार लेकर आ गई जिससे परिवारों को खर्चे में थोड़ी राहत मिल रही है। विपक्ष के अभियान के समानांतर प्रधानमंत्री लगातार रेल, सड़क, हवाई अड्डा, अस्पताल, कालेज, स्कूल सहित आधारभूत संरचना एवं विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास करते रहे तो दूसरी और कई योजनाओं में महिलाओं, किसानों, मजदूरों आदि के खाते में सीधे रकम स्थानांतरित हुई। इनमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत करीब एक करोड़ महिलाओं के खाते में भेजे गए 10 हजार रुपये तथा रोजगार में निवेश करने के प्रमाण पर भविष्य में दो लाख रुपये देने के वादे से भी माहौल बना है।

निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने भी कसी कमर। फाइल

भाजपा की नीति इस समय दिल्ली तथा उसके पूर्व हरियाणा, महाराष्ट्र में मिली जीत को कायम रखने की है। इसलिए वह किसी किस्म का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब नीतीश कुमार को लेकर भाजपा के स्वर पूरी तरह बदल गए हैं। एक-एक नेता उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने तथा पुनः उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए जाने का बयान दे रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव या अन्य नेताओं का यह कहना कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जनता के गले नहीं उतर रहा। प्रशांत किशोर ने लगातार अपनी यात्राओं, सभाओं और वक्तव्यों से बिहार से जुड़े अनेक आवश्यक, लोगों को स्पर्श करने वाले मुद्दे उठाए। इससे जन जागरण हुआ है। बावजूद इसके बिहार का वर्तमान राजनीतिक समीकरण बदल जाने की संभावना जमीन पर नहीं दिखती है। मतदाताओं के सामने प्रश्न है कि केंद्र में नरेन्द्र मोदी और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को कायम रखकर राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, शांति, विकास, इस्लामिक कट्टरपंथ का सरकार द्वारा नियंत्रण और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें या कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण उनके विरुद्ध जाएं?

बिहार में हमने 2005, 2010, 2014 और 2019 में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर मतदान करते देखा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा का राजग से बाहर आकर 137 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के परिणामस्वरूप राजद महागठबंधन को समतुल्य मत प्रतिशत एवं सीटें प्राप्त हुईं। इस बार लोजपा राजग गठबंधन में है तथा जीतन राम मांझी के हम एवं उपेंद्र कुशवाहा के लोकतांत्रिक मोर्चा के कारण भी इसकी शक्ति बढ़ी है। राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन में पशुपति पारस, विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी भरपाई करेंगे, ऐसा नहीं लगता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अभाव

धनवान हो या निर्धन, सभी को कभी न कभी, किसी न किसी प्रकार के अभाव का अनुभव होता ही है। किसी मनोवांछित वस्तु का अपने पास उपलब्ध न होना अभाव है। अभाव कई प्रकार का हो सकता है। रोटी, कपड़ा, मकान या रुपये-पैसे के अभाव को भौतिक अभाव तो प्रेम, सम्मान, ज्ञान, स्वास्थ्य, अनुभव, समय जैसे विषयों के अभाव को अभौतिक अभाव कहा जा सकता है। भौतिक अभाव को प्राथमिक अभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका व्यक्ति के जीवन निर्वहन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अभाव का अनुभव मनुष्य में निराशा, चिंता, हीनभाव, असंतोष और वंचना के भाव उत्पन्न कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है कि अभाव का व्यक्ति पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। अभाव व्यक्ति को कठिन परिश्रम करके अपने जीवन से अभाव को दूर करने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसे अनेक सफल लोगों के उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं, जो अपने प्रारंभिक जीवन के अभावों से जूझने की प्रेरणा के बल पर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचे। ऐसा भी अकसर देखने को मिलता है कि जिनके जीवन में कोई प्राथमिक या कोई अन्य प्रभावकारी अभाव नहीं होता या जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, वे कठिन परिश्रम से जी चुराते हैं।

भारतीय दार्शनिक परंपरा में अभाव के सकारात्मक महत्व का विशेष वर्णन है। इसके अनुसार अभाव हमें सीमित साधनों में जीना सिखाता है। यह हमारे अंदर संतोष, धैर्य और सहनशीलता जैसे उत्तम गुणों के विकास में सहायक होता है, जिसके परिणामस्वरूप हम दूसरों का हक मारने या उनसे ईर्ष्या करने जैसे दुर्गुणों से बच जाते हैं। अतः यही उचित है कि व्यक्ति अभाव के नकारात्मक प्रभावों से विचलित न होकर इसे कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणास्रोत माने और अभावग्रस्त परिस्थिति में भी सदैव संतुलित रहने का प्रयास करे।

डा. अरुण कुमार तिवारी

सड़क दुर्घटनाओं पर कब लगेगी लगाम

रंजना मिश्रा

सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले हर एक नागरिक की भी है

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में देश की सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। दरअसल भारत में सड़क सुरक्षा एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन चुका है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत में 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.72 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब हर दिन 474 से ज्यादा परिवार अपने किसी प्रियजन को हमेशा के लिए खो देते हैं। इन दुर्घटनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को हर साल जीडीपी का तीन प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होता है, जो हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर एक भारी बोझ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करते हुए तीन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान खींचा है, पैदल चलने वालों की सुरक्षा, हेलमेट का अनिवार्य उपयोग, और खतरनाक ड्राइविंग की आदतें।

पैदल चलने वाले, हमारी सड़कों पर सबसे असहाय और असुरक्षित हैं। वर्ष 2023 में लगभग 35 हजार पैदल यात्रियों को वाहनों ने कुचल दिया। शहरों में फुटपाथ या तो हैं ही नहीं, या उन पर दुकानों और पार्किंग का कब्जा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलने को मजबूर हैं। जेब्रा क्रासिंग को कुछ वाहन चालक एक सजावटी पट्टी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ऐसा लगता है मानो सड़क पर चलने वाला पैदल यात्री एक दोयम दर्जे का नागरिक है, जिसकी जान की कोई कीमत नहीं। कोर्ट का निर्देश इस बुनियादी मानवीय अधिकार को स्थापित करने की मांग करता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित रूप से चलने का अधिकार है। यह जानते हुए भी कि सिर की चोट जानलेवा होती है, लोग हेलमेट पहनने से बचते हैं। वर्ष 2023 में 54,000 से अधिक मौतें सिर्फ इसलिए हुईं, क्योंकि दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहने थे। कई बार लोग चालान से बचने के लिए सस्ते और घटिया हेलमेट खरीद लेते हैं, जो सुरक्षा के नाम पर एक धोखा है। लगभग 68 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करना, गलत दिशा से ओवरटेक करना एक आम बात बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ चालान काटना काफी नहीं है, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके, जैसे हर जगह कैमरे लगाकर, पारदर्शी तरीके से नियमों को लागू करना होगा।

सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि सड़क का उपयोग करने वाले हर एक नागरिक की भी है। हम अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी तो थमा देते हैं, लेकिन उन्हें सड़क शिष्टाचार और कानून का सम्मान सिखाना भूल जाते हैं। सड़क सुरक्षा को स्कूलों में एक अनिवार्य विषय बनाना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता

आदित्य सिन्हा का आलेख ''दवाओं की गुणवत्ता से समझौता'' पढ़ा। चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डाक्टरों द्वारा किया गया अध्ययन अत्यंत चिंताजनक है, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि एंटीफंगल दवा इट्राकोनाजोल के 22 जेनेरिक संस्करणों की तुलना में केवल 29 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं ने दो सप्ताह में अपेक्षित स्तर हासिल किया, जबकि पेटेंट दवाओं में यह स्तर 73 प्रतिशत तक था। यह स्थिति देश में जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता और उनकी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में किफायती होती हैं, जिससे आम जनता को लाभ मिलता है, लेकिन यदि कम कीमत की आड़ में गुणवत्ता से समझौता किया जाता है तो यह मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। हाल में देश में एक जेनेरिक कफ सीरप कोल्ड्रिफ के उपयोग से कई बच्चों की दुखद मृत्यु ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार द्वारा जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित करना एक सराहनीय कदम है, किंतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये दवाएं प्रभावी, सुरक्षित और विश्वसनीय हों। संबंधित नियामक संस्थाओं को चाहिए कि वे कठोर गुणवत्ता मानक लागू करें, नियमित जांच करें और दोषी निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस संदर्भ में समाज के सभी वर्गों को जागरूक होना चाहिए और दवाओं की गुणवत्ता के प्रति सजग रहना चाहिए। केवल तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

डा. प्रदीपकुमार संघवी, झाबुआ

मेलबाक्स

लापरवाही का नतीजा

जयपुर के एक अस्पताल में आग लगने से छह मरीजों की जान जाने और अन्य के घायल होने ने फिर से सरकार पर अग्निशमन प्रबंधों को लेकर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्यों अस्पतालों में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते? क्यों आग से निपटने के लिए जरूरी हिदायतों और प्रबंधों का जायजा नहीं लिया जाता? आग लगने से अस्पताल में मरीजों की जान जाना सरासर सरकार की लापरवाही का नतीजा है। समय रहते अगर आग से निपटने के प्रबंधों का जायजा लिया जाए और स्टाफ को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता है। अगर सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों का यह हाल है तो निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा अग्निशमन व्यवस्थाओं का क्या ही जायजा लिया जाता होगा? देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर आश्रित है। निजी अस्पतालों में भारी भरकम फीस के चलते ज्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में आग लगने के ऐसे भयानक हादसे सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा देते हैं। आग लगने की स्थिति में साइरन का बजना, अग्निशमन यंत्रों का ठीक से काम करना, स्टाफ को इन यंत्रों को चलाने में दक्ष होना, आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह और आपातकालीन द्वारों का होना कुछ जरूरी पैमाने हैं जिनका अगर पालन किया जाए तो कीमती जिंदगियों को आग के हवाले होने से बचाया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है, सरकार को जागने की, रूटीन चेकिंग की और कड़े नियम बना उनका पालन हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी रखने की।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

पांडुलिपियों में निहित है ज्ञान

प्राचीन पांडुलिपियों में निहित ज्ञान से हमें स्वत्व का बोध होकर हम मानव मूल्यों की ओर प्रेरित होते हैं। पांडुलिपियां सिर्फ ज्ञान के नाम पर सूचनाओं का संकलन मात्र न होकर धर्म, दर्शन, संस्कृति तथा भाषा आदि पर प्रकाश डालती हैं। सिर्फ राजनीतिक या भौतिक दृष्टि ही किसी समाज एवं सभ्यता के सही आकलन का अधूरा मूल्यांकन है। पांडुलिपियां हमारे पास वह अमूल्य निधि हैं जो हजारों वर्ष की ऋषि परंपरा में अतिन्यून संसाधनों में तथा तप, त्याग एवं आर्षदृष्टि से ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं। ज्ञानभारतम् मिशन से विशाल पांडुलिपियों का संग्रह संरक्षित ही नहीं होगा, बल्कि समाज में शोध प्रवृत्ति भी निश्चित रूप से बढ़ेगी।

अर्जुन सिंह, संभल

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

7,500 से अधिक दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गईं थीं, कुछ वर्ष पहले तीन राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों से जांच के लिए इकट्ठा किए गए दवा के नमूनों में से।

आजकल

भारतीय दवा उद्योग की साख पर असर

भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने दवा बाजार को 130 अरब डालर से अधिक का बनाने का है। सरकार इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिसके तहत नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार से सीरप से जुड़ी घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए कई आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। यदि दवा कंपनियां इसी तरह अपनी साख गिराती रहीं तो निर्यात घट सकता है। फिर यह लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, लिहाजा इस बारे में विचार किया जाना चाहिए

संजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

वर्ष 2022 में गांबिया में एक आयातित कफ सीरप पीने से वहां 70 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। इसकी वजह उसमें इंडस्ट्रियल ग्रेड के डाइथाइलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल की भारी मात्रा थी। यह कफ सीरप एक भारतीय दवा कंपनी का बनाया हुआ था। दो साल पहले एक देशी कंपनी के बने सीरप के इस्तेमाल से जम्मू-कश्मीर में 17 बच्चों की मौत हो गई थी। सीरप में डाइथाइलीन ग्लाइकोल की मात्रा काफी ज्यादा थी। तब भारत सरकार ने डाइथाइलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल मिले कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आज जिस कफ सीरप के पीने से बच्चे मरे हैं, वह भी स्वदेशी है और बच्चों की मौत का कारण वही इंडस्ट्रियल ग्रेड का डाइथाइलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल है।

मतलब यह कि तीन बरसों में कुछ बदला नहीं है। गांबिया के बच्चों को मौत देने वाली हरियाणा की दवा कंपनी ने तब कहा था कि वह उत्पादन प्रक्रिया में 'स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रोटोकाल का सही पालन कर रही थी'। उसने इस घटना पर हैरानी और गहरा दुख भी जताया था। परंतु जांच के दौरान दवा निर्माण प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं पाई गईं। इसके बावजूद कंपनी को दंड देकर छोड़ दिया गया।

दवा बनाने के नियंत्रण में इसी ढिलाई के चलते आज भारतीय बाजार में बिकने वाले दवा उत्पादों में से 20 प्रतिशत से अधिक नकली हैं और लगभग इसी अनुपात में अमानक भी। कफ सीरप कांड के बाद केवल एक राज्य की फौरी जांच में पैरासिटामोल, ओआरएस घोल, सामान्य आई-ड्राप्स और फेसवाश जैसी सैकड़ों सामान्य उपयोग की दवाएं दूषित या अमानक पाई गईं।

टीका बनाने के मामले में दुनिया का यह अग्रणी देश 'फार्मेसी आफ द वर्ल्ड' कहलाता है। देश में तीन हजार से अधिक दवा कंपनियां और लगभग 13 हजार क्रियाशील दवा उत्पादन इकाइयां हैं। हम 190 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात करते हैं। वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं की 20 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति हम ही करते हैं और 2030 तक अपने दवा बाजार को 130 अरब डालर से अधिक का बनाने का लक्ष्य भी रखते हैं। सरकार सक्रिय रूप से फार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है, जिसमें नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना शामिल है। लेकिन यदि दवा कंपनियां इसी तरह दवा निर्माण के क्षेत्र में अपनी साख गिराती रहीं तो यह लक्ष्य कैसे संभव होगा? बिना इन पर नियंत्रण के बाकी उपलब्धियां बेमानी लगती हैं। हालिया घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी दवा नियंत्रण प्रणाली में गहरी खामियां हैं। यदि इन्हें समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया तो कहीं भी अत्यंत दारुण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दवा सीधे सेहत और जीवन से जुड़ी भरोसे की चीज है। यदि इसकी विश्वसनीयता गिरती रही तो यह नुकसानदेह साबित होगी।

केंद्र सरकार ने भी अपेक्षाकृत त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स की आपात बैठक बुलाई, जो स्वागतयोग्य कदम है। परंतु दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम तभी मिलेंगे जब ईमानदारी से कार्रवाई भी हो। शीघ्र ही सरकार द्वारा दवा निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं के काम को सुगम करने के लिए लाया गया जनविश्वास विधेयक राज्यसभा से पास होकर कानून की शक्ल ले सकता है। इसके तहत ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27(डी) में फेरबदल का प्रस्ताव है। सरकार का सोच सकारात्मक है- यह संशोधन विदेशी निवेशकों के लिए दवा व्यापार आसान बनाएगा और सस्ती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाएगा।

सच तो यह है कि हमें दवा से जुड़ी प्रणालियों को मजबूत करने की जरूरत है- नकली, अमानक और मिलावटी जानलेवा दवाओं के लिए कड़े जुर्माने और सीधे जेल की आवश्यकता है, न कि किसी ढील या माफी की। देश में आए दिन लाखों-करोड़ों की नकली दवाओं की बरामदगी होना और विदेश में भारतीय दवा उद्योग की हालिया बदनामी से उबरने तथा 'दुनिया के दवाखाने' की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें इस क्षेत्र में सख्त नियामकीय ढांचे का विकास करना होगा। भारत को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दवा उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद की समान गुणवत्ता हेतु कड़ी नियंत्रण प्रणाली और संहिता अनिवार्य करनी होगी। दवा निर्माण और वितरण से जुड़े नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिस नौकरशाही पर है, वह बेकार, अक्षम और भ्रष्ट न हो, इसकी निगरानी राज्य और केंद्र सरकारों दोनों को रखनी होगी।

वैसे समस्या केवल उत्पादन स्तर में नहीं है- निगरानी, गुणवत्ता-परीक्षण और लाइसेंसिंग की ढीली व्यवस्थाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कई बार जानलेवा दवाओं को रिकाल और रैपिड-अलर्ट दिशा-निर्देशों के तहत 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया जा सका। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। दवा उद्योग को राहत देना और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना, साथ ही आम नागरिकों की सेहत और जान की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना। ऐसे में सख्त नियमों के साथ प्रत्येक राज्य में आधुनिक प्रयोगशालाएं और त्वरित परीक्षण व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रशिक्षण स्तर में सुधार लाना होगा तथा दवा निर्माण से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़कर हर बैच का स्रोत और गुणवत्ता तुरंत जांची जाए ताकि दवा दर्द न दे। यदि सरकार सख्ती और जवाबदेही को आत्मसात करती है, तो वह देश की दवाओं तथा भारतीय दवा उद्योग की विश्वसनीयता को बचा लेगी। यही आशा की जानी चाहिए। (ईआरसी)

वैश्विक स्तर पर भारतीय दवाओं की बेहतर छवि कायम रखने के लिए इनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना होगा। फाइल

सुनिश्चित हो नियमों का समुचित पालन

विकास आसावत
पेटेंट अटार्नी एवं एडवोकेट

मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कफ सीरप के उपयोग से बच्चों की तबियत बिगड़ने व कुछ की मौत होने की खबरें विचलित करने वाली हैं। चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट में इस सीरप के बैच नंबर एसआर-13 में डायइथाइलीन ग्लाइकाल (डीईजी) की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा (48.6 प्रतिशत तक) पाई गई, जबकि स्वीकार्य सीमा 0.10 प्रतिशत तक ही है। डीईजी एक जहरीला औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग एंटीफ्रीज, ब्रेक द्रव आदि में किया जाता है, जबकि इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए अत्यधिक विषाक्त होती है और नर्वस सिस्टम, हृदय व किडनी को प्रभावित करता है। डीईजी युक्त कफ सीरप के दुष्प्रभाव के संबंध में देश में पहला मामला 2019 में जम्मू-कश्मीर से जुड़ा है।

किसी भी दवा के दुष्प्रभाव को समझने के लिए फार्माकोडायनामिक्स (पीडी) की जानकारी जरूरी है जो शरीर और दवा के बीच की अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करता है। पीडी का लक्ष्य न्यूनतम आवश्यक खुराक पर सकारात्मक प्रभाव डालना है जिससे अधिकतम चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न होता है। दवाओं को देते समय उम्र, लिंग, अन्य किसी रोग से ग्रसित होना, वजन का खास ध्यान रखा जाता है व दो डोज के बीच के अंतराल की भी अनुपालना को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दवा के दूषित होने में फार्मा ग्रेड की जगह इंडस्ट्रियल ग्रेड डीईजी का इस्तेमाल, विनिर्माण प्रक्रिया में संदूषण, परिवहन के दौरान अत्यधिक तापमान, आर्द्रता, अनुपयुक्त पैकिंग के कारण शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त होना, सीधे सूरज की रोशनी, ठंडी, सूखी जगह पर संग्रहित न करना, जैसे कई कारण हो सकते हैं। साथ ही बैक्टीरिया, नमी, वाष्प, बाह्य धूल आदि भी संदूषण के कारक हो सकते हैं। दूषित होने के कारण दवाओं की प्रभाविता कम हो सकती है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है व अत्यधिक गंभीर अवस्था में रोगी की मौत भी संभव है।

दवा के दूषित होने की आशंका को न्यूनतम करने से स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वसनीयता बनी रहेगी व रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लिहाजा दवा निर्माता केवल योग्य और प्रामाणिक आपूर्तिकर्ताओं से ही फार्मास्युटिकल ग्रेड एक्सिपिएंट्स खरीदें व इस्तेमाल से पहले उसका व्यापक परीक्षण करें। निर्माता द्वारा मटेरियल, निर्माण प्रक्रिया व टेस्ट संबंधी सटीक रिकार्ड रखने के साथ ही मार्केट में नकली, सब-स्टैंडर्ड दवाओं पर निगरानी व स्वयं की दवाओं की भौतिक स्थिति की जांच भी महत्वपूर्ण है। पूर्व में हुए कटु अनुभवों को देखते हुए बाल चिकित्सा फार्मूलेशन में प्रयुक्त एक्सिपिएंट बैचों की पूर्ण ट्रेसिबिलिटी बनाए रखना आवश्यक होगा। रिटेल व होलसेल मेडिकल स्टोर व घरों में दवा पर लिखे डायरेक्ट सनलाइट व नमी वाले क्षेत्र से दूरी संबंधित निर्देश का पालन हो। दवा की शीशी खुलने के बाद उसके उपयोग की समय सीमा जैसी जानकारी भी रोगी को परेशानी से बचा सकती है।

कफ सिरप के दूषित होने की घटना के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा सिस्टमैटिक गैप्स व गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की पहचान करने के लिए विनिर्माण इकाइयों में रिस्क-बेस्ड इंस्पेक्शन करने का निर्णय लेना सरकार की तरफ से ठोस कदम है। इन इंस्पेक्शन से दवा की गुणवत्ता में दोष के कारण व चूक उजागर करने में मदद मिलेगी। साथ ही भविष्य के लिए सदृढ़ रोडमैप का सुझाव भी सामने आएगा। वस्तुतः निर्माता द्वारा गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन, रेगुलेटर्स की सख्ती व कड़ी निगरानी, न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से क्रियान्वयन, सप्लाई चेन एजेंसी व केमिस्ट की नियामक-निर्देशों के प्रति सजगता व ग्राहक की नैतिक जिम्मेदारी, दवा के संदूषण व असमंजस की स्थिति से निपटने में कारगर कारक है।

खरी-खरी

भेड़ वाली डीपी

सुनील जैन राही

डीपी बदलने का मौसम आ गया है। चुनाव घोषणा के साथ ही नेता से लेकर कार्यकर्ता तक डीपी में मासूम दिखाई देने की कोशिश में जुटे गए हैं। डीपी में सुधार किया जा सकता है, चरित्र और व्यवहार में नहीं। चुनाव के दौरान ही यह छलावा करना है, फिर वही ढाक के तीन पात। डीपी देखकर शायद वोटर का मन बदल जाए, सोचने लगे पहले जैसी बात न हो।

दसियों रिटेक हुए, मासूम से मासूम चेहरा बनाने की भरसक कोशिश की, मन में यहां तक विचार लाया गया कि मां मर गई, बाप स्वर्ग सिधार गया है, इसके बावजूद चेहरे पर मासूमियत नहीं आ पा रही थी। मासूम चेहरा ही वोटर प्रभावित कर सकता है।

नेता धूर्त होता है, सबको पता है, लेकिन धूर्तता के साथ मासूमियत का मिश्रण होने से कद्र में इजाफा हो जाता है। पार्टी थिंक टैंक का रिसर्च विंग जब थक गया तो सोचा जानवरों में मासूमियत खोजी जाए। गाय से लेकर सुअर तक की डीपी लगाकर देखा। नेताजी गाय की तरह नहीं सीधे नहीं थे, सुअर की डीपी लगा नहीं सकते थे। गाय और सुअर दोनों से वोट बैंक प्रभावित होने का डर था। कुत्ते और गधे की डीपी लगाने से पोल खुल सकती थी।

आखिरकार भेड़ की डीपी लगाने पर विचार होने लगा। भेड़ की दिनचर्या से लेकर स्वभाव, प्रवृत्ति पर रिसर्च विंग ने काम किया। आदतों को परखा गया। ऐसा कुछ करने की युक्ति निकाली गई, ताकि वह भेड़ के रूप में दिखाई दे और भेड़ में भेड़िया के गुण भी नजर आए। निष्कर्ष निकाला गया कि नेताजी बेसिकली भेड़िया हैं, क्यों भेड़ की खाल पहना दी जाए? बात सटीक और फिट बैठ गई। फोटोशाप करते हुए शरीर भेड़ का और मुंह भेड़िये का किया गया। नेताजी अति प्रसन्न हुए। दो भाव एक साथ। मासूम भी और दानवी भी। कोई भेड़ न समझे हम किसी भेड़िये से कम नहीं हैं। शरीर और दिमाग भेड़िये का और मासूमियत भेड़ की। चुनाव परिणाम आ गए। भेड़ की डीपी ने चुनाव परिणाम पक्ष में कर दिए। डीपी बदलने का समय आ गया। नेताजी ने डीपी में भेड़ की खाल उतरवा दी, अब खालिस भेड़िया दिखाई दे रहा है।

X पोस्ट

दो साल लग गए बोलना सीखने में और 80 साल लग गए, चुप रहा जाए सीखने में।
अमिताभ बच्चन@SrBachchan

तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों की मौजूदा स्थिति इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। पाकिस्तान को लगा था कि उसने अफगानिस्तान में जीत हासिल कर ली है। जबकि भारत सतर्क था। इसने तालिबान से सतर्कतापूर्वक बातचीत की। अब पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में समस्या खड़ी हो गई है।
यूसुफ ऊंझावाला@YusufDFI

डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि इस बार नोबेल शांति पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा, लेकिन नतीजे आए तो फिर से वही बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली स्थिति है।
अनामिका जैन अंबर@anamikamber

एक स्त्री जिसने वेनेजुएला में तानाशाही के अंधेरे में लोकतंत्र की मशाल जलाई, वे जेल गईं, लेकिन झुकी नहीं। नाम है- मारिया कोरिना मचाडो। आज पूरी दुनिया उन्हें जान रही है, क्योंकि उन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार।
अपूर्व@grafidon

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या बिहार में हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी यादव का वादा विश्वसनीय है?

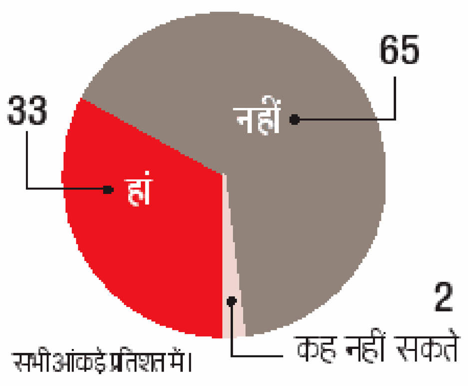

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या भारत द्वारा अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोलने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लालू जी दे नौकरी लिखवा लिए जमीन,
बेटा देकर नौकरी घर भी लेगा छीन!
घर भी लेगा छीन घूमियेगा हो पैदल,
'आज' दीजिए वोट सोच करके अपना 'कल'।
सब्जबाग दिखलाय जीतते नेता चालू,
वैसा ही है पूत कि जैसे थे खुद लालू!!
- ओमप्रकाश तिवारी

बिहार डायरी

स्वयं की जीत महसूस कर रहे मतदाता

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

चुनाव में जीत हार होती है। परिणाम के बाद राजनीतिक दल लाभ-हानि का हिसाब करते हैं। जनता अपने रोज के कामधाम में लग जाती है। पांच साल प्रतीक्षा करती है। बिहार विधानसभा का संभवतः यह पहला चुनाव है, जिसमें मतदाता मतदान से पहले लाभ का हिसाब लगा रहे हैं। साफ-साफ बता रहे हैं कि चुनाव से पहले उन्हें इतने रुपये का लाभ हुआ है। राजनीतिक दलों की ओर से की गई और की जा रही घोषणाओं का हिसाब यह है कि मतगणना से पहले जनता जीत का अनुभव कर रही है।

ठीक इसके विपरीत राजनीतिक दलों का आत्मविश्वास डगमगाया सा लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि घोषणाओं में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। राजद को महसूस हुआ कि कुछ कमी रह गई है। सो, तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनी तो हरेक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। कल कारखानों की बहार आ जाएगी। तेजस्वी बता रहे हैं कि हमारी सरकार बिहार के सारे दुख-दर्द दूर कर देगी।

इससे पहले राज्य की एनडीए सरकार की ओर से घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई है। तेजस्वी की घोषणाओं से पहले सरकारी योजनाएं नकद के रूप में मतदाताओं के खाते में जमा हो रही हैं। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में यह राशि 10 हजार है तो छात्राओं के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 से 75 हजार रुपये तक जमा कराए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि पहले ही चार सौ से बढ़ा कर 11 सौ रुपये कर दी गई है। प्रति परिवार मासिक 125 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने की योजना लागू हो चुकी है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि राज्य के सभी वर्ग के मतदाताओं के लिए कुछ न कुछ लाभ की योजनाएं शुरू की गई हैं। पक्ष-विपक्ष की योजनाओं और घोषणाओं से मतदाता गदगद हैं। इसके बाद भी उन्हें कुछ और लोकलुभावन घोषणाओं की आस है।

चुनाव से पहले ही बहुत कुछ हासिल होने और दलों के वादों से मतदाता उत्साहित दिख रहे हैं। फाइल

यह अलग बात है कि राज्य की आर्थिकी को समझने वाले लोग सरकार की घोषित योजनाओं की निरंतरता पर संदेह कर रहे हैं। तेजस्वी की सरकारी नौकरी देने की घोषणा को भाजपा की उसी घोषणा का राज्य संस्करण माना जा रहा है, जिसके तहत हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार-नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल भी तेजस्वी की घोषणा का अधिक विरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा नीतीश कुमार की ओर से पहले ही की जा चुकी है।

राज्य के खजाने का हिसाब यह है कि पिछले कई वर्षों से आंतरिक संसाधन के माध्यम से धन संग्रह करने की क्षमता नहीं बढ़ रही है। खनन, भू लगान, निबंधन और राज्य जीएसटी, आंतरिक संसाधन से धन जुटाने के यही कुछ स्रोत हैं। राज्य बजट के 70-75 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। अनुदान, विशेष सहायता और केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के मद में यह राशि मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि यह स्थिति एनडीए के शासन में बनी है। यह वर्षों से है। वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद दक्षिण बिहार के खदानों से रायल्टी और सेस के रूप में मिलने वाली राशि बंद हो गई। इधर 2016 से उत्पाद से होने वाली आमदनी पर भी ताला लग गया। आने वाले वर्षों में यदि बड़े पैमाने पर कल कारखाने खुलते हैं तो आंतरिक आय के नए स्रोत बन सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन की ओर से तेज औद्योगिक विकास का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन, अभी यह पानी में पड़ी हुई मछली की तरह है, जिसके हाथ में आए बिना लाभ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

समर्थक और विरोधी भी योजनाओं की निरंतरता के बारे में तर्कपूर्ण बहस नहीं करते हैं। भविष्य में क्या होगा? इसके बारे में मतदाताओं ने न कभी पहले विचार किया, न आज कर रहे हैं। राज्य के लिए शुभ यह हो रहा है कि पहले की तरह यह चुनाव जाति-धर्म के नाम पर केंद्रीत नहीं होने जा रहा है। उम्मीदवारों के गुण-अवगुण पर भी मंथन हो रहा है। सभी दलों में योग्य उम्मीदवारों की खोज हो रही है। यहां तक कि कई ऐसे विधायक, जिनकी जीत असंदिग्ध मानी जाती है, अलोकप्रिय छवि के कारण बेटिकट होने की आशंका से ग्रस्त हैं। परिवार और वंश का आग्रह समाप्त हो जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले की तुलना में इस प्रवृत्ति में कमी आएगी, ऐसी आशा की जा रही है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक-दो दिनों में गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। तब चुनाव की असली तस्वीर सामने आएगी।

मंथन

सामाजिक सहभागिता और संघ

आज की पीढ़ी एल्गोरिदम की गिरफ्त में है- स्क्रीन पर निर्भर, अस्थिर और अकेली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव से उन्हें उस हर चीज की प्राप्ति हो सकती है जो आधुनिक शिक्षा में नहीं है

गौतम कुमार झा
असिस्टेंट प्रोफेसर, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन विद्यालय, जेएनयू

डिजिटल युग में युवाओं की दुनिया अनगिनत संपर्कों से भरी हुई है। हर पल नोटिफिकेशन, चैट, काल और फीड से घिरी। फिर भी, यह बाहरी हलचल और भीतर गहरी खामोशी पैदा कर रही है। वे दिखते तो 'आनलाइन' हैं, पर असल में भावनात्मक रूप से 'आफलाइन' हो चुके हैं। डिजिटल युग की यह पीढ़ी हर समय 'कनेक्टेड' दिखती है, लेकिन भीतर से पहले से कहीं अधिक डिसकनेक्टेड है- परिवार, समाज और स्वयं से। स्मार्टफोन ने ध्यान-एकाग्रता को इतना सीमित कर दिया है कि अब यह सामाजिक और राष्ट्रीय संकट बन गया है।

जब तकनीक मनुष्य की भावनाओं और सामाजिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने लगे, तब राष्ट्र-निर्माण की जड़ें ही हिल जाती हैं। यह केवल पारिवारिक नहीं, सामूहिक चेतना और नागरिक अनुशासन का प्रश्न है। स्वाभाविक है कि ऐसे समय में एक ऐसा संगठन, जो अनुशासन, सेवा और राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत हो, युवाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार कर सकता है। यही संगठन उन्हें भटकाव से निकालकर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में सार्थक योगदान के लिए प्रेरित करता है। इसी दृष्टि से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा और जीवन-दृष्टि प्रदान करने की क्षमता रखता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से अधिक प्रासंगिक दिख रहा है।

शारीरिक अनुशासन : आरएसएस प्रशिक्षण में शारीरिक व्यायाम, योग और सामूहिक खेलों का विशेष महत्व है। यह केवल शरीर को सुदृढ़ नहीं बनाता, बल्कि मन और व्यवहार में स्थिरता लाता है। नियमित अभ्यास से युवा एकाग्रता, संयम और सहनशीलता जैसी मूलभूत जीवन-क्षमताएं विकसित करते हैं। आज के डिजिटल युग में, जब स्क्रीन जीवन का केंद्र बन चुकी है, यह शारीरिक अनुशासन युवाओं को डिजिटल व्यसन से मुक्ति और जीवन में संतुलन की दिशा प्रदान करता है।

संघ की शाखाओं में सामूहिकता की भावना सबसे प्रमुख है। सहभोज, सामूहिक प्रार्थना, संवाद और मिलकर कार्य करने की परंपरा युवाओं को यह सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति समान है और सबका योगदान जरूरी है। जब संगठन में समन्वय हो और दायित्व किसी भार के रूप में नहीं, बल्कि योग्यता के प्रतीक के रूप में महसूस किया जाए, तब व्यक्ति स्वयं को सबल मानने लगता है। इसी अनुभव से युवाओं में टीम भावना, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। यह सहभागिता केवल संगठनात्मक अनुशासन नहीं, बल्कि जीवन के लोकतांत्रिक संस्कारों का वास्तविक अभ्यास है।

नैतिक आधार : आरएसएस का प्रशिक्षण नैतिकता और आचरण को जीवन के केंद्र में रखता है। ईमानदारी, आत्मसंयम, सेवा और चरित्रबल जैसी अवधारणाएं यहां केवल पढ़ाई नहीं जातीं, बल्कि जी जाती हैं। हर गतिविधि, हर निर्णय और हर संवाद में यह मूल्य अंतर्निहित रहते हैं। यह नैतिक ढांचा युवाओं को प्रलोभनों से बचने और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। संघ का यह जीवन-दर्शन उन्हें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्म-नियंत्रण और जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय चेतना : संघ की सबसे बड़ी देन है भारत माता के प्रति प्रेम, गर्व और कर्तव्य-बोध की भावना। यह केवल राष्ट्रभक्ति का नारा नहीं, बल्कि एक जीवन-दृष्टि है, जिसमें व्यक्ति समाज और देश की उन्नति को अपना स्वाभाविक धर्म मानता है। शाखाओं में गाए जाने वाले गीत, संवाद और संस्कार युवाओं में राष्ट्र के प्रति भावनात्मक एकता को पुष्ट करते हैं। यह वह चेतना है जो व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठाकर समष्टि के हित में सोचने की प्रेरणा देती है- यही राष्ट्रीयता का जीवंत रूप है।

शाखाओं की गतिविधियां युवाओं में राष्ट्र के प्रति भावनात्मक एकता को मजबूत करती है। फाइल

अनुशासन और नैतिक जीवन : संघ का अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि भीतर से उपजा आत्म-नियंत्रण है। प्रत्येक शाखा एक लघु-लोकतंत्र की तरह कार्य करती है, जहां निर्णय संवाद, सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। यह अनुशासन किसी दंड या भय से नहीं, बल्कि संस्कार और जिम्मेदारी से जन्म लेता है। शारीरिक व्यायाम, योग, संयमित दिनचर्या और नशामुक्त जीवनशैली केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म-संयम की साधना हैं, जो व्यक्ति को भीतर से दृढ़, संतुलित और जागरूक बनाती हैं।

सामाजिक समरसता : संघ के लिए 'राष्ट्रीयता' कोई संकीर्ण अवधारणा नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी चेतना है। आदिवासी शिक्षा से लेकर शहरी सेवा कार्यों तक, ग्राम विकास से लेकर बाल संस्कार केंद्रों तक, संघ का प्रयास समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को जोड़ने का है। यह केवल 'अधिकार' की नहीं, बल्कि 'कर्तव्य' की संस्कृति सिखाता है, जहां समाज का हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हुए समरस भारत के निर्माण में भागीदार बनता है। आज जब समाज वर्ग, भाषा और धर्म के आधार पर विभाजनों में उलझा है, तब आरएसएस की यह समरस दृष्टि पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, एक ऐसी दृष्टि जो कहती है: राष्ट्र की शक्ति उसकी विविधता में नहीं, उसकी एकता में निहित है।

****

कल्पमेधा

शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे।

– महात्मा बुद्ध

जोखिम की तकनीक

तेजी से बदलते दौर में नई तकनीकों के उपयोग को वक्त की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी क्रम में आम जिंदगी में संवाद से लेकर पढ़ाई-लिखाई और लेन-देन जैसे तमाम मामले अगर डिजिटल तकनीक के दायरे में आ रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। इसी के मद्देनजर 'डिजिटल इंडिया' का नारा भी दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट आधारित तकनीकों के उपयोग के प्रति आकर्षित हों। विडंबना यह है कि जिस तेजी के साथ डिजिटल यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, उसी अनुपात में इसमें सुरक्षित गतिविधियों का ढांचा विकसित नहीं हुआ है। इससे उपजने वाले जोखिम रोज नए और जटिल स्वरूप में सामने आ रहे हैं। अमूमन हर रोज देश के किसी हिस्से से डिजिटल धोखाधड़ी की खबरें आती हैं और उसमें किसी की मेहनत की कमाई के लाखों रुपए अलग-अलग तरीके से लूट या उड़ा लिए जाते हैं। ऐसे मामले आम हैं, जिनमें सिर्फ किसी को फोन पर की जाने वाली बातचीत में उलझा कर उसे धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। सवाल है कि अगर देश में आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया जा रहा है तो क्या इससे बचाव के इंतजामों को भी उतना ही अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि डिजिटल फर्जीवाड़े के मामलों में कोई अचानक उफान नहीं आया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ है कि आधुनिक तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतना ही यह जोखिम का वाहक भी बन रही है। किसी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है और वह व्यक्ति बातों के जाल में इस कदर फंस जाता है कि अपने बैंक खाते से खुद ही लाखों रुपए भेज देता है। इसके कुछ ही पल बाद जब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले आम होते देखे गए हैं, जिसमें अनजान नंबर से आए फोन काल के जरिए किसी व्यक्ति को डरा-धमका कर 'डिजिटल कैद' की स्थिति में डाल दिया जाता है और फिर भयादोहन करके उसके बैंक खाते में जमा रकम को उड़ा लिया जाता है।

अब ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं रह गई हैं, लेकिन इसमें तेजी से होते इजाफे ने यह सवाल पैदा किया है कि जिन डिजिटल संसाधनों का विकास सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, आज उसी से उपजे खतरे से निपटने के तौर-तरीके आम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने या उन्हें खत्म करने के दावे के साथ डिजिटल दुनिया का विस्तार किया गया, कुछ जगहों पर व्यवहार में इसे अनिवार्य बना दिया गया, मगर आज हालत यह है कि सख्त कानूनों के बावजूद फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह साइबर संजाल में रोज नए तरीके अपना कर आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि एक समस्या डिजिटल यंत्रों के उपयोग में लापरवाही से लेकर प्रशिक्षण की सीमा की भी है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा का सवाल बेमानी नहीं हो जाता। निश्चित रूप से 'डिजिटल इंडिया' एक आकर्षक नारा है, लेकिन अगर इसमें जोखिम का पैमाना इतना ही ऊंचा रहता है, तो इसकी कामयाबी संदिग्ध ही रहेगी।

उत्पीड़न का तंत्र

हरियाणा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आत्महत्या और उससे जुड़े तथ्यों के संबंध में जैसी खबरें आई हैं, वे विचलित करने वाली हैं। यह अफसोसनाक है कि देश में फैली कुरीतियों और दुराग्रहों को दूर करने की उम्मीद जिस तंत्र से की जाती है, कई बार वह खुद भी इससे मुक्त नहीं दिखता है। गौरतलब है कि हरियाणा में भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी वाई पूरन कुमार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार 'असहनीय उत्पीड़न' से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उन्हें अधिकारों और अन्य मुद्दों से संबंधित मामलों में मुखर हस्तक्षेप के लिए जाना जाता था। खबरों के मुताबिक, एक 'आखिरी नोट' में उन्होंने कुछ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और दुर्भावनापूर्ण तरीके से छद्म शिकायतें दर्ज कराने आदि का गंभीर आरोप लगाया। भारतीय पुलिस सेवा के तहत अपने पद पर काम करते हुए किसी उच्च अधिकारी के सामने भी अगर आत्महत्या की नौबत आती है तो यह हर स्तर पर चिंता की बात होनी चाहिए। सवाल है कि सरकारी तंत्र के भीतर भी दबाव की राजनीति कैसे इस तरह काम करती है कि एक व्यक्ति के सामने जीने-मरने का सवाल आ खड़ा हो।

सही है कि हमारे समाज में आज भी समाज के हाशिये के तबकों के खिलाफ बहुस्तरीय भेदभाव और उत्पीड़न की जड़ें गहरी दिखाई देती हैं और कमजोर पृष्ठभूमि के लोग कई बार इसका सामना नहीं कर पाते। लेकिन उम्मीद की जाती है कि पद, प्रभाव या आर्थिक हैसियत में सक्षम होने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक अपमान, अत्याचार या जाति-आधारित भेदभाव करना आसान नहीं होता। अफसोस की बात है कि इस तरह के द्वेष के मनोविज्ञान और उसके काम करने का ढांचा इतना जटिल और बारीक होता है कि कई बार इसका शिकार होने वालों के सामने विकल्प सिमटते जाते हैं। हालांकि हरियाणा में पुलिस अधिकारी की आत्महत्या की घटना में जांच का कोण फिलहाल उनके 'आखिरी नोट' पर निर्भर है, लेकिन इसकी गहन और पारदर्शी तरीके से जांच इसलिए भी जरूरी है कि आरोपों की सत्यता सामने आए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और यह सभी स्तर पर एक सबक का काम करे।

सूखती नदियां और संरक्षण की राह

देश में नदियों और सहायक नदियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों से लेकर क्षेत्रीय नदियां कई स्थानों पर बांध, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण अपने पुराने स्वरूप को खोती जा रही हैं।

मनीष जैसल

पिछले कुछ दशकों से देश में नदियों और अन्य सहायक नदियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहीं झरने सूख गए, तो कहीं नदियों का बहाव इतना कम हो गया कि उनकी जीवंतता पर संकट मंडरा रहा है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों से लेकर हमारी क्षेत्रीय नदियां कई स्थानों पर बांध, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। मध्यप्रदेश जिसे 'नदियों का मायका' कहा जाता है, वहां भी आज कई नदियों के उद्गम स्थल विलुप्त होने के कगार पर हैं। वास्तव में मनुष्यों ने अक्सर अपनी सुविधा और औद्योगिक विकास की प्राथमिकता में नदियों को नजरअंदाज किया है। पिछले बीस वर्षों में नर्मदा और अन्य नदियों के किनारे फैली औद्योगिक इकाइयों ने जल स्रोतों को प्रदूषित किया और गोधूलि जैसी कई छोटी नदियां और जलधाराएं सूखती गईं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के दौर में कृत्रिम मेधा (एआइ) इस संकट से नदियों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत में नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को महती नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि गंगा और यमुना को पुराणों तथा महाकाव्यों में देवी एवं जीवनदायिनी का दर्जा दिया गया है। गंगा स्नान को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। महाकुंभ का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि नदियों का महत्त्व केवल जल की आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। इसलिए देश में नदियों का संरक्षण केवल जल संकट की समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

सिंध, क्षिप्रा, बनास और कूनो जैसी नदियां भले ही प्रदूषित नदियों की श्रेणी में न आती हों, लेकिन किनारे पर पसरी गंदगी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के निस्तारण का अभाव, अतिक्रमण और जल स्तर में कमी यह संकेत देती हैं कि यदि संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वक्त की कल्पना की जा सकती है। इन नदियों का महत्त्व जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है। वे कृषि, पारिस्थितिकी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार हैं। नदियों पर संकट के कई कारण हैं। कारखानों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट सीधे नदियों में मिलते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। अवैध रेत खनन और अतिक्रमण नदियों के किनारे प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पानी की उपलब्धता खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है।

यह कोई छिपी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना बड़े स्तर पर प्रदूषण की मार झेल रही हैं। दिल्ली से गुजरती यमुना का पानी इतना दूषित है कि उसे सुरक्षित नहीं माना जाता। प्रतिदिन लाखों लीटर गैर-उपचारित अपशिष्ट सीधे इसमें गिरता है। गंगा की सहायक नदियां जैसे गंडक और घाघरा अतिक्रमण तथा रासायनिक प्रदूषण से लगातार प्रभावित हो रही हैं। बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी तथा बागमती अब अपने असामान्य बाढ़ चक्र और प्रदूषण के लिए जानी जाती हैं। मानसून में प्रलयंकारी बाढ़ हजारों परिवारों को बेघर कर देती है, जबकि

गर्मियों में यही नदियां सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में गोदावरी और ताप्ती नदी की स्थिति चिंताजनक है। नासिक और अन्य शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट गोदावरी को प्रदूषित कर रहा है। ताप्ती के कुछ हिस्सों में जल इतना दूषित है कि मछलियां और अन्य जलीय जीव

नदियों के किनारे पर पसरी गंदगी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के निस्तारण का अभाव, अतिक्रमण और जल स्तर में कमी यह संकेत देती हैं कि यदि संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वक्त की कल्पना ही की जा सकती है। नदियों का महत्त्व जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है। वे कृषि, पारिस्थितिकी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार हैं। नदियों पर संकट के कई कारण हैं। कारखानों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट सीधे नदियों में मिलते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। अवैध रेत खनन और अतिक्रमण नदियों के किनारे प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पानी की उपलब्धता खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है।

लगभग लुप्त हो चुके हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की छोटी नदियां तो सूखे की वजह से केवल कागजों पर ही बची हैं।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में देश में जल निकायों की गणना कराई थी। इसमें लगभग 24.24 लाख तालाब, झीलें, जलाशय जैसी संरचनाओं और कृत्रिम जल स्रोतों को चिह्नित कर उनकी स्थिति का पता लगाया गया। इस पहल से यह स्पष्ट हुआ कि किस राज्य में कितने जल स्रोत हैं और उनमें से कितने उपयोगी हैं तथा कितने अतिक्रमण या सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की समय-समय पर रपट यह बताती रही है कि देश की अधिकांश प्रमुख नदियों विशेषकर गंगा, यमुना, साबरमती और गोमती का जल स्वच्छता मानकों से काफी नीचे है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली में यमुना की हालत बेहद खराब है। इसमें प्रदूषण की वजह से जल की गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मार्च 2025 में यमुना में फास्फेट और औद्योगिक अपशिष्ट की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई।

दूसरी ओर छोटी नदियों का अपना महत्त्व है। ये बड़ी नदियों का आधार हैं और अपने क्षेत्र की बड़ी आबादी के जीवन को सींचती हैं। इनके संरक्षण के लिए जितना जरूरी सरकारी प्रयास हैं, उतना ही समाज की सक्रिय भागीदारी भी है। इसमें दोराय नहीं कि आज के तकनीकी दौर में कृत्रिम मेधा नदियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों, ड्रोन से निगरानी और 'रीयल-टाइम डेटा एआइ माडल' के जरिए नदियों के जल स्तर, बहाव और प्रदूषण की स्टीक जानकारी मिल पाती है। इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने से समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं। 'गूगल अर्थ' और अन्य एआइ उपकरण नदियों के बदलते स्वरूप और प्रवाह का रेकार्ड रखने में मदद करते हैं। 'वाटरसिम' और 'रिवरवेयर' जैसे कृत्रिम मेधा माडल बाढ़ और सूखे की समय रहते चेतावनी देने में सक्षम हैं।

कृत्रिम मेधा आधारित मोबाइल एप और अन्य मंच नागरिकों को अपनी नदियों की स्थिति का पता लगाने का अवसर देते हैं। इनकी मदद से लोग नदी किनारे प्रदूषण, जल स्तर में बदलाव या अतिक्रमण की जानकारी तुरंत साझा कर सकते हैं। स्मार्ट सेंसर और अन्य कृत्रिम मेधा उपकरण जल गुणवत्ता, रासायनिक प्रदूषण और जैव विविधता की निगरानी करते हैं। इसके अलावा कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षा और जन-जागरूकता मंच भी बनाए जा सकते हैं। बच्चों और युवाओं में यह संदेश फैलाया जा सकता है कि नदियां केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति का आधार हैं। जब समाज के हर वर्ग को इसका महत्त्व समझ आएगा, तभी नदियों का संरक्षण स्थायी रूप से संभव हो पाएगा।

कई देशों में कृत्रिम मेधा का नदियों और अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए पहले से ही उपयोग हो रहा है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी आफ शेफील्ड और सीमेंस की साझेदारी में क्लाउड-आधारित एक कृत्रिम मेधा की प्रणाली विकसित की गई है, जो सीवेज पाइप में अवरोध का पता लगाने में मदद करती है। इससे नदियों में अपशिष्ट के अनियंत्रित प्रवाह और प्रदूषण को रोकने में मदद मिल रही है। हालांकि देश में इस काम के लिए तकनीक का होना ही पर्याप्त नहीं है। नीति निर्धारकों और प्रशासन को कृत्रिम मेधा उपकरणों से मिलने वाली जानकारी का सही इस्तेमाल करना होगा। नदियों के संरक्षण के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होगी। तकनीक के साथ आम नागरिकों की जागरूकता और सरकार की नीतियां मिल कर नदियों को नया जीवन दे सकती हैं। यह न केवल जल संरक्षण, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर होगी।

पहचान का संकट

दुनिया मेरे आगे

बेला गर्ग

हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम अपनी जड़ों से कटते हुए आधुनिकता और प्रगति की चकाचौंध में अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। यह त्रासदी केवल व्यक्ति स्तर पर नहीं, समाज और राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई देती है। एक तरफ तकनीक, शिक्षा, राजनीति और भौतिकता का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ संस्कृति, परंपरा और मूल्य बिखरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पहचान खोने का दौर है, जहां व्यक्ति अपने भीतर से खाली होता जा रहा है और समाज अपनी आत्मा से।

शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना या रोटी-रोजगार की गारंटी भर नहीं है। शिक्षा का मूल स्वरूप व्यक्ति में विवेक, संवेदनशीलता, सृजनशीलता और आत्मविश्वास जगाना होता है। लेकिन आज शिक्षा अब केवल अंक, डिग्री और पैकेज का पर्याय बनकर रह गई है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र किसी मशीन की तरह प्रशिक्षित तो हो रहे हैं, पर उनमें मनुष्यता घटती जा रही है। वे अपनी जमीन, अपने गांव, अपनी संस्कृति से अनजान रह जाते हैं। उनकी सोच उपभोक्तावाद से संचालित होती है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिक्षा व्यक्ति को 'उपभोक्ता' तो बना रही है, 'संस्कारवान नागरिक' नहीं।

शिक्षा के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। यह एक विसंगति है। तर्कशास्त्र का एक शब्द है- विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान। जैसे चमकती हुई रेत पानी का आभास कराती है, दूर से चमकती हुई सीपी चांदी का भ्रम पैदा करती है और अंधेरे में पड़ी हुई रज्जु या रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। यह विपर्यय है। विद्या के अध्ययन के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अपराध में पढ़े-लिखे और पैसे वाले लोग भी लिप्त हैं। कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ आदमी में इतनी चालाकी नहीं होती कि वह बारीक योजना बनाए, जिससे किसी को पता न चले और वह कानून की पकड़ से बाहर रहे। पढ़-लिख लेने के बाद चालाकी और क्षमता तो आ जाती है, लेकिन उसी मात्रा में नैतिकता का विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास हो और नैतिकता का विकास न हो, तो आदमी सड़क खोद कर गड्ढा करके वहां कीचड़ पैदा करेगा और फिर गाड़ी फंसने पर लोगों से पैसे वसूल कर उनकी गाड़ियां निकलवाएगा। जानबूझकर समस्या पैदा करने, उसमें दूसरे लोगों को फंसाने और पैसे लेकर उन्हें समाधान देने के लिए लोग बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। हमने बुद्धि को अंतिम विकल्प और सीमा मान लिया, यही सारी समस्याओं की जड़ है।

राजनीति कभी लोकसेवा का माध्यम मानी जाती थी, अब वह सत्ता-सुख और स्वार्थ-सिद्धि का औजार बन चुकी है। राजनीति का लक्ष्य अब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक समीकरणों पर टिके रहना है। राजनीतिक दल मूल्यों पर बहस करने के बजाय चुनावी गणित साधने में व्यस्त हैं। आधुनिकता का अर्थ अगर वैज्ञानिक सोच, समानता और नए विचारों का स्वागत है तो यह स्वागतयोग्य है। पर जब आधुनिकता केवल उपभोग, फैशन और प्रदर्शन तक सिमट जाए तो यह आत्मा को खोखला कर देती है। आज का युवा अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना डूबा है कि उसे लोकगीत, लोकनृत्य, लोककला की कोई खबर नहीं। घर-आंगन में गाए जाने वाले मंगलगीत, तीज-त्योहार की पारंपरिक उमंग और पड़ोस की साझी संस्कृति सब खोती जा रही है। संस्कृति का स्थान अब मनोरंजन चैनल मोबाइल और ऐप ले चुके हैं। त्योहार का अर्थ मिलन और उत्सव नहीं रहा, बल्कि 'सेल' और 'रियायती आकर्षण' हो गया है। भौतिक संपन्नता को ही जीवन की सफलता मान लिया गया है। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान और बैंक में पैसे ही आज की उपलब्धि के मानक हैं। इस दौड़ में रिश्तों की ऊष्मा, परिवार की आत्मीयता और सामाजिक जिम्मेदारी पिछड़ गई है। संस्कृति हमें संयम, सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाती थी। लेकिन भौतिकवाद हमें असीमित इच्छाओं का दास बना रहा है। उपभोक्तावाद की इस दौड़ ने हमें प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में उलझा दिया है।

संस्कृति केवल नृत्य, संगीत या परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब संस्कृति टूटती है तो समाज की आत्मा घायल होती है। आज स्थिति यह है कि गांव के चौपाल, मंदिर-मस्जिदों की साझी संस्कृति, आपसी मेल-मिलाप, और सामूहिकता का भाव खत्म हो रहा है।

संस्कृति केवल नृत्य, संगीत या परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब संस्कृति टूटती है तो समाज की आत्मा घायल होती है। आज स्थिति यह है कि गांव के चौपाल, मंदिर-मस्जिदों की साझी संस्कृति, आपसी मेल-मिलाप, और सामूहिकता का भाव खत्म हो रहा है। उनकी जगह कृत्रिमता और निजी स्वार्थ ले रहे हैं। जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारी पहचान खो जाती है। यही पहचान का संकट आज हर तरफ दिखता है। इस त्रासदी का समाधान हमारी शिक्षा, राजनीति, आधुनिकता और भौतिकता में संतुलन से निकलेगा। शिक्षा में रोजगार के साथ संस्कार और संवेदना को जोड़ना होगा। आधुनिकता का अंधानुकरण नहीं, विवेकपूर्ण स्वीकार करना होगा। और भौतिकता को साधन मानकर संयमपूर्ण उपयोग करना होगा।

पद-प्रतिष्ठा, सत्ता आदि ऐसे उन्माद हैं, जिनके आगे पढ़ाई-लिखाई सब नाकाम हो जाते हैं। जब तक उसे सकारात्मक भाव का विकास नहीं होता, चरित्र या नैतिक मूल्यों के विकास की कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। आज की यही सबसे बड़ी समस्या है कि चरित्र का विकास हम बौद्धिक ज्ञान से करना चाहते हैं। यह संभव नहीं। हमारा चरित्र पक्ष, आचार पक्ष ही हमारी श्रेष्ठता पर मुहर लगाएगा, ज्ञान की बात तो बाद की है। ईमानदारी की पूछ और परख गुजरे जमाने में भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। यह ऐसी निधि है, जिसकी कीमत कभी घट नहीं सकती।

दवा के जोखिम

'जानलेवा दवा' (संपादकीय, 7 अक्तूबर) पढ़ा। हर पिछले हादसे को लोग भूल जाते हैं। कोई नया हादसा होने पर ही सरकारी महकमों की नींद खुलती है। खांसी की प्रतिबंधित दवा लेने से मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में कई बच्चों की मौत ने सबको झकझोर दिया है। इससे पहले भी भारत में निर्मित कफ सिरप के इस्तेमाल से जांबिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले सामने आने पर दवा उद्योग की साख पर बट्टा लगने के बाद भी यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि देश में बन रहीं दवाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। एक ओर मध्यप्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों ने दावा किया था कि बच्चों की मौत का कारण मानी जा रही सिरप में विषाक्त रसायन नहीं मिला। जबकि जिस तमिलनाडु राज्य में दवा का निर्माण हुआ उनकी जांच में पता चला कि कफ सिरप में 48.6 फीसद खतरनाक तत्त्व 'डायथिलीन ग्लाइकाल' पाया गया। देश में यदि दोयम दर्जे की दवाओं का निर्माण जारी रहता है, गुणवत्ता और परीक्षण के नाम पर खानापूरी की जाती है, तो ऐसे में निर्दोष मासूमों की मौत के मामले सामने आते रहेंगे। इससे दवा उद्योग की छवि मलिन ही होगी।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम, हरियाणा

आफत की बारिश

'मौसम का मिजाज' (संपादकीय, सात अक्तूबर) पढ़ा। प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं, कब कहर बरपा दे। अब तो मौसम के मिजाज ने हर किसी को हैरान कर रखा है। प्रकृति के कोप को अब तक कोई काबू नहीं कर सका है। यही वजह है कि इस बार तो बरसात ऐसी हुई कि कई राज्यों के नागरिकों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश ने कई इलाकों से खासी तबाही मचाई। आए दिन बादल फटने की घटनाएं हुईं। भूस्खलन से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कुछ ऐसे राज्यों में बारिश ने भारी नुकसान किया, जहां अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्तूबर में भी बारिश ऐसी हो रही है, मानो सावन-भादो चल रहा हो। मानसून लौटने के बाद लोग अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। बाढ़ अब स्थायी समस्या बन गई है, लेकिन इससे निपटने के लिए पहले से कोई ठोस तैयारी नहीं की जाती। बरसात के वक्त हर वर्ष होने वाले करोड़ों-अरबों रुपए के नुकसान को रोकने के लिए अब दूरगामी योजना बनानी होगी।

– साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

चुनाव का मैदान

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य की जनता पूरे उत्साह से चुनाव में भाग लेती है। चौक-चौराहे से लेकर गांवों के चौपाल तक, हर जगह एक ही चर्चा है कि इस बार सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। सभी राजनीतिक दलों की असली परीक्षा चुनावी मैदान में होती है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाएगा, तो विपक्ष जनता के मुद्दों को उठा कर सत्ता परिवर्तन का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। अन्य मुद्दों के साथ विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को भी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। गठबंधन और समीकरण भी चुनाव का महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति सामाजिक और जातीय संतुलन पर टिकी रहती है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। किसानों को स्थायी समाधान चाहिए और आम लोगों को महंगाई तथा भ्रष्टाचार से राहत की प्रतीक्षा है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

सेहत के सामने

पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण का बढ़ना चिंताजनक है। यह स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे के प्रति आगाह करता है। आमतौर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ ध्वनि प्रदूषण का जब आकलन करते हैं तो तो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को प्रदूषण मानते है। बड़े वाहनों में इस्तेमाल होने वाले 'प्रेशर हार्न' पर अंकुश होना चाहिए। डीजे और लाउडस्पीकर की ध्वनि में भी ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पताल आदि की चारदीवारी पर मेहंदी की झाड़ी और आसपास घने पेड़ होने चाहिए, ताकि ये ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर सकें। सड़कों के किनारों दोनों ओर घने वृक्ष लगाने से भी ध्वनि की तीव्रता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने का संकल्प लेने की जरूरत है, ताकि सभी नागरिक स्वस्थ रहें।

– संजय वर्मा 'दृष्टि' मनावर जिला, धार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत रूप में देखने पर जोर

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (**ब्यूरो**)।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के तत्वावधान में शिक्षाविद–साहित्यकार राजेंद्र जोशी द्वारा संपादित पुस्तक 'आजीवन अधिगम और एक स्वास्थ्य' (दृष्टि और सृष्टि) का लोकार्पण गुरुवार को संस्था के सभागार में किया गया।

मुख्य अतिथि जगदीश कौर ने कहा कि मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत रूप से देखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजेंद्र जोशी ने भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में आयुर्वेद की भूमिका को रेखांकित किया। संघ के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर राजेश बताया कि इस अवसर पर 'फोस्टरिंग लाइफलांग लर्निंग इन हायर एजुकेशन : एआइ टू एआइ' का भी लोकार्पण किया गया। अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर एल राजा ने कहा कि आजीवन अधिगम और एक स्वास्थ्य पुस्तक गहन संबंध को रेखांकित करती है। समारोह में कई जानी–मानी हस्तियां शामिल हुईं।

'आजीवन अधिगम और एक स्वास्थ्य' पुस्तक का हुआ लोकार्पण।

अदालत में जूता उछालने के मामले में प्रधान न्यायाधीश ने कहा

घटना से हम स्तब्ध, अब यह विस्मृत अध्याय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि वह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उस समय स्तब्ध रह गए थे जब छह अक्तूबर को एक वकील ने उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया। अब यह मुद्दा एक 'विस्मृत अध्याय' है। घटना सोमवार को उस समय हुई, जब प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ वकीलों द्वारा उल्लेख किए गए मामलों की सुनवाई कर रही थी।

आरोपी वकील राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और उसे न्यायाधीशों की ओर उछालने का प्रयास किया। इस कृत्य की चौतरफा निंदा हुई थी। प्रधान न्यायाधीश ने वनशक्ति मामले में फैसले की समीक्षा और संशोधन का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। प्रधान न्यायाधीश ने जूता फेंकने के प्रयास की घटना पर कहा कि सोमवार को जो कुछ हुआ उससे मैं और मेरे विद्वान साथी (न्यायमूर्ति चंद्रन) बहुत स्तब्ध हैं। हमारे लिए यह एक विस्मृत अध्याय है। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने दोषी वकील के खिलाफ की गई कार्रवाई से असहमति जताई और कहा कि इस पर मेरे अपने विचार हैं, वह प्रधान न्यायाधीश हैं, यह मजाक की बात नहीं है! न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि यह घटना 'सुप्रीम कोर्ट का अपमान' है और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कृत्य को अक्षम्य बताया। शीर्ष विधि अधिकारी ने प्रधान न्यायाधीश की उदारता और महानता की सराहना की। अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन से सुनवाई को आगे बढ़ाने तथा इस चौंकाने वाले प्रकरण पर आगे चर्चा न करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया कि हमारे लिए यह एक विस्मृत अध्याय है। इसके बाद पीठ मामले की सुनवाई करने लगी।

आपत्तिजनक एआइ वीडियो बनाने पर एफआइआर

पुलिस ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के बारे में एआइ की मदद से बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में नवी मुंबई के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नवी मुंबई के पनवेल निवासी के रूप में पहचाने गए आरोपी ने कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का इस्तेमाल करके न्यायमूर्ति गवई के लिए अपमानजनक संदर्भों वाला एक वीडियो बनाया। पनवेल तालुका पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पनवेल के एक व्यक्ति ने मंगलवार को कई सोशल मीडिया मंचों पर साझा किए गए इस वीडियो को देखा और शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर, बुधवार को भारतीय न्याय संहिता और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उसका पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

वीडियो के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है।

पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों को आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने के निर्देश भी जारी किए हैं।

आंबेडकरवादी संगठनों ने हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (ब्यूरो)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कई आंबेडकरवादी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर 'हमले' की घटना को 'न्यायपालिका का अपमान और संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार' करार देते हुए गुरुवार को इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।

उच्चतम न्यायालय के वकील राकेश किशोर ने छह अक्तूबर को अदालत कक्ष में प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता उछालने का प्रयास किया था। इस दौरान, किशोर को सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे चिल्लाते हुए सुना गया था। नानासाहेब इंदिसे के नेतृत्व में कई आंबेडकरवादी संगठनों के सदस्यों ने ठाणे में कोर्ट नाका स्थित बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली तख्तियां थाम रखी थीं। कार्यकर्ता राजाभाऊ चव्हाण और भास्कर वाघमारे ने ठाणे नगर पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत भी दी।

भाजपा का तंत्र कमजोर वर्गों के लिए अभिशाप बन चुका है : खरगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरियाणा के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा का मनुवादी तंत्र इस देश के अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और कमजोर वर्गों के लिए अभिशाप बन चुका है।

वाई पूरण कुमार (52) 2001 बैच के आइपीएस अधिकारी थे और वह मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में मृत पाए गए थे। अधिकारी के सेक्टर 11 स्थित आवास के भूतल के एक कमरे में उनका शव मिला। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि भाजपा का मनुवादी तंत्र इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी व कमजोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। कुमार की मजबूरन आत्महत्या की खबर न केवल स्तब्ध करने वाली है, बल्कि सामाजिक अन्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयावह प्रमाण है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मानसिकता इतनी गहरी कर दी है कि एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय नहीं मिलता।

आइपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या का मामला।

हादसा मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बुधवार रात दुर्घटनाग्रस्त हुई क्षतिग्रस्त पोर्श कार का मलबा पुलिस स्टेशन में।

बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय औषधि नियामक की कार्रवाई

दवा इकाइयों के परीक्षण व लेखा जांच अभियान शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

केंद्रीय औषधि नियामक सीडीएससीओ ने कफ सिरप निर्माता इकाइयों के परीक्षण और आडिट के लिए पूरे भारत में अभियान शुरू किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

नियामक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आडिट के लिए कफ सिरप निर्माता कंपनियों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के बाद उठाया गया है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक किसी भी राज्य ने सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई (सीएपीए) दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जो सुरक्षित दवा उत्पाद सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए शुरू किए गए हैं। अब तक, 18 राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों ने आनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंस प्रणाली (ओएनडीएलएस) को अपनाया है, जिसका उद्देश्य औषधि लाइसेंस और नियामक अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है। ओएनडीएलएस भारत में विभिन्न दवा–संबंधी लाइसेंसों की प्रक्रिया के लिए एक डिजिटल, एकल–खिड़की मंच है। भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से आग्रह किया था कि वे मध्यप्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा उत्पादों को बाजार में भेजने से पहले उनके कच्चे माल और तैयार उत्पाद का परीक्षण सुनिश्चित करें।

डीसीजीआइ ने एक परामर्श में कहा कि विनिर्माण संयंत्रों के हालिया निरीक्षणों और 'मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं' घोषित की गई दवाओं की जांच के दौरान यह पाया गया कि कई निर्माता उपयोग से पहले निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए दवा निर्माण में सहायक सामग्री के प्रत्येक बैच और सक्रिय अवयवों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं।

अभी तक किसी भी राज्य ने दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, जो सुरक्षित दवा उत्पाद सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए शुरू किए गए हैं।

डीसीजीआइ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों से आग्रह किया था कि वे मध्यप्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर दवा उत्पादों को बाजार में भेजने से पहले उनके कच्चे माल और तैयार उत्पाद का परीक्षण सुनिश्चित करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शंका जताई, सरकार ने कहा

खांसी की तीन दवाओं की खेप वापस मंगाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

केंद्रीय औषधि नियामक सीडीएससीओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सूचित किया है कि तीन कफ सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर और रीलाइफ को वापस मंगाया गया है और निर्माताओं को इनका उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि औषधि नियामक ने बुधवार को वैश्विक स्वास्थ्य एजंसी को सूचित किया कि इनमें से कोई भी उत्पाद भारत से निर्यात नहीं किया गया था। डब्लूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से जानना चाहा था कि क्या देश में बच्चों की मौत से जुड़ा कफ सिरप दूसरे देशों को निर्यात किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की बीमारियों और मौतों के बारे में भारत से आई हालिया मीडिया रपट पर कड़ी नजर रख रहा है।

दूषित कफ सिरप के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश के पांच बच्चों की हालत गंभीर है, जबकि 20 बच्चों की मौत मिलावटी कफ सिरप के सेवन से हुए गुर्दा संक्रमण के कारण हुई है। प्रयोगशाला जांच में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकाल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकाल (ईजी) की मात्रा अधिक पाई गई है।

दूषित कफ सिरप के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश के पांच बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है, जबकि 20 बच्चों की मौत मिलावटी कफ सिरप के सेवन से हुए गुर्दा संक्रमण के कारण हुई है।

सुप्रीम कोर्ट जहरीली दवा के मामले में आज करेगा सुनवाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने गुरुवार को कहा कि यह मामला गंभीर है और तत्काल सुनवाई योग्य है।

याचिका में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में जांच और सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे पूर्व आइपीएस अधिकारी शिवदीप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर।

भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के पूर्व अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे ने गुरुवार को कहा कि वह बिहार में दो सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लांडे ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, 'मैंने निर्णय लिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में दो सीटों जिसमें जमालपुर और अररिया से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ूंगा।'

उन्होंने बताया कि, 'मैंने अपनी राजनीतिक पार्टी 'हिंद सेना' इस अप्रैल में बनाई थी, लेकिन यह अभी तक निर्वाचन आयोग से इसका पंजीकरण नहीं सका है।'

पेज 1 का बाकी

एक पंक्ति का आदेश नहीं, नाम काटने की वजह विस्तार से बताएं

कारण सहित आदेश के माध्यम से निपटाने के प्रश्न पर 16 अक्तूबर को अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की अपील दायर करने में सहायता के लिए अर्ध–विधिक स्वयंसेवकों की सूची जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास ऐसे लोगों के नाम की अस्वीकृति के विस्तृत आदेश हों।

सुनवाई की शुरुआत में शीर्ष अदालत में उस समय नाटकीय स्थिति पैदा हो गई जब वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि बिहार एसआइआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एडीआर) ने एक व्यक्ति का फर्जी विवरण दिया है, जिसने दावा किया है कि उसका नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है। द्विवेदी ने बताया कि एनजीओ के हलफनामे में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, उसका नाम मसविदा मतदाता सूची में नहीं है और उन्होंने जो विवरण दिया है, वह किसी महिला का है।

पीठ ने विवरण पर गौर करने के बाद कहा कि हमें हैरानी है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद है। एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्हें ये विवरण एक बेहद जिम्मेदार व्यक्ति ने मुहैया कराए हैं। जिस मतदाता ने दावा किया है कि उसका नाम बिहार की अंतिम मतदाता सूची में नहीं है, उसका नाम प्राधिकरण द्वारा पता लगाया जा सकता है। पीठ ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि इसकी उम्मीद नहीं थी और स्पष्ट किया कि वह कुछ टिप्पणियां कर सकती है। द्विवेदी ने कहा कि एनजीओ और अन्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं और निर्वाचन आयोग को अपना जवाब दाखिल करना है।

खांसी की दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार

सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्यरात्रि को शुरू किए गए अभियान के बाद रंगनाथन को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए सुंगुवरछत्रम थाने ले जाया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश पुलिस की टीम के आने के बाद से ही दोनों राज्यों की पुलिस की टीम सात अक्तूबर से जी रंगनाथन की तलाश कर रही थी और आखिरकार बुधवार देर रात करीब डेढ़ बजे रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कांचीपुरम स्थित कारखाने से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए अदालत में पेश किए जाने के बाद रंगनाथन को छिंदवाड़ा ले जाया जाएगा। श्रीपेरंबदूर औषधि नियंत्रण निरीक्षक ने सात अक्टूबर को दवा कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दवा की गुणवत्ता और लेबलिंग में विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।

वहीं, छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सिंह नेत्री ने बताया कि पांच वर्षीय विशाल की बुधवार शाम को और चार वर्षीय मयंक सूर्यवंशी की देर रात पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चे छिंदवाड़ा के परासिया कस्बे के रहने वाले थे। इस मामले में अब मृतकों की संख्या 22 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार, छिंदवाड़ा के इन बच्चों की मौत गुर्दा खराब होने के कारण हुई, जिसका संबंध 'विषाक्त' कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस ने मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है और तमिलनाडु स्थित कोल्ड्रिफ निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

उधर, तमिलनाडु सरकार ने खांसी की दवा में मिलावट के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमणियन ने बताया कि उस फार्मा कंपनी को स्थायी रूप से बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिसकी दवा से कथित रूप से कई बच्चों की मौत हुई। दोनों अधिकारियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उन्होंने पिछले दो वर्षों से श्रीसेन फार्मा की विनिर्माण इकाई का निरीक्षण क्यों नहीं किया। जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

सुब्रमणियन ने कहा कि तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने खांसी के सिरप (कोल्ड्रिफ) में मिलावट की पुष्टि की और हमने तत्काल केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, ओड़ीशा और पुदुचेरी को इस खतरे की जानकारी दी। हमारी त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ी त्रासदी टल गई। उधर, परासिया के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की मौतों की जांच के बीच दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के एक उप निदेशक को निलंबित कर दिया था और राज्य के औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया था।

छिंदवाड़ा के चिकित्सक प्रवीण सोनी को कथित कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परासिया शहर की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को डाक्टर सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

जम्मू-कश्मीर : लापता जवान का शव मिला, दूसरे की तलाश

इलाका और खराब मौसम इन प्रयासों में बाधा बन रहे हैं। मंगलवार को कोकेरनाग इलाके में तलाश अभियान के दौरान एक विशिष्ट पैरा यूनिट के दोनों कमांडो लापता हो गए।

यह अभियान दो दिन पहले अहलान गडोले इलाके में आतंकवादियों के एक समूह के छिपे होने की सूचना के बाद शुरू किया गया था।अधिकारियों के अनुसार, दोनों सैनिक संचार संपर्क टूटने के बाद लापता हो गए। कमांडो का पता लगाने के लिए हेलिकाप्टरों को हवाई निगरानी में लगाया गया।

श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने बताया कि सोमवार रात अभियान में शामिल टीम बर्फीले तूफान में फंस गई थी। चिनार कोर ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'छह और सात अक्तूबर की दरम्यानी रात को किश्तवाड़ रेंज में अभियान चला रही टीम को दक्षिण कश्मीर के पहाड़ों में बर्फीले तूफान और बर्फबारी का सामना करना पड़ा।

तब से दो सैनिकों से संपर्क टूट गया है।' उसने बताया, 'गहन खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है।' उन्होंने बताया कि घाटी में आतंकियों की तलाश में भी सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

असम–मेघालय सीमा पर झड़प में एक की मौत

के तपत गांव के लोगों ने विरोध किया और उनके बीच हाथापाई हुई। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय मेघालय के लापांगप गांव और असम के तपत गांव के निवासियों के बीच कई बार झगड़ा हुआ।

मेघालय के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस झड़प में कार्बी समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई।' मृतक की पहचान असम के तपत गांव निवासी 48 वर्षीय ओरिवेल तिमुंग के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। घायलों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसांग ने कहा कि मेघालय सरकार ने बृहस्पतिवार शाम को पश्चिमी जयंतिया हिल्स के लापांगप गांव में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही हिंसा को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। असम और मेघालय के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा पर 12 क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद है। लापंगाप, मेघालय–असम सीमा पर शेष छह विवादित क्षेत्रों में से एक है, जिनका समाधान होना बाकी है। दोनों राज्य सरकारों ने इससे पहले मार्च 2022 में नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर मतभेद के 12 क्षेत्रों में से छह को सुलझा लिया था।

मृतक की पहचान असम के तपत गांव निवासी 48 वर्षीय ओरिवेल तिमुंग के रूप में हुई है।

खालिस्तानी उग्रवादियों पर करें कार्रवाई, कट्टरपंथ की जगह नहीं

में एक यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुआ था।' भारत, ब्रिटिश धरती पर खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर ब्रिटेन के समक्ष अपनी चिंताओं से अवगत कराता रहा है। ब्रिटेन में हुए आव्रजन विरोधी प्रदर्शनों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर, मिसरी ने कहा, 'ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान ब्रिटिश अधिकारियों को करना होगा।

ये ब्रिटेन के अंदर की स्थितियों का परिणाम हैं, लेकिन जहां तक अवैध आव्रजन का सवाल है, यह दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहा है। आज भी नेताओं के बीच इस पर चर्चा हुई।' इन प्रदर्शनों में भारतीयों को भी निशाना बनाया गया था। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अवैध आव्रजन का समर्थन नहीं करता है। इसके लिए भारत प्रतिबद्ध है।

निर्धारित मार्ग पर नहीं चली वंदे भारत

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (ब्यूरो)।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा पांच और छह अक्तूबर को साबरमती और गुरुग्राम के बीच दो एकतरफा वंदे भारत सुपरफास्ट विशेष ट्रेन का दोनों ही अवसरों पर निर्धारित मार्ग पर संचालन नहीं किया जा सका, क्योंकि ट्रेनसेट अधिसूचित मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं थे।

अहमदाबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश से जब इस पर प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पश्चिम रेलवे ने चार अक्तूबर को ट्रेन संख्या 09401–साबरमती से गुड़गांव के बीच एकतरफा वंदे भारत सुपरफास्ट विशेष ट्रेन– को केवल दो दिनों के लिए संचालित करने की अधिसूचना जारी की थी। साबरमती से गुड़गांव (हरियाणा) तक संचालित इस ट्रेन के लिए मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़, अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी में ठहराव निर्धारित किए गए थे।

खुशखबर : सीएम योगी ने गोरखपुर में 160 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी

दीपावली से पहले मिला अनमोल उपहार गरीबों का अपने घर का सपना साकार

हाई-राइज बिल्डिंग में बनाए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गोरखपुर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। पाम पैराडाइज, देवरिया बाईपास स्थित हाई-राइज बिल्डिंग में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां भेंट कीं। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 80 निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं। साथ ही, गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम ने पौधारोपण भी किया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। दिवाली पर स्वदेशी अपनाओ को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी ने स्वदेशी मेले में रविकिशन की विदेशी घड़ी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी बोलने से कुछ नहीं होगा। इसे अपनाना भी होगा। सीएम ने सांसद रविकिशन को बुलाकर अपने पड़ोस कुर्सी पर बैठाया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हर परिवार की एक तमन्ना होती है कि उसका अपना एक घर हो, सर ढकने को छत मिले। आज 160 परिवारों को यह दीपावली का शुभ उपहार मिल रहा है। कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में यह उपलब्धि और भी खास है। उन्होंने कहा कि एक परिवार में औसतन 5-6 सदस्य होने पर करीब 700-800 लोग सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के लिए केवल आवास ही नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना होती है।

आवासीय समितियां गठित हों : उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों को चाहिए कि हाई-राइज़ बिल्डिंग के रखरखाव के लिए आवासीय समितियां गठित हों, जिससे लिफ्ट और अन्य व्यवस्थाओं का नियमित मेंटेनेंस हो सके।

उन्होंने पूर्व योजनाओं गोरख एंक्लेव, राप्ती नगर और पत्रकारपुरम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर तबके-गरीब, स्ट्रीट वेंडर, श्रमिक, पत्रकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक और व्यापारियों के लिए भी समय-समय पर विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले गोरखपुर में गरीबों को अनमोल उपहार सौंपा। कार्यक्रम में गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे।

विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता

सीएम योगी ने कहा कि आवास वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। जीडीए की हाउसिंग स्कीम में 40 विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई। शेष 120 परिवारों का चयन लॉटरी से हुआ। 9,000 से अधिक आवेदनों में से ये सौभाग्यशाली हैं। विकास प्राधिकरण को चाहिए कि बाकी जरूरतमंदों के लिए आवास प्रक्रिया तेज करे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स 35 वर्ग मीटर के हैं, जिनकी बाजार कीमत 13-15 लाख रुपए है, लेकिन सब्सिडी से मात्र 5.40 लाख रुपए में उपलब्ध हैं। एलआईजी फ्लैट्स 41 वर्ग मीटर के हैं, बाजार मूल्य 19-20 लाख के मुकाबले 10.80 लाख रुपये में। उन्होंने कहा कि जब सरकार और जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे तो गरीबों को अपना घर मिलने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकेशन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस आवास के पास रामगढ़ ताल, जू और खोराबार के बेहतरीन स्थान हैं। यहीं पर कुछ दूरी पर सांसद रवि किशन का आवास भी है। हाई-राइज बिल्डिंग में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं।

जल्द आगे बढ़ेगी खोराबार स्कीम

सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर 4 करोड़ गरीबों को फ्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख से अधिक गरीबों को आवास मिल चुके हैं। अच्छी नियत से अच्छे कार्य होते हैं। जनता अच्छी सरकार चुनती है, तो विकास गरीब तक पहुंचता है। सीएम योगी ने कहा कि खोराबार स्कीम जल्द आगे बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि पिछले वर्ष प्रयागराज में माफियाओं से कब्जाई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनाए गए थे। इसी तरह लखनऊ में भी कब्जाई जमीन को मुक्त कर गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं की हवेलियों की जगह गरीबों के लिए मकान खड़े होंगे।

बिहार चुनाव

एनडीए सरकार की विदाई तय : राजपूत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

लखनऊ. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है, लेकिन एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। एनडीए नेताओं का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे। वहीं, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि सभी चीजें अंतिम रूप ले चुकी हैं। एनडीए पर तंज कसते हुए उन्होंने एनडीए को बिखरा हुआ कुनबा और भ्रष्टाचार का तंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता की सेवा नहीं करना चाहती।

जल्द ही बिखर जाएगी जनसुराज पार्टी : कांग्रेस नेता ने जनसुराज पार्टी को तकनीकी जमात और व्यापारी प्रकार का राजनीतिक संगठन बताते हुए कहा कि यह जल्द ही बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी मार्केटिंग करने वालों का गठजोड़ है, जिस पर अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता ने उन्हें समाजवाद का पुरोधा बताते हुए नमन किया।

दक्ष एवं पारदर्शी पुलिसिंग के मॉडल को दर्शाती है सफलता

मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड समीक्षा में टॉप रही गौतमबुद्धनगर पुलिस

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

गौतमबुद्धनगर. कानून व्यवस्था और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिणाम एक बार फिर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री दर्पण डैशबोर्ड की सितंबर समीक्षा रिपोर्ट में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेटों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रदेश के सभी जनपदों की श्रेणी में इसे द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। यह सफलता पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में दक्ष एवं पारदर्शी पुलिसिंग के मॉडल को दर्शाती है।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस उपलब्धि पर पुलिस टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह रैंकिंग आमजन के विश्वास और पुलिस-जन सहयोग का परिणाम है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ कार्य करते हुए गौतमबुद्धनगर को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।

फाइल फोटो

51 बिंदुओं पर मूल्यांकन

डैशबोर्ड समीक्षा में कुल 51 बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया, जिनमें 112 पीआरवी रिस्पांस टाइम, अग्नि सुरक्षा एनओसी जारी करने की गति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े गंभीर अपराधों (हत्या/बलात्कार) पर कार्यवाही, आग से हुए नुकसानों का आंकलन, आबकारी एवं एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, गुंडा एवं गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी, 1090 पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, कर्मचारी, किराएदार एवं घरेलू सहायता सत्यापन, चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया, लंबित विवेचनाओं में कमी, पॉक्सो एक्ट में प्रभावी कार्यवाही तथा जनसुनवाई एवं सीसीटीएनएस संबंधित शिकायतों के समाधान जैसे महत्वपूर्ण मानक शामिल थे।

'ए श्रेणी की रैंकिंग'

इन बिंदुओं पर त्वरित, प्रभावी और सतत अभियान चलाकर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 'ए श्रेणी की रैंकिंग' प्राप्त की। यह उपलब्धि पुलिस बल के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मी की मेहनत, सतर्कता और जनसहभागिता आधारित कार्यशैली को दर्शाती है।

आजम खान पर कटाक्ष

चाहे कोई पहचानें या नहीं, हमने तो दिल से दी थी दुआ : नदवी

रामपुर@पत्रिका. रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सपा नेता आजम खां के उस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने न पहचानने की बात कही थी। नदवी ने कहा कि जिले की 20 लाख आबादी का नेतृत्व करने वाले सांसद को अगर कोई नहीं पहचानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान या शख्सियत के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और जीत हासिल की गई।

नदवी के मीडिया प्रभारी ने उनके बयान की पुष्टि की है। नदवी ने कहा कि पहले भी रामपुर से कई सांसद रहे हैं। उन्हें जनता की नुमाइंदगी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी पूर्वज रामपुर में दफन हैं और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उन्हें अपना नेता माना है। नदवी ने कहा कि उन्होंने आजम के लिए जेल से रिहाई की दुआ की थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम ने अपने ही पार्टी के सांसद को पहचानने से इनकार किया।

कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने 5वीं बार सरकार बनाने की प्रतिबद्धता जताई

लखनऊ@पत्रिका. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पांचवीं बार सरकार बनाने की प्रतिबद्धता दिखाकर विपक्षी दलों को कड़ा संदेश दिया।

वीआईपी रोड पर बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित 'कांशीराम स्मारक स्थल' में हुए इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लाखों कार्यकर्ता, समर्थक और आम लोग शामिल हुए।

मायावती ने एक्स हैंडल पर कहा कि इस आयोजन में युवाओं और महिलाओं की भीड़ ने उत्साह दिखाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विपक्ष के दुष्प्रचार और हथकंडों से सावधान रहने की अपील की। मायावती ने कहा, "बहुजन समाज अपने वोटों की ताकत से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।" उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के मिशन को तन, मन, धन से पूरा करने का आह्वान किया।

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती

कांशीराम को श्रद्धांजलि

बीएसपी कार्यकर्ताओं ने कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की और मायावती के नेतृत्व में अगले चुनाव में जीत का संकल्प लिया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज का जोश विपक्षी दलों की नींद उड़ा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मिशन को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार जताया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर कोने से आए लाखों लोगों को सुरक्षित लाने-ले जाने में पार्टी यूनिट ने बेहतरीन काम किया।

नदवी-आजम के बीच नहीं कोई कटुता : आशुतोष

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

लखनऊ. रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और वरिष्ठ नेता आजम खान के बीच खींचतान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से चुने हुए सांसद हैं और आजम खान रामपुर में समाजवादी पार्टी की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के बीच कोई कटुता नहीं है। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी आजम खान के घर से लेकर मोहिबुल्लाह नदवी के संसदीय दफ्तर तक एकजुट है। हम फिर से वहां साइकिल का निशान आगे बढ़ाकर जीतेंगे।"

आशुतोष वर्मा का यह बयान उस समय आया है, जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात के बाद रामपुर में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह ने जोर पकड़ा है। अखिलेश यादव के दौरे के बीच अपने ही संसदीय क्षेत्र में कथित तौर पर रोके जाने पर रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी नाराज हैं। मोहिबुल्लाह नदवी ने बयान में कहा कि उन्हें रामपुर आने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका यह इशारा आजम खान की तरफ था। नदवी ने यह भी कहा है कि उनकी सात पुश्तों की कब्रें रामपुर में हैं, जबकि आजम खान के दादा बिजनौर से आए थे।

मुलायम की पुण्यतिथि | **संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प**

पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे : अखिलेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

इटावा. सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को सैफई स्थित समाधि स्थल पर पूरा कुनबा मौजूद रहा। सभी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी नेताजी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संविधान की रक्षा के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। समाजवादी संविधान को 'संजीवनी' कहते हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम, पीडीए, एक हैं। हम पीडीए के सम्मान और गरिमा के लिए लड़ेंगे।

सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर किया संघर्ष : सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी का पूरा संघर्ष दबे, पिछड़े, शोषित, वंचित, किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए रहा। उनको सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर संघर्ष किया। हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। नेताजी ने बहुत सारे फैसले लिए, जिनकी वजह से समाज में सम्मान और बदलाव दिखाई देता है। हमारे फौजी, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, मुख्य रूप से समाजवाद और सेक्युलरिज्म को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इस देश में हम सब मिलकर पीडीए सरकार बनाकर पीडीए समाज को हक और सम्मान दिलाएंगे।

इससे पहले सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता भी नहीं जानते थे, उन्हें सांसद बना दिया। जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे, उन्हें विधायक बनाकर भेजा। 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेकेंगे।

गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव समेत पूरा यादव कुनबा सैफई में मौजूद रहा है। इस मौके पर मंच पर शिवपाल सिंह, धर्मेंद्र और डिंपल यादव समेत परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे।

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सैफई पहुंचे अखिलेश।

संविधान को खत्म करने की साजिश

अखिलेश ने कहा कि सरकार संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन हम उन सभी ताकतों को नष्ट कर सामाजिक न्याय को स्थापित करेंगे। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। इसके लिए सरकार कोई न कोई षड्यंत्र कर रही है। वह लोग आरक्षण छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे लोगों को हम हमेशा के लिए हराएंगे। नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया और समाजवाद को बढ़ाया। उस पर चलकर उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव : चुनाव आयोग का फैसला

ईपिक नहीं है तो 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों के सहारे कर सकेंगे मतदान

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. चुनाव आयोग ने वैसे मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) नहीं है, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बयान जारी कर दिया है।

चुनाव आयोग की ओर से मान्य वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड शामिल है।

'पर्दानशीं' मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है, केवल पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये, विशेषकर 'पर्दानशीं' (बुर्का या पर्दा करने वाली) महिलाओं के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। महिला मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुये उनकी पहचान की जाएगी। आयोग के अनुसार, बिहार में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को ईपिक कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि नये मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ईपिक कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए।

121 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी

पटना. बिहार विधानसभा की 243 में से प्रथम चरण में 121 सीट पर 06 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, बिहार की 121 विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी और 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण में राज्य के जिन 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है उनमें आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर (सुरक्षित), मधेपुरा, सोनबर्षा (सुरक्षित), सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, कुशेश्वर अस्थान (सुरक्षित), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (सुरक्षित), सकरा (सुरक्षित), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट भोरे (सुरक्षित), हथुआ, सिवान, जीरादेई, दरौली (सुरक्षित), रघुनाथपुर, दरौंधा, बड़हरिया, गोरियाकोठी, महराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (सुरक्षित), अमनौर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजा पाकड़ (सुरक्षित), राघोपुर, महनार, पातेपुर (सुरक्षित), कल्याणपुर (सुरक्षित), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा (सुरक्षित), हसनपुर, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (सुरक्षित), अलौली (सुरक्षित), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर (सुरक्षित), इस्लामपुर, हिलसा, नालन्दा, हरनौत, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी (सुरक्षित), मसौढ़ी (सुरक्षित), पालीगंज, बिक्रम, सन्देश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (सुरक्षित), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराँव और राजपुर (सुरक्षित) शामिल है।

दो अपराधी घायल, हथियारों की बड़ी बरामदगी

रांची के रातू थाना क्षेत्र में पुलिस और दुबे गैंग के बीच मुठभेड़

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रांची. झारखंड में रांची के रातू थाना क्षेत्र के खलारी रोड पर शुक्रवार सुबह पुलिस और राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो कुख्यात अपराधी घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद जैसे ही इलाके में सर्च अभियान चलाया, वहां भारी मात्रा में हथियार सहित कारतूस भी बरामद किए हैं।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि ठाकुर गांव, खलारी और रातू थाना क्षेत्र की सीमा पर अपराधियों के होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौका-ए-वारदात पर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने पहुंच कर तलाशी शुरू की, वहां मौजूद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी उसी वक्त जवाबी कार्रवाई की इसमें दो अपराधियों को गोली लगी। दोनों घायल अपराधी साजन अंसारी और अमित गुप्ता बताए जा रहे हैं। इन दोनों अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रांची ग्रामीण एसपी प्रवीन पुष्कर ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके गैंग की अन्य जानकारी मिल सके और बाकी अपराधियों को पकड़ा जा सके। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में व्यापक सर्च अभियान चलाकर घटनास्थल में 8 पिस्टल और दर्जनों कारतूस बरामद किए हैं।

रांची के अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव सस्पेंड

रांची@पत्रिका. झारखंड में रांची के अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को जोनल आईजी मनोज कौशिक ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उस गंभीर मामले के बाद की गई है, जिसमें एक युवक को थाना की हाजत में बंद करके मारपीट करने का आरोप लगा था।

पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि इससे पहले इस मामले में एसएसपी ने एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। वहीं, इस मामले को और गंभीरता से देखते हुए जोनल आईजी को थाना प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट की जांच के बाद जोनल आईजी मनोज कौशिक ने थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी नागरिक के साथ अनुचित व्यवहार न हो।

गंदगी रोकने के लिए रेलवे ने लगाई पाबंदी

पटना जंक्शन पर अब नहीं बिकेगा केला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

पटना. रेलवे ने पटना जंक्शन परिसर में केले की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। रेल प्रशासन का तर्क है कि छिलके वाले फलों, खासकर केले से प्लेटफार्म और स्टेशन परिसर में गंदगी फैल रही थी, जिससे स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो रहा था।

रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब जंक्शन परिसर में केवल 12 निर्धारित फलों की ही बिक्री की अनुमति होगी, जिनमें सभी या तो बिना छिलके के खाने योग्य हैं या फिर छिलके से गंदगी फैलने की संभावना कम होती है। जिन 12 फलों की बिक्री की अनुमति दी गयी है उनमें सेब, अंगूर, ककड़ी, अमरूद, खीरा, अनार, अनानास, खजूर, पपीता (कटा हुआ और साबुत), संतरा, आम और पपीता साबुत शामिल हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन परिसर की साफ-सफाई को लेकर यह कदम उठाया गया है। छिलके वाले फल, विशेष रूप से केला, प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने का प्रमुख कारण बन रहा था, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही थी और स्वच्छ भारत मिशन के मानकों पर भी असर पड़ रहा था।

नियम तोड़े तो विक्रेता पर कार्रवाइ

रेलवे ने फल विक्रेताओं को नियंत्रित दामों की सूची और फल बेचने के स्पष्ट दिशा- निर्देश सौंप दिये हैं। यदि कोई विक्रेता तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिये लिया गया है। साथ ही यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग करें।

जदयू के वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा राजद में शामिल

पटना@पत्रिका. बिहार में पूर्णिया के पूर्व सांसद और जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए। कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर उनकी उपस्थिति में राजद की सदस्यता ग्रहण की।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक : एफ-2() सा.प्र. / मदसविवि/2025/ दिनांक: 09.10.2025

ई-निविदा सूचना सं. 58 व 59

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में निम्नानुसार कार्य /सेवाओं हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मो/ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन-लाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :

SN	Work Description	E.Bid.	UBN No.
1	विश्वविद्यालय स्थित समस्त भवनों एवं सम्पूर्ण परिसर आदि की साफ-सफाई का कार्य दो वर्ष हेतु ठेके पर दिए जाने बाबत्	58	MDU2526WSOB00012
2.	मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि उपलब्ध कराने बाबत्	59	MDU2526SLOB00011

निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वैब साईट www.mdsuajmer.ac.in तथा राज्य सरकार की वैब साईट sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति सराहनीय

महिलाएं आज के दौर में जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त बन रही हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त करने के पिछले सालों में व्यापक प्रयास भी हुए हैं। जाहिर है बदलाव का माध्यम शिक्षा बनी है और बेहतर शिक्षा से ही महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। कामकाजी महिलाएं न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही हैं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ देश की आर्थिक समृद्धि में भी सतत योगदान दे रही हैं। अब समय आ गया है कि कामकाज-कार्यालय की व्यवस्थाओं के संबंध में नीतियां बनाते समय पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिलाओं की अनुकूलता का भी ध्यान रखा जाए। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार की 'मासिक धर्म अवकाश नीति-2025' एक सराहनीय कदम है।

कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिहाज से भी पिछले सालों में कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने का काम भी हुआ है। फिर भी कामकाजी महिलाओं के हित से जुड़े कई मामलों में अभी ठोस काम होना बाकी है। इनमें महिलाओं को उनके श्रम का उचित मूल्य मिलना तो शामिल है ही, कार्यस्थल पर बच्चों के लिए क्रेच व घर से कार्यस्थल तक सुगम व सुरक्षित आवागमन का बंदोबस्त भी शामिल है।

यह भी एक तथ्य है कि सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में इस दिशा में सुधारात्मक प्रयास भी हो रहे हैं। कामकाजी महिलाओं से जुड़ा एक अहम मुद्दा उन्हें मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने का भी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक आदर्श नीति बनाने के निर्देश पहले ही दे रखे हैं लेकिन गिने-चुने राज्यों में सरकारों व कुछ निजी कंपनियों ने ही अपने यहां कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अवकाश के अलग-अलग प्रावधान किए हैं। मासिक धर्म अवकाश कामकाजी महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बड़ी राहत कहा जा सकता है। कर्नाटक में हर माह सरकारी दफ्तरों से लेकर आइटी कंपनियों व फैक्ट्रियों तक में महिलाओं को एक दिन की पेड लीव यानी सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। वस्तुतः पीड़ा के इस दौर में अवकाश का प्रावधान करना निश्चित ही ऐसी महिलाओं के अधिकार का विषय होना चाहिए। हालांकि इससे पूर्व बिहार, ओडिशा व केरल सरीखे गिने चुने राज्यों व कुछ निजी कंपनियों में ही अवकाश का प्रावधान किया गया है। जबकि यह मांग देश के अन्य हिस्सों से भी लगातार उठती रही है।

नियोक्ताओं की ओर से महिलाओं को दी जाने वाली इस तरह की सुविधाएं एक संवेदनशील कदम हैं। अध्ययन बताते हैं कि मासिक धर्म के दौरान कामकाजी महिलाओं को अवकाश मिलने से उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। अब समय है कि बाकी राज्य और केंद्र भी इस दिशा में कोई न कोई कदम अवश्य उठाए।

लक्ष्मी पृथ्वी है-पदार्थ है, आकृति देती है। उसका रज सृष्टि को त्रिगुणी बना देता है। अर्थवाक्, जड़ सम्पदा लक्ष्मी-विष्णु (सोम) की सृष्टि है। ब्रह्मा की रजोगुणी सृष्टि में शब्द वाक् स्पष्ट रहती है। शिव के संहार में काली का तम साथ जुड़ा होता है। शिव श्वेत हैं।

मानवता का निर्माण

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

स्त्रीः देह से आगे
विषय विवेचन
जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में ***गुलाब कोठारी*** के संबोधन का वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

ब्रह्म और माया का प्रथम अवतार हुआ अव्यय पुरुष। उसका हृदय हुआ अक्षर पुरुष। अव्यय वेदत्रयी रूप-ऋक्-यजुः-साम हैं। अक्षर रूप हृदय में प्राणरूप ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र रहते हैं। इन तीनों को युगल रूप में माया ने ही पैदा किया था। दुर्गा सप्तशती में वर्णन मिलता है कि त्रिगुणमयी महालक्ष्मी ही सबका आदिकारण है। इस जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा महामाया, महाकाली, कालरात्रि, दुरत्यया आदि अभिधानों से सुशोभित देवी का रूप धारण किया। सत्वगुण के द्वारा महालक्ष्मी ने सरस्वती महाविद्या, भारती, कामधेनु आदि नामों वाली देवी का रूप धारण किया। रजोगुण रूप उपाधि के द्वारा महालक्ष्मी ने गौरी, श्री, मेधा आदि नामों वाली देवी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के साथ लक्ष्मी-हिरण्यमयी, विष्णु के साथ गौरी, इन्द्र (शिव) के साथ सरस्वती को क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने उत्पन्न किया। विष्णु-ब्रह्मा-शिव क्रमशः सत्व, रज, तम के स्वामी हैं। माया ने युगल रूप में ब्रह्मा-सरस्वती, विष्णु-लक्ष्मी, शिव-गौरी को संकल्पित करा दिया–

ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम्।
रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्।।
(दुर्गा सप्तशती प्राधानिक रहस्य/26)

ब्रह्मा बाहर (पुरुष रूप) रजोगुणी, उनका भीतर का स्त्रैण भाग तमोगुणी हुआ। सरस्वती बाहर तमोगुणी-भीतर रजोगुणी (वाक्) हुई। स्त्री-पुरुष के भीतरी भाग ही तो दोनों के पूरक बनते हैं। ब्रह्मा जहां माया पुत्र हैं, वहीं सरस्वती शिव की भगिनी है शिव उनके पीहर (पितृगृह) के प्रतिनिधि हैं। विवाह पश्चात् दोनों के आत्मा के गुण बदल जाते हैं। विष्णु सत्वगुणी तो हैं, किन्तु लक्ष्मी रजोगुणी है। कार्य तो विष्णु के लिए रजोगुणी होते हुए भी सत्व रूप ही करेगी। किन्तु विष्णु के सत्व के साथ ही शिव का तमस भी जुड़ जाएगा। विष्णु के शुक्र में सत्व के साथ में तम का प्रभाव भी होगा। लक्ष्मी पृथ्वी है–पदार्थ है, आकृति देती है। उसका रज सृष्टि को त्रिगुणी बना देता है। अर्थवाक्, जड़ सम्पदा लक्ष्मी-विष्णु (सोम) की सृष्टि है। ब्रह्मा की रजोगुणी सृष्टि में शब्द वाक् स्पष्ट रहती है। शिव के संहार में काली का तम साथ जुड़ा होता है। शिव श्वेत हैं।

भारतीय विवाह परम्परा पशुओं की भांति शरीरों का मेल नहीं है। यह प्रकृति आधारित भी है और व्यक्ति आधारित भी (सात पीढ़ियों का सूत्र)। इसमें स्त्री-पुरुष के अलावा दोनों पक्षों के पितरों के प्राण भी नई सन्तान में पहुंचते हैं। तब पुरुष शरीर में स्त्रैण भाग पर ससुराल का प्रभाव रहता है। स्त्री शरीर में भी पति के परिवार एवं पूर्वजों का प्रभाव स्पष्ट है। नई विवाह संस्था में स्त्री के परिवार का अंश नई सन्तान तक नहीं पहुंचता। स्त्री के मूल प्राण उसके पिता के पास ही रह जाते हैं। तब सन्तान का आकर्षण दोनों परिवारों में बंट जाता है। स्त्री भी दोनों परिवारों के मध्य जीती है।

विवाह के बाद पुरुष के स्त्रैण भाव का पोषण स्त्री के सोम से होता है। और स्त्री के पौरुष को पुरुष सींचता है। आज नई व्यवस्था में स्त्री-पुरुष दोनों का स्वरूप नहीं बदलता, दोनों अपने-अपने भागों का पोषण जीवनसाथी के अर्द्धांग में नहीं करते हैं। परस्पर विवाह सूत्र की पकड़ ढीली रह जाती है। ऊपर से यदि स्त्री अति बुद्धिमान हुई अथवा अति महत्वाकांक्षी हुई तो दोनों पुरुष रूप लम्बी यात्रा साथ-साथ नहीं कर पाएंगे। आत्मभाव पैदा होना कठिन है। अथवा स्त्री दृढ़ संकल्पवान हो तो लम्बा संघर्ष करके अपना स्थूल स्थान तो सम्मानजनक बना सकती है, किन्तु उसके सात पीढ़ी के अंश सन्तान को प्राप्त नहीं हो सकते।

हमारा दर्शन कर्म-कर्मफल-पुनर्जन्म पर आधारित है। इसका एक ही अर्थ है कि हम जैसा करते हैं, वैसा ही लौटकर हमारे पास आता है। आज चारों ओर जैसा अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा अनाचार फैला हुआ है, उसके कारण भी हम ही हैं। मेरा सुख, मेरा दुःख, दोनों मेरे कारण ही हैं। समष्टि रूप में समाज का स्वरूप भी मेरे कारण ही बनता है। व्यक्ति से ही समाज बनता है। अतः समाज को भला-बुरा कहते समय स्वयं को प्रश्न कर लेना चाहिए। शिक्षा ने एक प्रकार का अपेक्षा भाव हर व्यक्ति के मन में जगा दिया, किन्तु व्यक्ति को उस के लायक नहीं बनाया। सरकार निश्चेष्ट है- उच्च शिक्षा भारतीय मूल्यों की चर्चा ही नहीं करती। शिक्षा में व्यक्ति की चर्चा ही सुनाई नहीं देती। विषय प्रधान होकर रह गई है।

शिक्षा में विषय की प्रवीणता है, व्यक्तित्व का ह्रास है। अध्यात्म के चार अंगों में से शिक्षा दो अंगों का ही पोषण करती है- शरीर और बुद्धि का। शेष दो अंगों की भूमिका अल्पतम रह जाती है–मन और आत्मा की। एक अच्छे व्यक्ति को असंतुलित कर देती है। उच्च शिक्षा-अधिक असंतुलन। यह एक भाग है। दूसरा भाग है–समानता की अवधारणा का, जिसका अर्थ ही शायद स्पष्ट नहीं है। पश्चिम की अंधी नकल मात्र है। पश्चिम में समाज व्यवस्था नहीं है। हर व्यक्ति-स्त्री हो या पुरुष, एकल इकाई के रूप में रहता/रहती है। कानून भी एकल को ही सम्बोधित करते हैं। दाम्पत्य भाव में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपनी निश्चित पहचान है। दोनों का साथ रहना या अलग होना सामान्य जीवन शैली का अंग है। यही कारण है कि वहां लिव-इन सामान्य बात है। सन्तान न होना भी इसी अवधारणा का परिणाम है।

भारतीय दर्शन में यह स्वच्छन्दाचार कहलाता है। मर्यादा की परिधि ही आकृति का निर्माण करती है। आकृति ही सत्य भाव है। निराकार का स्वयं का अस्तित्व नहीं होता। पश्चिम की नकल में शिक्षित भारतीय स्त्री भी निराकार जीने को उतावली है। हवा-पानी की तरह। यही जीवन के उजाड़ की शुरुआत है। नकल में व्यक्ति स्वयं को देखना भूल जाता है, सामने वाले पर आंख रहती है। हमको प्रकृति पैदा करती है। प्रकृति की सच्चाई कुछ और ही है।

आधुनिक शिक्षा का बड़ा अभिशाप यह है कि इसमें अधिदेव की शिक्षा नहीं है। भारतीय जीवन पद्धति तीन धरातलों में प्रतिष्ठित है–आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। पश्चिम में भी अधिदेव की शिक्षा नहीं है जो कि प्राणों का क्षेत्र है। हम तो आत्मा को प्राण रूप मानते हैं। सारे देवी-देवता, असुर आदि प्राण सृष्टि के ही अंग हैं। अधिभूत में भौतिक जगत है और अध्यात्म में शरीर संस्था है। सूक्ष्म शरीर ही स्थूल और कारण शरीर के बीच का सेतु है। इसके अभाव में जीवन स्वतंत्र रूप से दो खण्डों में बंट जाता है। दोनों ही खण्डों में व्यक्ति अलग-अलग जीता है। तब पूर्णता कैसे संभव है।

अधिदेव के अभाव में शरीर पिण्डमात्र रह जाता है, जैसा मेडिकल साइन्स में देखा जा सकता है। इसका प्रभाव आत्मा (कारण शरीर) तक पहुंच ही नहीं पाता। अधिभूत केवल भोग की वस्तु बनकर रह जाता है। अधिदेव रहित जीवन पदार्थ रूप में भोग की वस्तु बन जाता है। संपूर्ण पश्चिम-विकसित देश- इसका प्रमाण है। दुर्भाग्य से हमारे देश की शिक्षा उसी दिशा में ले जा रही है। वैसा ही हमारा विकास होगा। विवाह शरीर मात्र की आवश्यकता बनती जाएगी। जमीन की तरह शरीर भी मुद्रा का रूप लेता जा रहा है। आत्मा सुप्त होने से कचोटता नहीं है। संवेदनहीन जीवन में प्रेम की धड़कनें शान्त होती जा रही है। क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी-स्त्री-ने मानवता का निर्माण बन्द कर दिया है। **-क्रमशः**

gulabkothari@epatrika.com

बुक इनसाइट

आर्टिकुलेट

आर्टिकुलेट ए डीफ मेमॉयर ऑफ वॉइस रेचल कोल्ब की लिखी गई एक भावनात्मक और प्रेरणादायक आत्मकथा है। यह किताब बधिर लेखिका रेचल कोल्ब की जिंदगी की कहानी है, जो उनकी आवाज और पहचान की खोज को दर्शाती है। रेचल कोल्ब बचपन से ही बधिर हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सीमाओं को रुकावट नहीं बनने दिया।

किताब में वे बताती हैं कि कैसे उन्होंने बोलना, दूसरों को समझना और अपनी पहचान बनाना सीखा। यह कहानी उन संघर्षों की है जो हर उस व्यक्ति के अंदर चलती है जो समाज में अलग महसूस करता है लेकिन फिर भी अपनी राह बनाता है। कहानी का हर अध्याय भाषा, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति की ताकत को उजागर करता है। रेचल बताती हैं कि 'सुनना' सिर्फ कानों का नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने का अनुभव है। उनकी कहानी में दर्द के साथ-साथ हिम्मत भी झलकती है।

आर्ट एंड कल्चर

अमिताभः एक नाम जो वक्त से बड़ा है

कुछ ही दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हर पल जीवन का, कुछ न कुछ सिखाता है, क्षमता कम न हो सीखने की, समय यही सिखाता है'। 83 की उम्र में सीखने की यह जिद ही शायद अमिताभ को अमिताभ बनाती है। वर्षों से सोशल मीडिया का सबसे अनुशासित उपयोग करने वाले सेलिब्रिटी के रूप में अमिताभ देखे जा सकते हैं।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

आज भी अमिताभ वह हर नया जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, जिसके लिए हिम्मत जुटाने में कोई भी युवा वर्षों गुजार दे। टेलीविजन पर अमिताभ जिस स्नेहिल अभिभावक की तरह अब दिखते हैं भारतीय दर्शक उससे सीधे कनेक्ट करते हैं। शायद यही कारण है कि हरेक अनिवार्य अभियान के लिए अमिताभ अनिवार्य समझे जाते हैं, चाहे वह पल्स पोलियो की बात हो या स्वच्छता अभियान की या फिर गुजरात टूरिज्म या महाराष्ट्र हॉर्टिकल्चर के ब्रांड एम्बेसडर बनने की। आप इसे अमिताभ की सामाजिक भूमिका के रूप में स्वीकार करें या अभिनय के प्रयोग के रूप में अमिताभ का महत्त्व कहीं भी उन्नीस नहीं होता। वास्तव में अमिताभ के लिए सफलता की राह आसान नहीं रही। काम की तलाश में उन्हें भटकना ही नहीं पड़ा था, जलालत भी झेलनी पड़ी थी। जाहिर है अमिताभ के लिए सफलता कीमती थी, उनके कॅरियर में आए दो दौर की ढलान यात्रा ने सफलता को उनके लिए और भी कीमती बना दिया था।

अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म के. ए. अब्बास की 'सात हिन्दुस्तानी' थी, संदेह नहीं कि यह फिल्म उन्हें अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी के वजह से मिली थी। उन्हें इसके लिए नवोदित अभिनेता का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला था लेकिन उन्हें पहचान मिली हृषिकेश मुखर्जी की संवेदनशील फिल्म 'आनन्द' से, तयशुदा मौत का जीवंतता से मुकाबला करते राजेश खन्ना की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की संक्षिप्त उपस्थिति यह विश्वास दिलाने में सक्षम थी कि हिन्दी सिनेमा को एक बेहतर अभिनेता मिल सकता है। अभिमान, नमक हराम, बेमिसाल, मिली, चुपके-चुपके, अलाप, जुर्माना जैसी फिल्मों में बगैर किसी दोहराव के अमिताभ ढलते चले गए। लोग दशक के सर्वश्रेष्ठ का खिताब पाकर धन्य हो जाते हैं, अमिताभ के पास 'सदी के सर्वश्रेष्ठ' के न जाने कितने खिताब सुरक्षित होंगे। वास्तव में अमिताभ की महानता आज किसी भी विमर्श से परे है। आज जब अमिताभ 83 वर्ष के हो गए हैं तो स्वाभाविक हैं, अमिताभ को सिर्फ फिल्मों के लिए याद नही किया जा सकता। उन्होंने अपनी सक्रियता से परदे से अलग सामाजिक पारिवारिक पहचान भी बनाई है, जो शायद हमारे लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

गाजा में युद्ध विराम बीस सूत्री योजना का खाका पेश किया गया

शांति की नई पटकथाः ट्रंप की योजना या पश्चिम एशिया का भ्रम

डॉ. एन.के. सोमानी
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

पिछले दो साल से जंग की आग में झुलस रहे गाजा में शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पिछले दिनों जब अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए बीस सूत्री योजना का खाका प्रस्तुत किया, उसके बाद से पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद की जा रही थी। योजना में इजरायली बंधकों को रिहा करने, हमास को हथियार छोड़ने व गाजा के पुनर्विकास की बात कही गई थी। इजरायल इस शांति प्रस्ताव पर शुरू से ही तैयार था लेकिन हमास अभी तक किन्तु-परन्तु की स्थिति में था। उसका कहना था कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना पर विचार करके प्रतिक्रिया देगा।

अब हमास की सहमति के बाद गाजा में युद्ध समाप्त होने और बंधकों को रिहा करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बदले में इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी और इजरायल की जेलों में बंद 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास तीन-चार दिन का वक्त है वरना परिणाम दुखद होंगे।

लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ट्रंप ने अपनी योजना में गाजा की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से हमास को पूरी तरह से अलग रखने की बात कही है क्या हमास उसको स्वीकार कर सकेगा? दूसरा योजना में जिस तरह से फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर प्रस्तुत करने की परिकल्पना की जा रही है, नेतन्याहू इसके लिए राजी होंगे? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि नेतन्याहू ने कभी भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि ट्रंप की प्रस्तावित शांति योजना जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते की तरह हमास-इजरायल हथकंडों की भेंट चढ़ जाए। डॉनल्ड ट्रंप ने अरब देशों के साथ बीस सूत्री शांति प्रस्ताव साझा किया है।

शांति प्रस्ताव में इजरायल-हमास के बीच जारी संघर्ष को रोकने व पश्चिम एशियाई क्षेत्र में शांति के लिए गाजा को कट्टरपंथ और आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई है। प्रस्तावित शांति योजना के अनुसार इजरायल गाजा पर कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। प्रस्तावित शांति योजना में गाजा के पुनर्निर्माण का चरणबद्ध उल्लेख किया गया है। गाजा के पुनर्निर्माण का काम वहां के नागरिकों की इच्छानुसार जाएगा। प्रशासनिक कार्य के लिए एक गैर राजनीतिक समिति का गठन किया जाएगा। हमास और अन्य गुटों को इस समिति से दूर रखा जाएगा। समिति के कार्यों की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष स्वयं डॉनल्ड ट्रंप होंगे।

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित अन्य वैश्विक नेताओं को बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। क्षेत्र में शांति स्थापना के प्रयासों को किसी तरह से नुकसान न पहुंचे इसके लिए अमरीका अपने अरब और दूसरे अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय बल तैनात करेगा। कुल मिलाकर कहें तो प्रस्तावित शांति योजना में हमास को क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश की गई। ट्रंप की योजना फिलिस्तीन और इजरायल के लोगों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में एक बारगी तो शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से गाजा के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण और विकास से हमास को अलग रखा गया है उसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति के प्रयास सफल होंगे।

नीदरलैंड्स में विकास व प्रकृति का संतुलन
वन्यजीवों के ग्रीन ब्रिज

नीदरलैंड्स *दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण और पशु-सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है। यहां पर जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए वाइल्डलाइफ क्रॉसिंग यानी पशु-पुल, इस बात के प्रतीक हैं कि आधुनिक विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे कायम किया जा सकता है। देश में 600 से अधिक ऐसे विशेष पुल, सुरंगें और हरित मार्ग बनाए गए हैं, जो सड़कों से अलग होकर वन्यजीवों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता प्रदान करते हैं।*

आपकी बात

माता-पिता का सम्मान करें

आज के बच्चे मोबाइल में इतने उलझ गए हैं कि माता-पिता की बातों का जवाब देने लगे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे अधिक भलाई उनके माता-पिता ही सोचते हैं। उनकी आज्ञा मानना और बात सुनना हमारे संस्कारों की पहचान है। उनके हर सुझाव के पीछे हमारी भलाई छिपी होती है। उनका सम्मान करना चाहिए। **- प्रियव्रत चारण, जोधपुर**

बदलते मौसम में बरतें सावधानी

बारिश के बाद सर्दी की आहट शुरू हो गई है, ऐसे में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मच्छरों से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनें, धुआं करें और पानी जमा न होने दें। घर में सीलन और नमी से बचें। यदि मलेरिया, डेंगू या वायरल के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और लापरवाही न बरतें।- **निर्मला वशिष्ठ,** अलवर

मिलावट से सतर्क रहें

त्योहारों के समय मिलावटखोरी चरम पर रहती है। खाने-पीने से लेकर दवाओं तक में मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और खाद्य विभागों को सक्रिय होकर जांच अभियान चलाना चाहिए। **- नरेश कानूनगो,** देवास

अपराधियों को संरक्षण न मिले

गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जनता का विश्वास बहाल नहीं होगा। अपराधियों को कठोर सजा ही समाधान है। **- प्रकाश भगत,** चांदपुरा

जयप्रकाश नारायण जयंती आज उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व मतभेदों को मिटाकर जनहित के लिए काम करता है

संघर्ष वही है, जो समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ा जाए

राजेन्द्र गहलोत
सांसद, राज्यसभा
@patrika.com

जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है, भारतीय लोकतंत्र के ऐसे नायक हैं, जिन्होंने न केवल तानाशाही को ललकारा, बल्कि राजनीति को समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का हथियार बनाया। जेपी के जिक्र के बिना न तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यशगाथा पूरी होती है और न आजादी के बाद की चुनौतियों के बीच भारतीय लोकतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की। इस वर्ष, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, जेपी का स्मरण करना मेरे लिए केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरे जीवन के उन पन्नों से जुड़ा है, जब मैंने उनके विचारों को नजदीक से जाना व उनके सान्निध्य में समय बिताया।

1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान को ताक पर रखकर देश में तानाशाही थोप दी। ऐसे में जेपी एक तूफान बनकर उभरे। बिहार से उनका 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन शुरू हुआ। मैं उस समय युवा था और जेपी की पुकार ने मुझे सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। जेपी की ताकत उनकी सादगी और सिद्धांतों में थी। वे सत्ता के भूखे नहीं थे। 1977 में उनकी प्रेरणा से जनता पार्टी की जीत और भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन इस बात का सबूत था कि जनता की ताकत तानाशाही से बड़ी है। मैंने उस दौर के जश्न को देखा, जब लोग सड़कों पर नाच रहे थे, मानो देश ने नई आजादी पाई हो। जेपी ने अलग-अलग विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व मतभेदों को मिटाकर जनहित के लिए काम करता है।

बाद में, मुझे कई बार जेपी का सानिध्य भी मिला जो मेरे लिए एक अमूल्य पूंजी है। उनकी बातें आज भी मेरे जेहन में ताजा हैं। एक बार उन्होंने कहा था, सत्ता साधन है, साध्य नहीं। असली जीत समाज के कमजोर तबके की बेहतरी में है। यह बात मेरे लिए राजनीति का असली मोल समझने का सबक थी। जेपी का मानना था कि किसान, मजदूर, दलित और महिलाएं समाज की नींव हैं और उनकी प्रगति ही देश की प्रगति है। उनकी यह सोच आज की राजनीति के लिए एक आईना है। शायद इसीलिए जेपी के समाजवाद के ज्ञान पर गांधीजी ने स्वयं लिखा, जयप्रकाश कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, वे समाजवाद के आचार्य हैं और भारत में समाजवाद के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता।

आज का दौर जेपी की कमी को और गहराई से महसूस कराता है। राजनीति अब सत्ता की जंग बन गई है, जहां सिद्धांत और जनहित गौण हो गए हैं। ऐसे में जेपी का 'संपूर्ण क्रांति' का नारा केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक दर्शन है-सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा का दर्शन। जेपी की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। हमें बताती हैं कि सच्चा नेता वही है, जो जनता के दुख-दर्द को अपना समझे। उनकी 'संपूर्ण क्रांति' केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि यह समाज को बदलने का आह्वान था। उनका वाक्य, 'सच्चा संघर्ष वही है, जो समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए लड़ा जाए' किसी मंत्र से कम नहीं है।

आज का सवाल

लगातार कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले क्यों नहीं रुक पा रहे हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

प्रेरणा

हर एक कमाई जो उसके लिए की गई मेहनत के अनुरूप नहीं है, बेईमानी है। - लियो टॉल्सटॉय

संपादकीय

गाजा में शांति से दुनिया चैन की सांस ले रही है

हमास ने क्या किया, उस पर इजराइल की प्रतिक्रिया कैसी और किस मात्रा में न्यायपूर्ण होती, ये सवाल गौण हैं। आज युद्ध की विभीषिका से बचे फिलिस्तीनियों के चेहरे पर खुशी है, इजराइल के लोग भी उल्लास में हैं और दुनिया राहत की सांस ले रही है। इतना काफी है। यह ट्रम्प के दबाव के बगैर संभव न होता। इजराइल को दबाना ट्रम्प के अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। 20 बिंदुओं के समझौता-मसौदे में 19वां बिंदु फिलिस्तीनियों को आने वाले समय में स्व-शासन देने का वादा है, जिसे तेल अवीव ने मजबूरी में ही माना होगा। हमास भी आसानी से हथियार छोड़ कर शांति की प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा, यह कुछ हफ्तों पहले तक सोचना भी नामुमकिन था। पीएम मोदी ने ट्रम्प और इजराइली पीएम को धन्यवाद देते हुए इसे अनायास ही ऐतिहासिक नहीं बताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रम्प ने इजराइल-ईरान जंग में भी दबंग मध्यस्थ की भूमिका न निभाई होती तो स्थिति अकल्पनीय होती। ट्रम्प के कुछ प्रयासों को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। रूस-यूक्रेन युद्ध एक-दूसरे को अस्तित्वविहीन करने की जिद तक पहुंच गया है। अमेरिका दोनों को धमकी से लेकर पुचकारने तक सब कुछ कर रहा है। रूस को भी सोचना होगा कि इस जंग ने उसकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया है। बहरहाल, अगर अमेरिका व्यापार में नर्मी बरतता है तो मोदी-ट्रम्प भेंट सम्भव है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

धार्मिक पर्यटन में अब और अधिक व्यवस्थाएं जुटाएं

जब भीड़ तमाशा बन जाती है तो मौत को प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। चाहे राजनीतिक सभाएं हों या धार्मिक आयोजन, भीड़ एक मापदंड हो गया है। इस समय धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, पर जो तीर्थस्थान हैं, वहां का प्रबंधन अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भीड़ में बदल जाते हैं। इन धार्मिक शहरों में रहने वाले स्थानीय लोग अपने शहर की दुर्दशा देखकर दुःखी हो गए हैं। उनका वश चले तो वो पर्यटकों को रोकने में ताकत लगा देंगे। स्पेन के बार्सीलोना में ऐसी घटना घट चुकी है। वहां के नागरिक पर्यटकों को रोक रहे हैं। सिटी ऑफ मैथ्स- यानी जो अपनी गणितीय आकृतियों के लिए मशहूर है- उस बार्सीलोना के लोगों का कहना है हमारे शहर की शांति भंग हो गई, व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है- भीड़ के कारण। इसलिए भीड़-प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को चाहिए और खासतौर पर धार्मिक पर्यटन में- कि अब अधिक व्यवस्थाएं जुटाएं। वरना मौत और दुर्घटना को अपना तांडव करने के लिए इससे अच्छा मंच और कहां मिलेगा?

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • चुनाव न सिर्फ स्वतंत्र हों, बल्कि दिखें भी

चुनाव से पहले मुफ्त सौगातें क्या नैतिक रूप से सही हैं?

फ्रीबीज़

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर को तीन चुनाव आयुक्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। यह घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी। इसके एक घंटे पहले दोपहर 3 बजे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। हर महिला को 10 हजार रुपए दिए गए। इससे पहले, उसी दिन मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो के एक हिस्से का उद्घाटन भी किया।

आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले खुले हाथों से इतना पैसा बांटना क्या नैतिक तौर पर सही है? भले यह गैर-कानूनी ना हो, लेकिन कानून की भावना के विरुद्ध अवश्य है। मुझसे पूछें तो यह खुलेआम रिश्वत बांटने जैसा है। अतीत में खुद प्रधानमंत्री जनकल्याण के नाम पर रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति की निंदा कर चुके हैं। लेकिन यहां उनकी खुद की 'डबल इंजन' सरकार ऐसा कर रही है। चुनाव स्वतंत्र होने ही नहीं, बल्कि दिखने भी चाहिए। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में वोटिंग के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, बैलट से छेड़छाड़ और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आम बात थी। 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी. एन. शेषन के कार्यकाल में महत्वपूर्ण बदलाव आया। शेषन ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और शराब बांटने पर रोक लगाई। वोटर आईडी कार्ड लागू करने, चुनाव खर्च सीमित करने और संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया। इससे बूथ कैप्चरिंग और वोटिंग के दिन होने वाली हत्याओं में कमी आई। पर्यवेक्षकों की तैनाती बेहतर हुई और चुनाव अधिक विश्वसनीय होने लगे।

शेषन ने आदर्श आचार संहिता के सख्ती से पालन पर जोर दिया था। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियम-कायदे हैं। ये कानून तो नहीं हैं, लेकिन जन-आकांक्षाओं, कानूनी समर्थन और नैतिकता की धारणा से ये पोषित होते हैं। आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है। यह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रभावित कर सकने वाली किन्हीं भी नई परियोजनाओं-योजनाओं और सत्ताधारी दल व मंत्रियों द्वारा धन-वितरण को प्रतिबंधित करती है। मतदाताओं को प्रभावित करने या प्रचार की शुरुआत से पहले 'फील गुड' का माहौल बनाने जैसे कदमों से यदि किसी का इरादा साफ तौर पर चुनावी फायदा लेने का दिख रहा है तो नैतिकता भी संदेह के दायरे में आ जाती है। आचार संहिता की तारीख के आसपास ऐसा हो तो बहुत संभावना है कि इन मुफ्त की सौगातों को नीति के बजाय प्रलोभन माना जाए।

राजनीतिक निष्पक्षता के लिए समान अवसर जरूरी हैं। लेकिन चुनावों में स्वाभाविक तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी फायदे में होती है। उसके हाथ में सरकारी तंत्र, विजिबिलिटी और संसाधन होते हैं। फ्रीबीज यदि आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले दी जाएं तो यह फायदा और बढ़ जाता है। वहीं इसका जवाब देने के लिए विपक्षी दलों को समान अवसर नहीं मिल पाता। मतदाता तर्कसंगत चयन के बजाय उम्मीदवार की इस संरक्षणवादी राजनीति में फंस जाते हैं। जनता के पैसों का इस्तेमाल सियासी लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। कोई योजना वोट खरीदने की मंशा से-खासतौर पर अंतिम समय में घोषित की जाए तो इससे यह सिद्धांत कमजोर होता है कि शासन सभी के लिए होना चाहिए- महज उन लोगों के लिए नहीं, जो सत्ताधारी दल को वोट देते हैं या दे सकते हैं। इसके अलावा, अब यह धारणा भी बन गई है कि ऐसी मुफ्त की सौगातें सुशासन के लिए आवश्यक हैं। यह शासन में गंभीर कमजोरी का संकेत है, वरना सरकारों को अंत समय में ऐसे प्रलोभनों का सहारा क्यों लेना पड़े? ऐसी परंपराएं जब आम हो जाती हैं, तो वे चुनावी भ्रष्टाचार को निचले स्तर तक ले आती हैं। कभी अनुचित समझी जाने वाली चीज आज सामान्य मान ली जाए तो इससे लोकतांत्रिक संस्कृति को नुकसान होता है।

आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है। यह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली योजनाओं और सत्ताधारी दल द्वारा धन-वितरण को प्रतिबंधित करती है।

निष्कर्ष यही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मुफ्त की सौगातें बांटना नैतिक रूप से निंदनीय है। इससे ऐसा लगता है, जैसे कल्याण की धारणा को सरकार के दायित्व के स्थान पर चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। असल लोकतंत्र कानून में नहीं, बल्कि उन मानदंडों में होता है, जिन्हें हम वैधानिक और निष्पक्ष मानते हैं। सौभाग्य से, वोटर अब इस सियासी चालबाजी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अक्सर वो पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं, जो उन्हें बेहतर लगता है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मुद्दा • चुनाव आयोग बिहार में रोड-शो पर पाबंदी लगाए

और कितनी मौतों के बाद हम रोड-शो पर रोक लगाएंगे?

भगदड़

विराग गुप्ता
वकील और 'इलेक्शन ऑन द रोड्स' के लेखक

तमिलनाडु के करूर में एक रैली में भगदड़ के बाद 41 लोगों की मौत के बाद सुपर स्टार विजय के दोस्त आधव अर्जुन ने सोशल मीडिया में लिखा कि दुष्ट शासक के अधीन कानून भी दुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने श्रीलंका और नेपाल की तर्ज पर जेन-जी से क्रांति और परिवर्तन का आह्वान किया। लेकिन रोड-शो के नाम पर सड़कों पर अराजकता फैलाकर लोगों को मौत के मुंह में डालने वालों से व्यवस्था-परिवर्तन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इससे जुड़े 5 मसलों पर चर्चा जरूरी है।

1. मुद्दे को भटकाना : बेंगलुरु में आरसीबी के विजय समारोह, दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब करूर में भीड़ की भगदड़ जैसे सभी मामलों में जांच समिति, बारीक बहस और नए कानून के नाम पर मुद्दे को भटकाकर संविधान की समानता का मखौल उड़ाया जाता है। टीवीके पार्टी की रैलियों में पहले भी 3 लोगों की मौत हुई थी। अब 41 निरीह लोगों की मौत की कानूनी जवाबदेही लेने के बजाय सीबीआई जांच के नाम पर अदालतों में मुकदमों का खेल हो रहा है। भीड़ प्रबंधन के लिए एनडीएमए और बीपीआरडी की 2020 और 2025 में जारी दो गाइडलाइंस हैं। इसके बावजूद तमिलनाडु में नई एसओपी की बेतुकी मांग हो रही है। सरकारी संसाधन, पुलिस और अदालतों के दुरुपयोग के बाद लम्बित मुकदमों और जेलों में भीड़ के मर्ज पर हमारा रुदन कितना सही है?

2. रोड-शो : बाइक रैलियों और रोड-शो से बड़े पैमाने पर प्रदूषण बढ़ता है। सभास्थल पर पीने का पानी, टॉयलेट्स, पार्किंग और आपात रास्तों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए सड़कों पर रैली नहीं हो सकती। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार रोड-शो छुट्टियों के दिन होना चाहिए, जिससे आम जनता को असुविधा नहीं हो। स्कूल, अस्पताल, ब्लड-बैंक और जरूरी सुविधाओं के इलाकों में रोड-शो नहीं हो सकता। काफिले में दस से ज्यादा गाड़ियां नहीं हों और उनका पूर्व विवरण अधिकारियों को देना जरूरी है। रोड-शो के दौरान आधी सड़क में यातायात सुचारु रूप से जारी रहना चाहिए। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने और मरीजों की जान जोखिम में डालकर रोड शो करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।

3. जवाबदेही : कफ सिरप से हुई मौतों के बाद दवा फैक्ट्री और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बजाय डॉक्टरों पर दोषारोपण से मामले को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। सीवर लाइन में हो रही मौतों पर नगर निगम की जवाबदेही तय करने के बजाय ठेकेदार के खिलाफ मुकदमे से लीपापोती हो जाती है। साल 2024 में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान के नाम पर आम जनता से 12632 करोड़ वसूले गए। दूसरी तरफ सुपरस्टार विजय को बचाने के लिए गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ कमजोर धाराओं में एफआईआर भर ही दर्ज की गई है।

4. मुआवजा : एक फिल्म के लिए सैकड़ों करोड़ की फीस लेने वाले देश के दूसरे सबसे महंगे स्टार विजय ने हर मृतक को 20 लाख का मुआवजा देकर कानूनी जवाबदेही से छुटकारा पाने का प्रयास किया है। नए मोटर वाहन कानून में सख्त जुर्माने के प्रावधान के बावजूद 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 4.44 लाख लोगों की मौत हुई। फरवरी 2022 में बनाए नियमों के अनुसार हिट एंड रन मामलों में मृत लोगों के लिए 2 लाख के मुआवजे का नियम है। तमिलनाडु सरकार ने 10 लाख तो प्रधानमंत्री ने 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन सरकारी सिस्टम में खामियों की वजह से मरने वाले अनेक लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजे की रकम चुनावी नफे-नुकसान के अनुसार निर्धारित होना असंवैधानिक है। एक संविधान और एक नागरिकता वाले देश के सभी राज्यों में पीड़ितों को समान रूप से मुआवजे का एक कानून होना चाहिए।

स्कूल, अस्पताल, ब्लड-बैंक और जरूरी सुविधाओं के इलाकों में रोड-शो नहीं हो सकता। काफिले में दस से ज्यादा गाड़ियां न हों। उनका पूर्व विवरण देना भी जरूरी है। रोड-शो के दौरान आधी सड़क में यातायात सुचारु जारी रहना चाहिए।

5. चुनावी रथ : आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने चुनावी रथ की शुरुआत की थी। आडवाणी की रथ-यात्रा की सफलता के बाद नेताओं में रोड-शो का चलन बढ़ गया। बड़े नेताओं का अनुसरण करते हुए विजय ने भी रथ को चुनावी मंच में तब्दील कर लिया था। थिंक टैंक सीएएससी ने पिछले आम चुनावों के समय चुनाव आयोग से गैर-कानूनी चुनावी रथ और रोड-शो के चलन पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस सख्ती से बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, उसी तर्ज पर चुनावी रथ और रोड-शो को रोकने के लिए कानून लागू हों तो लोकतंत्र और संविधान दोनों के प्रति जेन-जी और युवाओं का सम्मान ज्यादा बढ़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

11 अक्टूबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने साइबर हमलों में बढ़ोतरी से कारोबारों को हो रहे नुकसान पर खास खबर की है। मैग्जीन ने मिडिल ईस्ट में युद्धविराम के संभावित नतीजों का विश्लेषण किया है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

रिसर्च

डार्क चॉकलेट के फायदों के दावों पर संशय है

डार्क चॉकलेट को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है। उससे हाई ब्लडप्रेशर, अवसाद से बचाव और मानसिक जागरुकता में सुधार जैसे दावे किए जाते हैं। अक्सर बड़ी चॉकलेट कंपनियों द्वारा प्रायोजित कई अध्ययनों में इन दावों को सच बताया गया है, लेकिन रिसर्च इन्हें गलत भी बताती है। एक बड़े ट्रायल में डार्क चॉकलेट खाने से डायबिटीज, दिल की बीमारियों और कैंसर के नए मामलों की दर में कोई अंतर देखने को नहीं मिला है।

डार्क चॉकलेट से फायदों के दावे फ्लैवेनॉल जैसे तत्व के कारण बताए गए हैं। यह कोका में काफी मात्रा में होता है। 2015 में अमेरिका में डार्क चॉकलेट खाने के प्रभावों पर एक बड़े ट्रायल कॉस्मॉस से स्थिति स्पष्ट होती है। 60 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को 42 माह तक 500 मिलीग्राम फ्लैवेनॉल के कैप्सूल दिए गए। फ्लैवेनॉल की इतनी मात्रा के लिए 280 ग्राम डार्क चॉकलेट खाना पड़ेगी। फ्लैवेनॉल से डायबिटीज, दिल के दौरे, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर के नए मामलों की दर पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

दमन भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर बने लियूझी कानून से कारोबारी और अधिकारी प्रताड़ित हो रहे हैं

चीन में अमीरों पर बेड़ियां, 2024 में 38 हजार से ज्यादा गिरफ्तार, 5 बड़ी कंपनियों के प्रमुख आत्महत्या कर चुके

यू फाक्सिन का नाम अब तक चीन के अग्रणी वैज्ञानिकों और उद्यमियों में गिना जाता था। वे रक्षा तकनीक से जुड़े अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के विशेषज्ञ थे, लेकिन 22 सितंबर को उनकी कंपनी ग्रेट माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ने खुलासा किया कि चीन की भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। वे फिलहाल 'लियूझी' नामक हिरासत प्रणाली में हैं। 'लियूझी' एक ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायिक प्रणाली से अलग काम करती है। और जिसमें अब तेजी से कई कारोबारी फंस रहे हैं।

लियूझी प्रणाली को 2018 में बनाया गया था। शी जिनपिंग की शुरू की गई इस मुहिम का मकसद शुरुआत में पार्टी नेताओं और सरकारी अफसरों पर भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई करना था, लेकिन अब इसका निशाना कारोबारी भी बन रहे हैं। यह व्यवस्था सामान्य पुलिसिंग से अलग है। इसके तहत किसी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी नहीं होती। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को वकील की सामान्य सेवाएं नहीं मिलतीं। जून में बने नए नियमों से एजेंसियों को किसी को आठ महीने तक बंद रखने, नए आरोप जोड़ने और अनंतकाल तक पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है। इन हिरासत कक्षों में न खिड़की होती है, न अंधेरा। चौबीसों घंटे रोशनी रखी जाती है। कैदियों के शौचालय जाने तक की निगरानी होती है। शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का तेजी से विस्तार इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। सलाहकार फर्म गेवेकल ड्रैगनॉमिक्स के अनुसार, इस साल 10 लाख से अधिक मामले दर्ज होने की संभावना है। विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र, जो स्थानीय सरकारों से गहराई से जुड़े हैं, ज्यादा जोखिम में हैं। कुछ मामलों को 'डीप-सी फिशिंग' यानी दबाव डाल कर फंड लेने का बहाना बताया जा रहा है- जहां हल्के आरोपों पर किसी कारोबारी को पकड़ लिया जाता है, ताकि दबाव डालकर उससे किसी और अमीर व्यक्ति का नाम निकलवाया जा सके, और फिर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

पिछले साल 39 कंपनियों के प्रमुख नजरबंद

2024 में सितंबर तक करीब 39 लिस्टेड कंपनियों के प्रमुखों को नजरबंद किया गया। हालांकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि अनलिस्टेड कंपनियों को निवेशकों को ऐसी जानकारी देने की बाध्यता नहीं होती। पार्टी के अनुशासन जांच आयोग (सीसीडीआई) के अनुसार 2024 में कुल हिरासतों की संख्या लगभग 38,000 रही।

क्रेडिट ब्लैकलिस्ट खतरनाक

कई शीर्ष उद्यमियों के नाम हाल में देश की क्रेडिट ब्लैकलिस्ट में डाले गए हैं- जो उन्हें आलीशान जीवन से रोकती है। इस सूची में आने वालों पर विमान या लग्जरी ट्रेन से यात्रा करने, महंगे होटलों में रुकने जैसी पाबंदियां लग जाती हैं।

इमारतों से लगा रहे हैं छलांग

अप्रैल से जुलाई के बीच कम-से-कम पांच प्रमुख कारोबारियों ने ऊंची इमारतों से छलांग लगाकर जान दी। इनमें वांग लिनपेंग का मामला सबसे चर्चित रहा, जो हुबेई प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति और एक सफल डिपार्टमेंट स्टोर चेन के संस्थापक थे। अप्रैल में उन्हें लियूझी में रखा गया, जुलाई में छोड़ा गया, लेकिन निगरानी जारी रही।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

वर्ल्ड इन ब्रीफ

ब्रिटेन: यहूदियों के खिलाफ छह माह में 1500 घटनाएं

ब्रिटेन में जून तक यहूदियों के खिलाफ नफरत से जुड़ी 1500 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें सड़कों, ऑनलाइन गाली-गलौज और यहूदी स्कूलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लाल पेंट लगाने जैसे वाकये शामिल हैं।ब्रिटेन में तीन लाख 50 हजार यहूदी हैं। दो अक्टूबर को मानचेस्टर में यहूदी धर्मस्थल साइनागॉग पर हमले में दो यहूदियों की मौत ने समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी यहूदी की हत्या होते नहीं देखी थी।

माइग्रेशन में गिरावट से अमेरिका को नुकसान

राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में हर साल अमेरिका में 25 लाख आप्रवासी आते थे। इस साल यह संख्या शून्य है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने मेक्सिको से लगी सीमा बंद कर दी है। इमिग्रांट्स पर रोक का असर कृषि और उद्योगों पर पड़ने की संभावना बढ़ी है। अमेरिकी शहर सैन डिएगो में कारोबार प्रभावित होने लगा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के फ्लोरेंस जाउमोटे के अनुसार अमीर देशों में माइग्रेंट्स की संख्या में एक प्रतिशत वृद्धि से प्रति व्यक्ति जीडीपी में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। अब 79% अमेरिकी कह रहे हैं कि देश के लिए इमिग्रेशन अच्छा है।

दुनियाभर में लग्जरी ट्रैवल में भारी बढ़ोतरी के आसार

लग्जरी इंडस्ट्री में विभाजन दिखाई पड़ता है।कई लोग हाई हील्स, हैंड बैग्स जैसी फैन्सी चीजों पर कम खर्च कर रहे हैं। वहीं कुछ पॉश होटलों और फर्स्ट क्लास हवाई किरायों पर खूब खर्च कर रहे हैं। कंसल्टेंसी मेकिंजी ने बताया कि 2028 में ग्लोबल लग्जरी हॉस्पिटैलिटी पर खर्च 34.59 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह 2023 में 21 लाख करोड़ रुपए था। डेटा फर्म कोस्टार के मुताबिक इस साल 2024 की तुलना में लग्जरी होटल रूम से अधिक आय हुई है। जून-अगस्त के बीच अमेरिका में फर्स्ट क्लास फ्लाइट बुकिंग पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ीं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन पुराने समझौतों के मुकाबले नई पहल अधिक व्यावहारिक

मिडिल ईस्ट में नई शुरुआत करने का अच्छा अवसर

कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच भीषण टकराव का हल निकालने की कोशिश की है। गाजा में दो साल तक अंतहीन हत्याओं के बाद अब डोनाल्ड ट्रम्प उन नेताओं की छोटी सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें कामयाबी मिली है। इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के शुरुआती समझौते ने मिडिल ईस्ट में एक नए दौर का रास्ता खोला है। रास्ता संकरा तो है, लेकिन यह 1993 और 1995 के ओस्लो समझौतों के बाद स्थायी शांति का सबसे बेहतर मौका है।

यह जमीन के नक्शों और दो देशों की काल्पनिक संवैधानिक व्यवस्था के लिए अंतहीन बातचीत से परे है। इसने गाजा के शासन और उसे नए सिरे से बनाने, आतंकवादियों से मुक्ति दिलाने का व्यावहारिक प्रस्ताव रखा है।

शांति करार ट्रम्प की सौदेबाजी और धमकाने की कूटनीति की जीत है। ट्रम्प की बीस सूत्री योजना के तहत अगले दौर में एक सरकार गाजा का पुनर्निर्माण करेगी। हमास को सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके हथियार ले लिए जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय सेना वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगी। फिलिस्तीनियों के जिम्मेदारी संभालने तक ट्रम्प एक बोर्ड की अगुआई करेंगे।

समझौते की राह में बहुत बाधाएं हैं। दोनों पक्ष के वार्ताकार अपने मतभेद नहीं सुलझा पाए हैं। हमास के निशस्त्रीकरण पर गतिरोध है। हमास आगे जाकर दिक्कत पैदा कर सकता है। फिर भी उम्मीद के आधार मौजूद हैं। युद्ध खत्म होने से दोनों पक्षों के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। हमास के बाकी नेताओं को हटाया जा सकता है इजराइल में एक साल के अंदर चुनाव कराना होंगे। सर्वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू को पद छोड़ना पड़ेगा। दुनिया का फोकस भी शांति पर है। ट्रम्प ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने में नहीं हिचकेंगे। ईरान और उसके सहयोगियों के कमजोर पड़ने से क्षेत्र में खतरा कम हो गया है। खाड़ी के अरब देश गाजा पुनर्निर्माण के लिए धन देंगे। वे शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ट्रम्प को अब देखना होगा कि नेतनयाहू या उनके उत्तराधिकारी यहूदी बस्तियों का विस्तार न कर पाएं। वहां बसे यहूदियों और सैनिकों की हिंसा को रोकना होगा। इजरायलियों के लिए यह अरब देशों से सहयोग और सुरक्षित रहने के लिए नई व्यवस्था बनाने का अवसर है।

दोनों पक्षों का कड़ा रुख

2012 में 61 % इजराइली दो राष्ट्रों के समर्थक थे। अब सिर्फ एक चौथाई हैं। कई फिलिस्तीनियों की मौतों पर बेरुखी जताते हैं। दूसरी ओर फिलिस्तीनी लोग इजराइल को एक दुष्ट राज्य मानते हैं जो उनकी जमीन हथियाना चाहता है। हिंसा करना चाहता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

खतरा जगुआर जैसी कंपनियों पर बढ़े साइबर हमले

साइबर हमले से बचाव पर इस साल खर्च होंगे 18 लाख करोड़ रुपए

इन दिनों साइबर अपराधी बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के पीछे कई गुट काम कर रहे हैं। अभी हाल में साइबर हमलों से भारतीय कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) और जापानी बियर कंपनी असाही का काम ठप पड़ गया था। जेएलआर पर तीन संगठनों की टीम स्कैटर्ड स्पाइडर/ लेपसस$ हंटर्स ने हमले का दावा किया है। रूसी ग्रुप क्विलिन ने असाही को निशाना बनाया था। असाही ने 30 सितंबर को बताया कि हमले से कंपनी की 30 फैक्टरियां, कॉल सेंटर प्रभावित हुए। हैकिंग के बाद कार निर्माता जेएलआर के उत्तर और मध्य इंग्लैंड स्थित कारखानों में काम रुक गया था। बढ़ते हमलों से बचाव के लिए इस साल साइबर सिक्योरिटी पर 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। साइबर हमले से प्रभावित जेएलआर को एक सप्ताह में 595 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

1.33 लाख करोड़ प्रीमियम

इंश्योरेंस कंपनी म्यूनिख रे के अनुसार 2024 में दुनियाभर में साइबर अपराधों से बचने के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपए प्रीमियम चुकाया गया। इसके 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।

साइबर इंश्योरेंस विशेषज्ञ बताते हैं,दस छोटी से मध्यम कंपनियों में से केवल एक कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी नीति बनाई है। जबकि दस बड़ी कंपनियों में से छह ने बचाव के कदम उठाए हैं। बढ़ते जोखिम को देखते हुए इंश्योरेंस पॉलिसी के मूल्य अगले 12 महीनों में बढ़ सकते हैं। रिसर्च फर्म गार्टनर के अनुसार इस साल साइबर सिक्योरिटी पर 18.38 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बात कहूंगा खरी-खरी

दीपावली के उपहार इंद्र की शक्ति की तरह हैं!

सुरेंद्र शर्मा
कवि एवं लेखक
surendersharmakavi@hotmail.com

अक्टूबर त्योहारों का महीना है। पिछले सप्ताह दशहरा मनाया गया। दिल्ली में रावण को जलाने के चक्कर में रामलीला कमेटियों के पसीने छूट गए। भारी भीड़ रावण-दहन का कार्यक्रम देखने इकट्ठी थी। लेकिन बारिश ने रावण को न जलने का वरदान दे रखा था। इधर मंच पर रावण बनकर युद्ध करने वाला अभिनेता भी पसीने में लथपथ था कि उसका पुतला जले तो उसे मुक्ति मिले। लेकिन रावण का पुतला जलने को तैयार ही नहीं था। अंत में रो-पीटकर आयोजकों को खुले आसमान की जगह बंद पंडाल में छोटा सा रावण फूंककर रावण को मृत्युदंड देना पड़ा। तब कहीं जाकर असत्य पर सत्य की जीत हो सकी।

एक रामलीला में तो मुझे मुख्य अतिथि बनाकर रावण मारने का कार्य सौंपा गया। मैंने साफ इनकार कर दिया। रावण हमारे कुल का है। मैं अगर उसे मार देता तो बाद में मेरी अन्तरात्मा मुझे धिक्कारती। अपने परिवार के आदमी को मारने में जो सहयोगी रहेगा, उसे भला कैसे चैन मिलेगा। विभीषण को ही देख लो। आज तक किसी ने अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखा। हमारे एक वरिष्ठ कवि विमलेश राजस्थानी ने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखी। उसमें वर्णन है कि युद्ध के बाद राम जब अयोध्या लौटे तब रामजी ने भरत को गले लगाया। विमलेश जी लिखते हैं कि इस क्षण में विभीषण किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था, और मन ही मन सोच रहा था कि एक ये भाई है, एक मैं भाई हूं।

अब पूरा देश दीपावली के उपहार बांटने निकल पड़ा है। वही डिब्बे घूम-फिरकर एक-दूसरे को पकड़ा दिए जाते हैं।

एक रामलीला कमेटी ने उसी व्यक्ति को इस वर्ष भी रावण का रोल करने को कहा, जिससे पिछले वर्ष करवाया था। अच्छा, रावण का पिछली बार का पेमेंट बाकी था। वह भी खुशी-खुशी रावण बनने को तैयार हो गया। लेकिन उसने तय कर लिया कि अबकी बार पूरा पेमेंट लिए बिना मरूंगा ही नहीं।

आधा-पौना घंटा युद्ध चलता रहा। डायरेक्टर पर्दे की पीछे से बार-बार कहता कि रावण मर जा, पर रावण ने तय कर रखा था कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, तब प्राण नहीं छोड़ूंगा। मजबूरन रामलीला वालों ने तीर के आगे रुपए बांधकर मुद्रा बाण छोड़ा। तब रावण मरा।

हम ऊपर-ऊपर त्योहार मनाते फिरते हैं और मन के अंदर कोई त्योहार नहीं मनता। अब पूरा देश दीपावली के उपहार बांटने निकल पड़ा है। वही डिब्बे घूम-फिरकर एक-दूसरे को पकड़ा दिए जाते हैं। हमारे घर पर कई साल से बंद मेवे का एक थाल है। पिछले साल मैंने देखा कि उसके मेवों में घुन लग चुका है। मैंने उसे हर साल की तरह किसी को उपहार में दे दिया। और हर साल की तरह वह पिछले साल भी घूम-फिरकर फिर हमारे घर लौट आया। वह दरअसल थाल नहीं, इन्द्र की एक शक्ति है जो एक बार प्रयोग के बाद वापस लौटकर इन्द्र के पास चली जाती है। यदि इस साल यह थाल उपहारों की यात्रा का वनवास काटकर मेरे घर नहीं लौटा तो मैं घी के दीये जलाउंगा।

कार्टून कोना

माइंड ट्विस्टर

‘मैं फल हूं अस्पताल नहीं...’

हर हफ्ते यहां आपसे पूछा जाएगा एक सवाल जिसके देने होंगे जवाब। पिछले हफ्ते का सवाल था- **एक अनार सौ बीमार क्यों कहते हैं, दो सौ-तीन सौ बीमार क्यों नहीं...**

- अगर कह दें ‘दो सौ या तीन सौ बीमार’, तो अनार तुरंत नौकरी छोड़ देगा, बोलेगा ‘भाई, मैं फल हूं, अस्पताल नहीं!’ **- अभय जाजड़ा, नागौर**
- कहावत बनाने वाला नव-साक्षर होगा, उसे 100 तक ही गिनती आती होगी। **अजय त्रिपाठी, चित्तोड़गढ़**
- दो या तीन सौ ही नहीं मौजूदा जनसंख्या को देखते हुए एक अनार हजार बीमार कहना अधिक उचित होगा। **- शिव चन्द्र साह, बिहार**
- एक अनार सौ बीमार बाकी सब सब लाचार। अस्पतालों की हालत देखते हुए सौ ही बहुत हैं। **- प्रतिभा शाह, इन्दौर**
- भाई ‘अनार’ हैं कोई ‘डॉक्टर’ नहीं कि 100 मरीज ठीक कर लिए तो अब ‘...200 बीमार, 300 बीमार’ बोलो। **- प्रिंस विन्नी, राउरकेला**
- सौ बीमार सुनने में फिट बैठता है- न ज्यादा, ना कम, जैसे बॉलीवुड का डायलॉग ‘एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ोगी?’ **- भव्य अमुलानी**
- बोलेंगे, जरूर बोलेंगे...200 बीमार...300 बीमार, बस अनार को तरबूज/कुम्हड़े के आकार के होने दीजिए, तब तक थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। **- प्रीत पंछी हैप्पी**
- जिस तरह होता- सौ सुनार का एक लुहार का। उसी तरह होता- एक अनार का सौ बीमार का। **- राकेश साहू, नागपुर**
- अनार का जमाना गया, अब एक वाई-फाई और लाखों तैयार का जमाना है साहेब। **- विश्वास दीपक**

अगला सवाल **शेखी बघारना क्यों कहते हैं, शेखी तलना-भूनना क्यों नहीं?** पाठक इसके फनी जवाब इस पते humour@dbcorp.in पर भेज सकते हैं।

फन लाइनर

पंकज प्रसून

ब्रेकअप की भाषा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी

- **बिहार में लाखों नाम मतदाता सूची से कटे।**
बिहार चुनाव में नारा होना चाहिए- पहले ढूंढो नाम, न मिले तो जलपान, मिल जाए तो मतदान।
- **रूस ने कहा- अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा, तो हम भी करेंगे।**
ऐसा लगता है अब ग्लोबल वॉर्मिंग नहीं, अब ग्लोबल वार्निंग का समय चल रहा है।
- **गृह मंत्री अमित शाह ने Zoho Mail पर किया स्विच।**
अब अगर मेल देर से पहुंचे, तो बोला जाएगा- ‘आत्मनिर्भरता में टाइम लगता है।’
- **अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की।**
सपा में फिर से ‘पुराना समाजवाद’ एक्टिव मोड में है।
- **सोनम वांगचुक बोले- जांच होने तक जेल में रहने को तैयार।**
जमानत की जगह जांच मांगने वाला यह व्यक्ति जेल में भी शायद सोलर प्रोजेक्ट लगा दे।
- **युवा AI से डेटिंग सलाह ले रहे।**
प्यार की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौर में ब्रेकअप का कारण होगा- सिस्टम एरर 404: लव नॉट फाउंड।

सैंसिबल मीम्स

सौरभ जैन

गिरीश कुमार

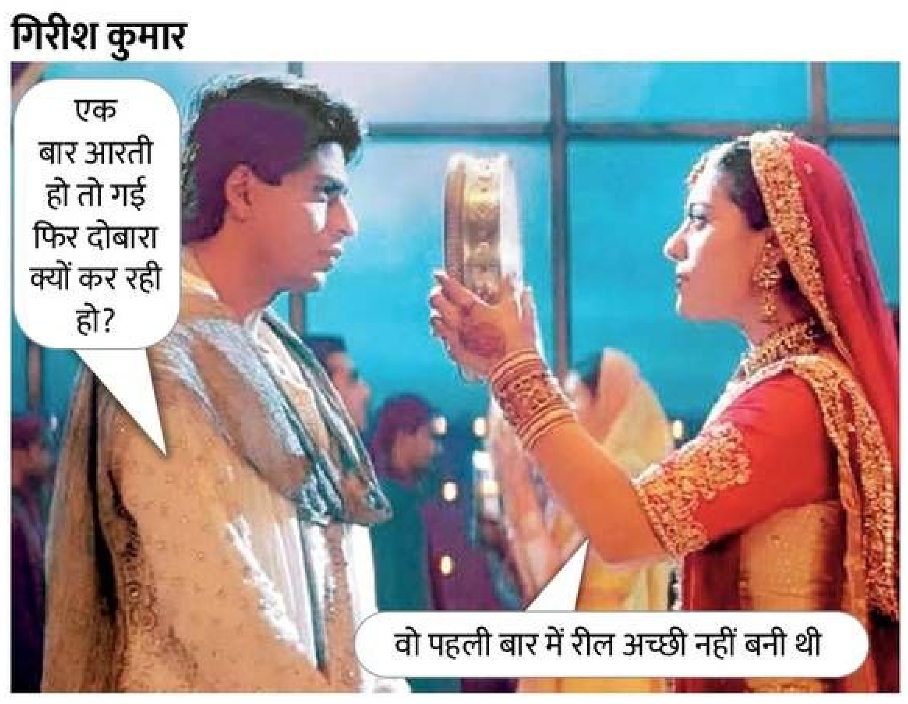

क्लासिक कॉर्नर

ठंड में नहाना प्रकृति विरुद्ध है

हरिशंकर परसाई
मूर्धन्य व्यंग्यकार और लेखक

गंगा स्नान ही नहीं, साधारण स्नान के बारे में भी बड़ा अंधविश्वास है। जैसे यही, कि रोज नहाना चाहिए- गर्मी हो या ठंड। क्यों नहाना चाहिए? गर्मी में नहाना तो माफ किया जा सकता है, पर ठंड में रोज नहाना बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध है। जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है, वे यह क्यों नहीं सोचते की यदि शीतऋतु भी रोज नहाने की होती, तो वह इतनी ठंड क्यों पैदा करता? शीतऋतु उसने नहाने के लिए बनाई ही नहीं है, लेकिन आप ‘सी-सी’ करते जा रहे और रोज नहा रहे हैं। और मुझे यह आजतक समझ नहीं आया कि नहाने और खाने का क्या संबंध है? कोई दोस्त इतवार को सुबह आ जाता है और दोपहर तक बैठता है, मैं उससे भोजन के लिए कहता हूं, तो कह देता है- अभी तो नहाया नहीं है। कितनी लचर दलील है! नहाया नहीं है, तो खाना क्यों नहीं खाएंगे? नहाते शरीर से हैं पर खाते तो सिर्फ मुंह से हैं!

रोज नहाने के पक्ष में तरह-तरह के तर्क दिए जाते हैं; जैसे यह कि स्फूर्ति आती है, दिमाग साफ होता है, काम में मन लगता है आदि। यह सब झूठ है। रोज नहाने वाले कई मूर्ख मैंने भी देखे हैं और आलसी ऐसे कि आज नहाकार सोए, तो कल नहाने के वक्त उठेंगे। प्रतिभा का तो नहाने से उल्टा संबंध है। जो अधिक नहाएगा, उसकी प्रतिभा धुलती जाएगी।

मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो केवल इस कारण शेखी बघारते फिरते हैं कि वे रोज दो बार नहाते हैं। इसे वो बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इससे जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं- ‘भैया, कोई भी मौसम हो, हम तो दो बार नहाते हैं। और ठंडे पानी से’ स्नान के अनुभव को वे बड़े महत्व से सुनाते हैं- ‘बस, पहला लोटा उडेलो, तभी जरा ठंड लगती है। इसके बाद ठंड लगती ही नहीं। गर्मी लगती है। फिर दिन भर बड़ा अच्छा लगता है।’ मैं नहीं जानता, अपने शरीर की सारी उष्णता ठंडे पानी से लड़ने के लिए रोज बाहर निकालना कहां तक अच्छा है। इस उष्णता से कोई उपयोगी काम किया जा सकता है।

गर्मी में नहाना तो माफ किया जा सकता है, पर ठंड में रोज नहाना बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध है। शीतऋतु नहाने के लिए बनी ही नहीं है।

पिछले महीने जब कड़ी ठंड पड़ रही थी, मुझे एक परदेसी मित्र मिला। वह किसी के यहां तीन-चार दिन के लिए मेहमान था। स्नान के बारे में बात करते हुए उसने बताया- ‘आज सुबह मैं नहाने पहुंचा, तो देखा कि सीमेंट के हौज में पानी भरा है; रात भर का ठंडा पानी। पहले तो जी हिचका। पर फिर मैंने लोटा भरकर डाल ही लिया। पांच मिनिट तक देह सुन्न रही।’

मुझे सुनकर ही कंपकंपी आ गई। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा- ‘बंधु, तुममे गजब की इच्छा-शक्ति है। ऐसी दृढ़ इच्छा-शक्ति से तुम बड़ा काम कर सकते थे। पर तुम उसका उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे हो; अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हो। वह हंसता रहा। रवीन्द्रनाथ ने ठीक ही कहा है की ज्ञान की निर्झरनी अंध-विश्वासों की मरूभूमि में खो गई है।

- व्यंग्य ‘स्नान’ के चुनिंदा अंश

फैटी लिवर: डाइट के साथ योग भी जरूरी, त्रिकोणासन से लेकर भुजंगासन जैसे विकल्प से होती है लिवर की सफाई

हर दिन जरूर करें ये 5 योगासन, आपका लिवर होगा डिटॉक्स

आजकल फैटी लिवर एक आम स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जो जीवनशैली और खान-पान की आदतों से जुड़ी है। हालांकि यह बीमारी गंभीर हो सकती है, लेकिन सही उपायों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। योगासन फैटी लिवर के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक तरीका साबित हो सकता है। योग न केवल लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है।

1. त्रिकोणासन

- **फायदे:** यह आसन शरीर में खिंचाव लाकर रीढ़, कमर और हिप्स को मजबूत करता है। पाचन सक्रिय करता है।
- **कैसे करें:** • सीधे खड़े होकर अपने पैरों को फैलाए। • दाहिने हाथ को नीचे पैर की तरफ झुकाएं और बायां हाथ ऊपर उठाएं। • 30 सेकंड तक स्थिति बनाए रखें। • दूसरी तरफ भी दोहराएं।

2. स्फिंक्स मुद्रा

- **फायदे:** स्फिंक्स मुद्रा कोर मसल्स को मजबूत करती है और यह आपके शरीर को रिलेक्स करने में भी काफी उपयोगी है।
- **कैसे करें:** • पेट के बल लेट जाएं। • कोहनियां को कंधों के नीचे रखें। • फिर ऊपर की ओर छाती उठाएं और सीधा देखते रहें। इसी अवस्था में आपको 1 मिनट तक रहना है।

3. भुजंगासन

- **फायदे:** यह आसन रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाती है और पाचन व श्वसन क्रिया को बेहतर बनाती है।
- **कैसे करें:** • पेट के बल लेटकर हथेलियां कंधों के नीचे रखें। सांस लेते हुए छाती और सिर ऊपर उठाएं। इसके बाद 30 सेकंड तक इसी अवस्था रहें, 1 से 3 बार दोहराएं।

4. धनुरासन

- **फायदे:** यह आसन रक्त संचार को तेज करती है और पाचन तंत्र को सक्रिय बनाती है। शरीर की थकान भी दूर होती है।
- **कैसे करें:** • पेट के बल लेट जाएं। • पैरों को मोड़कर टखनों को पकड़ें। • छाती और पैरों को ऊपर उठाएं। • 30 सेकंड तक रहें। 1–2 बार दोहराएं।

5. अर्ध मत्स्येन्द्रासन

- **फायदे:** इस आसन को करने से शरीर का तनाव कम होता है। साथ ही लिवर, पाचन तंत्र जैसे आंतरिक अंग भी सक्रिय होते हैं।
- **कैसे करें:** • बैठकर एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के बाहर रखें। शरीर को घुमाएं और पीछे की ओर देखें। 1 मिनट तक रहें, फिर दूसरी ओर करें।

एक अच्छी आदत

रोज माइंडफुल ब्रीदिंग करें, इसके तीन फायदे

हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताना अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। माइंडफुल ब्रीदिंग एक ऐसी आसान प्रैक्टिस है, जो बिना किसी खर्च के मन को शांत और शरीर को रिलैक्स कर सकती है।

कैसे करें माइंडफुल ब्रीदिंग

- **शांत जगह पर बैठें:** रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। अब बस अपनी सांस पर ध्यान दें, कैसे आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं।
- **गिनती के साथ फोकस करें:** सांस अंदर लेते हुए मन में गिनें, 1, 2... 3... सांस छोड़ते हुए गिनें।
- **विचार आने पर घबराएं नहीं:** अगर मन में विचार आने लगें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें।
- **गहरी सांस का अभ्यास करें:** गहरी सांस लें, 5 सेकंड रोकें और धीरे से छोड़ें। यह 3 बार करें।

इस आदत के तीन बड़े फायदे

- **नींद बेहतर होती है:** रात में सोने से पहले यह करने से नींद गहरी और आरामदायक होती है।
- **फोकस बढ़ाता है:** दिनभर के काम में एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।

ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है: नियमित डीप ब्रीदिंग से हार्ट रेट और बीपी दोनों संतुलित रहते हैं।

मेंटल हेल्थ: हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर जोर दीजिए

तनाव दूर करने में दवाइयों से डेढ़ गुना असरदार है एक्सरसाइज

healthline से विशेष

लगातार स्ट्रेस न सिर्फ मूड पर असर डालता है, बल्कि दिल की बीमारी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। व्यायाम कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे- डिप्रेशन, ADHD और एंग्जायटी के इलाज में असरदार सपोर्टिव तरीका है। 2023 की एक स्टडी में पाया गया कि मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल एक्टिविटी दवाइयों से 1.5 गुना अधिक असरदार रही।

एक्सरसाइज तनाव कैसे कम करती है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन की 2021 की एक स्टडी के अनुसार व्यायाम करने से तनाव से जुड़े हार्मोन (जैसे कॉर्टिसोल) को कंट्रोल करने वाले सिस्टम में सुधार आता है। इसका असर धीरे-धीरे आपकी मानसिक स्थिति पर दिखने लगता है। स्टडी में ये भी पाया गया कि जो लोग तेज या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, वे हल्की एक्सरसाइज करने वालों की तुलना में तनाव पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं।

दैनिक भास्कर हेल्थ पॉडकास्ट

इस खबर को आप पॉडकास्ट के जरिए भी सुन सकते हैं। इस QR को स्कैन करें और हेल्थ की इस खबर को मजेदार अंदाज में सुनें। हर हफ्ते आपको हेल्थ पेज पर मिलेगा पॉडकास्ट।

एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा... ये बातें जानें

1. अपनी पसंद का समय चुनें
कुछ लोग सुबह जल्दी तो कुछ शाम को वर्क आउट करना पसंद करते हैं। जब आप अपने लिए सही समय तय कर लेते हैं, तो उसे रूटीन में बनाए रखना आसान हो जाता है।

2. छोटे टास्क से करें शुरू
बड़े लक्ष्य शुरू में डरावने लग सकते हैं। इसलिए पहले छोटे लक्ष्य बनाए। हर बार जब आप इन्हें पूरा करें, तो खुद को छोटा रिवॉर्ड दें। जैसे सप्ताह में एक दिन या दो दिन से शुरू करें। धीरे-धीरे इसे बढ़ाएं।

3. ग्रुप एक्सरसाइज करें
किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ वर्कआउट करने से मोटिवेशन भी बढ़ता है। साथ में एक्सरसाइज करना ज्यादा मजेदार और प्रेरणादायक हो सकता है।

4. पर्सनल ट्रेनर की मदद लें
एक प्रोफेशनल ट्रेनर आपको आपकी जरूरत और फिटनेस लेवल के अनुसार गाइड कर सकता है। इससे आपकी तकनीक सही रहेगी, चोट लगने का खतरा कम होगा और आप हर सेशन से पूरा फायदा उठा पाएंगे।

हेल्थ रिसर्च

चैटबॉट की सलाह से युवाओं में कम हुई शुगर ड्रिंक्स की लत

किशोरों को अगर चैटबॉट से पर्सनल फीडबैक मिले, तो वे शुगर ड्रिंक्स पीने की आदत काफी हद तक छोड़ सकते हैं। दक्षिण कोरिया में हुई एक नई स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 14 दिन के चैटबॉट इंटरवेंशन से टीनएजर्स की शुगर ड्रिंक की खपत 40 ग्राम से घटकर 2 ग्राम प्रतिदिन रह गई। इस रिसर्च में R-Ma Bot नाम के चैटबॉट का इस्तेमाल हुआ। इसी की मदद से शुगर की लत कम हुई।

क्या निकले नतीजे?

- 42 टीनएजर्स ने इस स्टडी में हिस्सा लिया।
- 38% ने अपनी शुगर ड्रिंक पूरी तरह छोड़ दी।
- औसत शुगर सेवन 39.8 ग्राम से घटकर 1.8 ग्राम रह गया।
- जिन बच्चों को पर्सनलाइज्ड चैट फीडबैक मिला, उनमें सुधार ज्यादा दिखा।

न्यूट्रिशन गाइड: टोफू के साथ पालक, फ्रूट चाट और ओट्स-बेरी जैसे विकल्प चुनें

दिन की शुरुआत के लिए 5 गट-फ्रेंडली ब्रेकफास्ट

क्या हर सुबह आपका पेट भारी महसूस करता है? अगर हां, तो जरूरत है अपनी सुबह की प्लेट को थोड़ा स्मार्ट बनाने की। छोले भटूरे-पूरी सब्जी, समोसा या तले हुए विकल्प शरीर में थकान बढ़ाते हैं। ऐसे में फाइबर, प्रोटीन और प्रोबायोटिक से भरपूर नाश्ता पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको कोई महंगे इंग्रीडिएंट्स या मुश्किल रेसिपीज की जरूरत नहीं ब्लकि कुछ सरल और पोषण से भरपूर विकल्प आपके पाचन तंत्र को बेहतर बना सकते हैं। तो आपके लिए पेश हैं ये 5 गट-फ्रेंडली ब्रेकफास्ट...।

1. ब्रेड के साथ केले और पीनट बटर

ब्रेड टोस्ट करें, ऊपर पीनट बटर लगाएं और केले के टुकड़े रखें। फाइबर से भरपूर ये नाश्ता पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है।

2. ओट्स-बीज और बेरी के साथ

ओट्स, दूध, चिया सीड्स और शहद मिलाकर फ्रिज में रात भर रखें। सुबह ताजा फल डालकर खाएं। नाश्ता आपको दिनभर ऊर्जा देता है।

3. फ्रूट चाट को चुनिए

सेब, पपीता, कीवी और संतरे जैसे फल काटें। कद्दू, अलसी और सूरजमुखी के बीज डालें। नींबू और काला नमक डालकर खाएं। ताजे फल और बीज पाचन में मदद करते हैं।

4. टोफू और पालक को मिक्स करके खाएं

टोफू को कड़ाही में हल्का भूनें, इसमें पालक, प्याज और मिर्च डालें। टोफू प्रोटीन देता है और पालक आयरन व फाइबर से भरपूर है।

5. बादाम के दूध के साथ चिया-पुडिंग खाएं

चिया बीज और बादाम का दूध मिलाकर रात भर फ्रिज में रखें। ऊपर फल या मेवे डालकर खाएं। ओमेगा-3 और फाइबर से भरपूर है।

अपराध संक्षेप

पकड़े जाने पर खुद को ब्लेड मारा

पूर्वी दिल्ली। शकरपुर में एक आरोपी ने पकड़े जाने पर खुद को ब्लेड से घायल कर लिया। आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी साहिल उर्फ मुस्तकीम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी चार अक्तूबर की रात स्कूल ब्लॉक शकरपुर बस स्टैंड के पास बस से उतर रही एक महिला से मोबाइल फोन लूट कर भाग रहा था। इस दौरान जब आरोपी को पकड़े जाने का अहसास हुआ तो उसने खुद को ब्लेड से घायल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद

कई मामलों में वांछित बदमाश दबोचा

नई दिल्ली। अपराध शाखा ने कई जघन्य अपराधों में शामिल रहे बदमाश दीपक उर्फ दीपू उर्फ पव्वा उर्फ अजय को गुलाबी बाग से गिरफ्तार किया। उसे कई मामलों में बदमाश घोषित किया हुआ था। पुलिस ने इसके पास से चोरी की स्कूटी और ओपो मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी हत्या के प्रयास, डकैती, सेंधमारी और शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन आदि के 30 से अधिक मामलों से शामिल रहा है। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि एसआई प्रकाश, एसआई रंजीत सिंह व एसआई गुमान सिंह की टीम ने उसे 9 अक्तूबर की सुबह गुलाबी बाग में घेराबंदी कर चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो

लूटकर भाग रहे बदमाश ने चाकू मारा

नई दिल्ली। आजादपुर मंडी इलाके में बदमाश ने संजय कुमार नाम के व्यक्ति का मोबाइल लूट लिया। पीड़ित के बेटे नितिन ने भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया तो बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गया। मौका पाते ही बदमाश फरार हो गया। लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। महेंद्र पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया। घायल के पिता संजय कुमार आजादपुर मंडी स्थित बी ब्लॉक के पास कचौड़ी की रेहड़ी लगाते हैं। आठ अक्तूबर की रात काम खत्म कर बेटे के साथ लौट रहे थे। तभी वारदात हुई। ब्यूरो

ऑनलाइन बाल अश्लीलता में गिरफ्तार

नई दिल्ली। भलस्वा डेयरी इलाके से ऑनलाइन बाल अश्लीलता के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान कलंदर कॉलोनी (भलस्वा डेयरी) निवासी सलमान के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से साक्ष्य के तौर पर उसका मोबाइल बरामद किया। जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि गुमशुदा व शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र की ओर से भलस्वा डेयरी पुलिस को साइबर टिपलाइन रिपोर्ट मिली। इसमें बाल यौन शोषण सामग्री थी। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता की ओर से तैयार रिपोर्ट बाल यौन शोषण सामग्री विशेष रूप से बाल अश्लीलता के निर्माण व वितरण से संबंधित थी। ब्यूरो

गहनों की दुकान में लाखों की लूट, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सहित 3 धरे

24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, 15 लाख के गहने, मोबाइल व नकदी बरामद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। समयपुर बादली में पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई की ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की। बदमाश दुकान से दस सोने की चेन लूटकर भाग गए। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए घटना के 24 घंटे के अंदर पीड़ित के दो चचेरे भाइयों विशाल और मनीष के साथ सुमित को गिरफ्तार कर लिया।

सुमित राष्ट्रीय स्तर का वालीबॉल खिलाड़ी है और नरेला में हत्या के एक मामले में शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 15 लाख कीमत की दस सोने की चेन, मोबाइल र 10,000 रुपये नकद बरामद किए हैं।

जब्त हुआ सामान। अमर उजाला

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 4 अक्तूबर को पुलिस को रोहिणी सेक्टर-18 स्थित ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की सूचना मिली। मौके पर पुलिस को शिकायतकर्ता बादली निवासी अनिल कुमार मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि बदमाश उनकी आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़ककर करीब दस सोने की चेन लूटकर भागे हैं। वह सोनी ज्वैलर्स के नाम से एक ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं।

पीड़ित ने बताया कि दोपहर में वह दुकान में मौजूद थे। करीब डेढ़ बजे उनका चचेरा भाई बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी विशाल एक साथी के साथ उनकी दुकान पर आया। उसने अनिल से कुछ सोने की चेन दिखाने को कहा और कहा कि उसका दोस्त सोने की चेन खरीदना चाहता है। पीड़ित ने काउंटर पर 10-11 सोने की चेन वाली ट्रे रख दी। कुछ समय बाद विशाल मोबाइल पर बात करते हुए दुकान से बाहर चला गया जबकि उसका साथी उनकी आंखों पर मिर्च स्प्रे कर सभी सोने की चेन लूटकर भाग गया।

थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह जाखड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसमें बदमाश वारदात के बाद कार से भागते हुए दिखे। बदमाशों के परिचित होने की वजह से पुलिस ने तकनीकी जांच करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान विशाल वर्मा, ककरौला निवासी उसका चचेरा भाई मनीष वर्मा और सेक्टर-19 द्वारका निवासी सुमित डबास के रूप में हुई। विशाल और सुमित डबास के पास से पांच-पांच सोने की चेन, 10,000 रुपये नकद और 40,000 रुपये कीमत का एक मोबाइल फोन मिला।

जांच में पता चला कि आरोपियों ने एक सोने की चेन बेचकर अपने दो खातों में 80,000 रुपये जमा करवाए हैं, पुलिस ने उस खाते को फ्रीज कर दिया है।

जेल में हुई थी विशाल और सुमित की दोस्ती

पूछताछ में पता चला कि विशाल वर्मा पीड़ित का चचेरा भाई है। उसे शराब पीने और इधर-उधर फालतू में पैसे खर्च करने का शौक है। अक्तूबर 2024 में शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने उसे छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। वहीं, मनीष वर्मा विशाल का चचेरा भाई है और विशाल वर्मा के साथ ही घूमता है। सुमित राष्ट्रीय स्तर का वालीबॉल खिलाड़ी है। वह नरेला थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में शामिल रहा है। पूछताछ में पता चला कि दिसंबर 2024 को विशाल और सुमित की तिहाड़ जेल में दोस्ती हुई थी। विशाल जनवरी 2025 में जेल से बाहर आया और हाल ही में उसकी शादी हुई। सुमित डबास 18-19 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद हाल ही में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था। दशहरा से एक दिन पहले रामलीला मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों को पैसों की जरूरत थी। सुमित डबास ने उसे अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र से मिलवाया जो रामलीला मेले में बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। वहीं, विशाल ने अपने चचेरे भाई मनीष से उन्हें मिलवाया। सभी ने अनिल की ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की योजना बनाई। उनलोगों ने वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तम नगर से एक टैक्सी किराये पर ली और लूटपाट को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद विशाल और मनीष गुरुग्राम में एक पंजीकृत गोल्ड एक्सचेंजर के पास गए और वहां एक चेन बेच दी। उसने एक फोन खरीदा और मनीष के खाते में 50,000 रुपये और उसकी पत्नी के खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए।

दो मंजिला मकान गिरा, महिला की मौत, पांच साल की बेटी हुई घायल

उत्तम नगर के हस्तसाल गांव की घटना, पुलिस मकान गिरने के कारणों की जांच कर रही

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में शुक्रवार दोपहर दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरते ही अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत से जुड़ीं अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। कुछ देर में बचाव दल ने मलबे से मकान मालिक नीरज की पांच साल की बेटी और पत्नी को बाहर निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

मृतका की पहचान 33 साल की पूनम के रूप में हुई। घायल बच्ची नव्या को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए एजेंसियां मलबा हटाने के काम में जुट गईं लेकिन नीचे और कोई नहीं मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि मकान जर्जर हालत में था।

पुलिस मकान गिरने के कारणों की जांच कर रही है। दमकल अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3.10 बजे उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में दो मंजिला मकान गिरने और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मकान गिरने के बाद आसपास के लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचे और मलबा हटाने के काम में जुट गए।

उत्तम नगर में राहत व बचाव कार्य में जुटी टीम। अमर उजाला

घटनास्थल पर पहुंची एंबुलेंस। अमर उजाला

शुरुआती जांच में पता चला कि मकान काफी जर्जर हालत में था

थोड़ी ही देर में गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर घटनास्थल के पास घेराबंदी की। दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, एंबुलेंस और सिविक एजेंसी की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम तुरंत मलबा हटाने में जुट गई।

दमकल विभाग के एडीओ संतोष ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने कुछ देर बाद मलबे से पांच साल की बच्ची और एक महिला को बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

पैसे के विवाद में टैंपो चालक ने की मालिक की हत्या

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चाकू बरामद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। बुध विहार में पैसों के विवाद में टैंपो चालक ने मालिक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त रिठाला की पाल कॉलोनी निवासी (45) जितेंद्र यादव के रूप में हुई। पुलिस ने छानबीन करते हुए फरार आरोपी शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 2 अक्तूबर को बुध विहार थाने को अंबेडकर अस्पताल से एक व्यक्ति को चाकू मारे जाने के बाद भर्ती किए जाने की जानकारी मिली। घायल की पहचान रिठाला निवासी जितेंद्र यादव के रूप में हुई। वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। पुलिस वहां से घटनास्थल बजाज सर्विस सेंटर के पास पहुंची, वहां पीड़ित का 14 साल का बेटा मिला, जो चश्मदीद था।

बेटे ने पुलिस को बताया कि दोपहर को उनके टैंपो का ड्राइवर रिठाला निवासी शक्ति उसके पिता से बार-बार पैसे मांग रहा था। कहासुनी के दौरान शक्ति ने अचानक उसके पिता पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बेटे के बयान पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इसी बीच 8 अक्तूबर को जितेंद्र यादव ने दम तोड़ दिया। इस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी करुणा सागर के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी जांच कर आरोपी शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने भुगतान को लेकर विवाद था।

रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या

नई दिल्ली। न्यू उस्मानपुर में बृहस्पतिवार देर रात एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव खजूरी चौक के पास खादर इलाके में मिला। शव की शिनाख्त दयालपुर निवासी गजेंद्र (34) के रूप में हुई है। वह मूलरूप से मेरठ के गांव अजराय का रहने वाला था। पुलिस को शुरुआती जांच में रंजिश की वजह से हत्या की आशंका है। पुलिस ने केस दर्ज कर कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि रात 11:27 बजे पुलिस को खादर में एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि उसकी चाकू गोदकर हत्या की गई है लेकिन मौका मुआयना के दौरान वहां पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। आशंका है कि युवक की कहीं दूसरी जगह पर हत्या करने के बाद शव को वहां फेंका गया है। ब्यूरो

मुठभेड़ में वांछित बदमाश के पैर में लगी गोली

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। बवाना में बृहस्पतिवार देर रात बाहरी-उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ और वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

गिरफ्तार बदमाश की पहचान आफताब आलम के रूप में हुई है। उसपर लूट, झपटमारी और हत्या के मामले दर्ज हैं। 2024 में जेल से छूटने के बाद से वह फिर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि बदमाश के बारे में बृहस्पतिवार देर रात सूचना मिली।

स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद कुमार झा को सूचना मिली कि आफताब आलम काले रंग की स्कूटी पर वारदात को अंजाम देने के लिए बवाना में घूम रहा है। जानकारी मिलते ही स्पेशल स्टाफ की टीम बदमाश की तलाश में जुट गई।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बवाना जी ब्लाक के पास पुलिस ने काले रंग की स्कूटी पर पर एक व्यक्ति को आते देखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। टीम को देखते ही उसने भागने की कोशिश की और भागते हुए पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन राउंड फायरिंग की। एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी।

उसके बाद पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। उसकी पहचान आफताब आलम उर्फ अत्ती के रूप में हुई। वह बवाना स्थित जेजे कॉलोनी में रहता है।

बवाना में हुई मुठभेड़ बदमाश पर दर्ज हैं हत्या के दस मुकदमे

चाकू और ईंट से सिर पर वार कर की थी हत्या

जांच में पता चला कि आफताब ने 2024 में बवाना जेजे कॉलोनी में धीरज नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी ने पहले धीरज का सिर ईंट से कुचला और फिर उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा वह झपटमारी करता था। झपटमारी और लूटपाट का विरोध करने पर वह पीड़ित को चाकू मारने से परहेज नहीं करता था। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर आपराधिक वारदातों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है।

लग्जरी कारें चुराने वाले शरद पांडे गिरोह का भंडाफोड़

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी कारों को चुराने वाले शरद पांडे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान शरद पांडे, कपिल चितानिया, विजय फरमाना, सुमित वकील उर्फ विक्की और चंद्रशेखर गुप्ता उर्फ चंदू के रूप में हुई। गिरोह ने वर्ष 2015 से 2018 के बीच 100 से अधिक कारें चुराईं।

इन पांच आरोपियों के खिलाफ एमसीओसी एक्ट की कड़ी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं दो अन्य आरोपियों डेयर मादा यांगदा और यूसुफ अली को फरार घोषित किया गया है और उनके खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के लिए पीओ चार्जशीट दाखिल की गई है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, शरद पांडे बिंदापुर थाने का नामित अपराधी है। उसके खिलाफ 45 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसका गिरोह विशेष रूप से लग्जरी वाहनों की चोरी में शामिल था। चोरी की गई कारों को अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बेचा जाता था।

जांच में पाया गया कि गिरोह आर्थिक लाभ के लिए लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त था। गिरोह ने हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे संगीन अपराधों को भी अंजाम दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष एमसीओसी कोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, वर्ष 2015 से 2018 के बीच 100 से अधिक कारें चुराईं

गुरु तेग बहादुर के शहीदी वर्ष के संबंध में तैयारी तेज की

नई दिल्ली। डीएसजीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी से भेंट की। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी वर्ष पर इस दिवस को मिलकर भव्य स्तर पर मनाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर कालका और काहलों ने एडवोकेट धामी से अपील की कि शिरोमणि कमेटी को इस ऐतिहासिक दिवस के आयोजन में दिल्ली कमेटी को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में उन स्थानों पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित हैं। उन्होंने बताया कि 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किला मैदान में भव्य समागमों का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो

हत्या और डकैती में वांछित पारदी गिरोह का बदमाश धरा

दिल्ली पुलिस ने एमपी के वांछित आरोपी को पंजाब से किया गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अपराध शाखा ने मध्यप्रदेश के गुना में हत्या और डकैती सहित पांच जघन्य मामलों में वांछित पारदी गिरोह के बदमाश मोहन पारदी को लुधियाना, पंजाब से गिरफ्तार किया है।

एमपी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 12,000 रुपये का इनाम रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि पिछले दो साल में पारदी गिरोह के किसी सदस्य की यह पहली गिरफ्तारी है। आरोपी 2024 से फरार था। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि आरोपी एमपी गुना के कुख्यात पारदी गिरोह का सदस्य है, जो घरों में हत्या के साथ डकैती और सेंधमारी के लिए जाना जाता है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के नेबसराय में 17 सितंबर की रात को घर में सेंधमारी की एक घटना हुई थी।

जांच में पारदी गिरोह की संलिप्तता पाई गई। एसीपी राजपाल डबास व इंस्पेक्टर गौतम मलिक की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। इस टीम को लुधियाना, पंजाब में पारदी गिरोह की मौजूदगी के बारे में एक सूचना मिली। टीम के सदस्य एसआई कुलदीप और हवलदार रविंदर ने लुधियाना में आरोपी पारदी गिरोह के सदस्य का पता लगा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद, उसे दिल्ली लाया गया और पूछताछ की गई। बाद में उसे गुना पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी ने खुलासा किया कि वह गुना के आसपास रहने वाले संगठित गिरोह में शामिल है।

गिरोह में आदिवासी बदमाश हैं और घरों में डकैती, हत्या और चोरी आदि की वारदातों को अंजाम देते हैं। उनके पूर्वज भी यही करते थे। ये दो से पांच परिवारों के समूह में घूमते थे और विभिन्न शहरों और कस्बों में सड़क किनारे डेरा यानी कपड़े, तंबू और प्लास्टिक का अस्थायी ठिकाना बनाकर रहने लगते थे।

एमपी पुलिस ने गिरफ्तारी पर 12,000 रुपये का रखा था इनाम

मालिक के 18 लाख रुपये लेकर भागा कर्मचारी धरा

पैसे लेने के बाद फोन बंद कर भाग गया था आरोपी

नई दिल्ली। मोती नगर थाना पुलिस ने मालिक के 18 लाख रुपये लेकर भागे एक कर्मचारी को हर्ष विहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप सिंह के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 17.65 लाख रुपए बरामद कर लिए गए है। मालिक ने कर्मचारी को पैसे अपने भाई को देने के लिए अशोक विहार भेजा था। आरोपी पैसे लेने के बाद फोन बंद कर भाग गया था।

पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त दराडे शरद भास्कर ने बताया कि 6 अक्तूबर को गुरुग्राम फेज एक निवासी अजय सतीजा ने मोती नगर थाने में अपने कर्मचारी संदीप के पैसे लेकर भागने की शिकायत दी। अजय सतीजा का रामा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल का कारोबार है। संदीप नाम का कर्मचारी उनकी कंपनी में पिछले 15 साल से काम कर रहा था।

3 अक्तूबर को उसने संदीप को 18.25 लाख रुपये देकर अशोक विहार में रहने वाले भाई को देने के लिए भेजा लेकिन वह पैसे लेकर वहां नहीं पहुंचा। संपर्क करने पर उसका फोन बंद मिला। काफी तलाश के बाद उसके नहीं मिलने पर पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर अमानत में ख्यानत का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और उसे दबोच लिया।

थाना प्रभारी वरुण दलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी मूलतः यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने एक टीम को फिरोजाबाद के लिए रवाना किया। जहां स्थानीय स्तर पर जांच करने पर पता चला कि आरोपी दिल्ली के हर्ष विहार में रहता है।

सूचना पर पुलिस ने दूसरी टीम को हर्ष विहार में भेजा। तलाश के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी हर्ष विहार के गगन सिनेमा के पास देखा गया है। पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने निशानदेही पर उसके घर से 17.65 लाख रुपए बरामद कर लिए। ब्यूरो

अंतरराज्यीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का खुलासा

दो गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 80 लाख रुपये की दो किलोग्राम मलाना क्रीम बरामद

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। अपराध शाखा ने अंतरराज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए गिरोह के दो बदमाशों सागर सेजवाल और मनोज सनसनवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2.070 किलोग्राम चरस (मलाना क्रीम) बरामद की गई है।

आरोपियों के कब्जे से इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद

बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख रुपये आंकी जा रही है। आरोपियों के कब्जे से चरस छिपाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई एक टाटा नेक्सन कार भी बरामद की गई।

आरोपी सागर सेजवाल पर पहले से हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं, नरेंद्र संसनवाल जाफरपुर कलां थाना में जबरन वसूली के एक मामले में संलिप्त रहा है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह मुख्य रूप से कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और आईआईटी दिल्ली के छात्रों को चरस की सप्लाई करते थे। अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव के अनुसार इंस्पेक्टर मंगेश त्यागी और रॉबिन त्यागी की टीम को 8 अक्तूबर को एक गुप्त सूचना मिली कि एक अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल के दो बदमाश सागर सेजवाल और मनोज संसनवाल दिल्ली में चरस की आपूर्ति का कारोबार करते हैं। ये चरस की आपूर्ति के लिए दिल्ली आएंगे।

इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी की टीम ने सिंघु बॉर्डर, दिल्ली में घेराबंदी कर सागर सेजवाल और मनोज संसनवाल नामक आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आगामी त्योहारी सीजन और विभिन्न आयोजनों के कारण दिल्ली में चरस की भारी मांग है। आरोपियो क स्थानीय उपभोग और अंतरराज्यीय ड्रग सप्लायरों को चरस की आपूर्ति करनी थी।

जानलेवा हमले के आरोपियों को मुहैया कराए हथियार, धरा

नई दिल्ली। हौजकाजी थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में जानलेवा हमला करने वालों को हथियार मुहैया कराने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नदीम उर्फ घोड़ा मुरादनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसपर उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में हत्या, डकैती, लूट, हत्या के प्रयास, दंगों और गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, मैगजीन और 6 कारतूस बरामद किए हैं।

जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन ने बताया कि 29 सितंबर को पुलिस को हौजकाजी में फैजुद्दीन पर जानलेवा हमला किए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायतकर्ता ने बताया कि अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी विवाद में उसपर हमला किया है। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसपर गोली चलाई। हालांकि गोली उसे नहीं लगी। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया।

स्पेशल स्टाफ ने जांच करते हुए वारदात में शामिल रमीस उर्फ रमीज को 2 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि मुरादनगर थाने के हिस्ट्रीशीटर सीलमपुर के गौतमपुरी निवासी नदीम ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल मुहैया करवाई थी। थाना प्रभारी ईश्वर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नदीम को 5 अक्तूबर को गौतमपुरी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

गिरफ्तार बदमाश मुरादनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर

स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने कुचला, मां की मौत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सराय रोहिल्ला में स्कूटी से जा रहे मां-बेटे को एक ट्रक ने कुचल दिया। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान मोनिका के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत भाग गया था।

उत्तरी जिला डीसीपी राजा बाठियां ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह 11:35 बजे पुलिस को गुलाबी बाग गुरुद्वारा के पास सड़क हादसा होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 45 साल की महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी थी जबकि उसका 17 साल के बेटे को मामूली चोट लगी थी। पुलिस ने तुरंत उन्हें पास में दीप चंद बंधु अस्पताल लेकर गई।

जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान प्रताप नगर निवासी मोनिका के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

चालक ट्रक समेत मौके से भाग गया, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

बेटे ने बताया कि वह प्रताप नगर का रहने वाला है। परिवार में भाई, बहन और मां थीं। उसके पिता का देहांत हो चुका है। उसकी मां प्रताप बाग में रेहड़ी पर टिक्की बेचती थी। वह और उसके भाई बहन मां की मदद करते थे। वह मां के साथ स्कूटी पर जा रहा था।

गुलाबी बाग गुरुद्वारा के सामने पहुंचा, तभी शास्त्री नगर की तरफ से एक ट्रक आया और पीछे से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उसकी मां और वह नीचे गिर गए। उसकी मां के सिर के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजर गया। घटना को अंजाम देकर चालक ट्रक समेत वहां से भाग गया। मृतका के बेटे के बयान पर सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर लिया है।

कैंपस डायरी

जेएनयू में आदिवासी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मांग

नई दिल्ली। जेएनयू में आदिवासी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र संघ के संयुक्त सचिव ने कुलगुरु को प्रस्ताव सौंपा है। संयुक्त सचिव वैभव मीणा ने कहा कि यह पहल समावेशी शैक्षणिक विकास के प्रति एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो देश की सांस्कृतिक व पारिस्थितिक पहचान में आदिवासी समुदायों के अमूल्य योगदान को मान्यता देती है। प्रस्तावित केंद्र आदिवासी विरासत, भाषाओं, नायकों, पारिस्थितिक ज्ञान और उन स्वदेशी परंपराओं के समग्र अध्ययन के लिए मंच की परिकल्पना करता है। यह प्रत्येक छात्र के लिए गर्व का क्षण है। एबीवीपी छात्रों के साथ है। छात्रों के लिए है। ब्यूरो

विश्वविद्यालय जीवन व्यक्तित्व निर्माण का स्वर्णकाल : मुरली मनोहर

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय जीवन व्यक्ति के चरित्र, दृष्टि और व्यक्तित्व के निर्माण का स्वर्णकाल होता है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की साधना है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो श्रद्धा, अनुशासन और जिज्ञासा के साथ अध्ययन करता है। यह बातें श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक ने कही। कार्यक्रम में कुलपति ने छात्रों से भारतीय परंपरा, संस्कृति और शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी के साथ जुड़ने की अपेक्षा भी जताई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक परिवेश से परिचित कराना और उन्हें उच्च शिक्षा के आदर्श मूल्यों से ओत-प्रोत करना था। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. आदित्य पंचोली ने किया। ब्यूरो

जेएनयू में परिषद प्रीमियर लीग का आगाज

नई दिल्ली। जेएनयू में एबीवीपी की ओर से शुक्रवार को परिषद प्रीमियर लीग 3.0 का साबरमती ग्राउंड में आगाज हुआ। टूर्नामेंट का आयोजन 12 अक्तूबर तक होगा। खेलो भारत जेएनयू संयोजक रविंद्र ने कहा कि परिषद प्रीमियर लीग जेएनयू के प्रमुख वार्षिक खेल आयोजनों में से एक है जो विश्वविद्यालय में खेल भावना, अनुशासन, टीमवर्क और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को सशक्त करता है। इस वर्ष प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों एवं छात्रावासों की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 16 टीमें भाग ले रहीं हैं। लीग केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह युवाओं में खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की भावना को सशक्त करने का प्रयास है। खेलो भारत जेएनयू सदैव इस विचार के साथ कार्यरत है कि मैदान पर पसीना बहाने वाला प्रत्येक युवा समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनता है। यह आयोजन एबीवीपी-जेएनयू और खेलो भारत जेएनयू के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। ब्यूरो

आईपी यूनिवर्सिटी में हुआ गोलमेज सम्मेलन

नई दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारका स्थित कैंपस में अनुसंधान व विकास, नवाचार, कौशल और साइबर सुरक्षा विषय पर एक विशेष राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें देशभर से करीब 60 कुलपति और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास प्रयासों, डिजिटल परिवर्तन और भविष्य के कौशल के महत्व और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही सम्मेलन में देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आर एंड डी अनुसंधान कोष के न्यायसंगत उपयोग के लिए एक मंथन सत्र भी आयोजित किया गया। ब्यूरो

फलस्तीन के लिए बनाई मानव श्रृंखला

नई दिल्ली। एसएफआई की जामिया इकाई ने अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर फलस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाई। एसएफआई के अनुसार सात अक्तूबर को इस्त्राइल आक्रमण के तहत गाजा में लगातार हिंसा और मानवीय पीड़ा के दो साल पूरे हो गए। एसएफआई का मानना है कि भविष्य में किसी भी युद्धविराम में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा बिना किसी दबाव के फलस्तीन की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाना चाहिए। फलस्तीन की जनता की मांगें और आकांक्षाएं किसी भी शांति प्रक्रिया के केंद्र में होनी चाहिए। हम न्याय और आत्मनिर्णय की जीत होने तक फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। ब्यूरो

डीम्ड-टू-बी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं

यूजीसी ने बंगलूरू के मामले के बाद छात्रों को चेताया, दाखिले से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता जांचें

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो टूक कहा कि डीम्ड-टू-बी और निजी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की डिग्री मान्य नहीं होगी। क्योंकि, यूजीसी ने निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों को अन्य कॉलेजों या संस्थानों को इस प्रकार से संबद्ध करने की अनुमति नहीं दी है।

यूजीसी ने छात्रों को चेताया है कि बंगलूरू स्थित एमवर्सिटी नामक संस्थान अपने संबद्ध केंद्रों के साथ मिलकर निजी और डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों के साथ फ्रेंचाइजिंग, सहयोग या समझौतों के माध्यम से डिग्री कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। जबकि उसे यह अनुमति प्रदान नहीं गई थी। इसलिए इस यहां से डिग्री लेने वाले सभी छात्रों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी।

यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी की ओर से सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त है, वे भी डिग्री प्रदान कर सकते हैं। लेकिन निजी विश्वविद्यालयों और डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों को अन्य कॉलेजों या संस्थानों को इस प्रकार से संबद्ध करने की अनुमति नहीं है कि वे डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम चला सकें।

इसलिए ऐसे किसी भी अनधिकृत केंद्रों या संबद्ध संस्थानों के माध्यम से प्रदान की गई डिग्रियां या योग्ताएं अवैध मानी जाएंगी। यह डिग्री और डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए मान्य नहीं होंगे।

निजी विवि यूजीसी की अनुमति के बिना ऑफ कैंपस नहीं खोल सकते

निजी विश्वविद्यालय यूजीसी की अनुमति के बिना ऑफ कैंपस, अध्ययन केंद्र या विस्तार केंद्र नहीं खोल सकते हैं। दरअसल, यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और मानकों के अनुरक्षण) विनियम, 2003 के तहत भारत में निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना ऑफ कैंपस केंद्र, अध्ययन केंद्र, या विस्तार केंद्र यहां तक कि उसी राज्य के भीतर भी कैंपस स्थापित करने की अनुमति नहीं है। निजी विश्वविद्यालय सिर्फ अपने मुख्य परिसर या मैन कैंपस से ही डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई करवा सकता है।

यूजीसी नेट उम्मीदवारों का सत्यापन आधार से होगा

10वीं के प्रमाणपत्र का भी लिया जाएगा सहारा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों में पीएचडी दाखिले, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए यूजीसी नेट दिसंबर-2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो ओपन हो चुकी है। उम्मीदवार सात नवंबर तक आवेदन भेज सकते हैं।

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन दिसंबर और जनवरी के बीच होगा। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का सत्यापन दसवीं कक्षा के सर्टिफिकेट और आधार नंबर से होगा।

एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर-2025 परीक्षा के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है कि इच्छुक उम्मीदवारों को सात नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजना होगा। उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा के सर्टिफिकेट में लिखी गई जन्मतिथि, नाम, माता-पिता का नाम का आधार कार्ड में दी गई जानकारियों से मिलान किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले अपने आधार कार्ड में यदि कोई बदलाव या अपडेट करना है तो पहले कर लें।

दिसंबर 2025 की परीक्षा के लिए 7 नवंबर तक भरें ऑनलाइन आवेदन पत्र

सांकेतिक

एसएससी परीक्षा में कुप्रबंधन पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा

अभ्यर्थियों ने सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग की

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की सीजीएल 2025 और अन्य परीक्षाओं में कुप्रबंधन, अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर शुक्रवार को एसएससी अभ्यर्थियों ने आयोग पर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता आयोजित कर छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने एसएससी पर परीक्षा की अखंडता से खिलवाड़ का आरोप लगाया। इस दौरान सभी हालिया परीक्षाओं को रद्द करने, छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और छात्र आयोग गठित करने जैसी प्रमुख मांगें रखीं।

पत्रकारों से बातचीत में छात्रों ने एसएससी सीजीएल 2025, स्टेनोग्राफर और सिलेक्शन फेज परीक्षाओं में सामने आई खामियों पर चर्चा की। इस दौरान 16 प्रमुख मुद्दों को चिन्हिच कर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, स्टेनोग्राफर परीक्षा में ग्लिच के बावजूद पुनः परीक्षा न घोषित करने, जयपुर के अभ्यर्थियों को मैसूर जैसे दूरस्थ केंद्र आवंटित करने जैसी मांगे रखीं।

साथ ही सिस्टम क्षमता से अधिक रोल नंबर जारी करने, निगरानी में चूक (वेबकैम बंद, सीसीटीवी आंशिक), पुनः परीक्षा मानदंडों की अस्पष्टता, फीडबैक बटन की अकुशलता, आधिकारिक एक्स हैंडल पर रिप्लाई ब्लॉक करने, समेत पुनः परीक्षा तिथि जैसे मुद्दों पर भी तीखे सवाल किए गए। विशेष रूप से पवन गंगा और लोटस लैब्स केंद्रों पर अभ्यर्थियों के साथ मारपीट और अवैध हिरासत की घटनाओं का जिक्र किया गया, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी पर गार्ड द्वारा हमला शामिल था।

प्रेस वार्ता आयोजित कर छात्र आयोग गठित करने की भी मांग की

तकनीकी खराबी नहीं सिस्टम की विफलता है

अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जहां सैकड़ों केंद्र आवासीय भवनों, बैंक्वेट हॉल और गैर-तकनीकी जगहों पर आयोजित किए गए। अभ्यर्थियों ने बिजली कटौती, खराब सिस्टम और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। अभ्यर्थी राम ने कहा कि ये मुद्दे तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता हैं, जो लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने एसएससी से सवाल किया कि पूर्व-परीक्षा ऑडिट क्यों नहीं हुए? यदि हुए तो ऐसी घटिया जगहों को मंजूरी क्यों दी गई? एडुक्विटी कैंरिअर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जैसे वेंडर पर केंद्र प्रबंधन के लिए क्या दंड लगाया गया? वहीं, अभ्यर्थी अभिषेक चौधरी ने गलत और अस्पष्ट प्रश्नों पर रोशनी डाली, जहां कई शिफ्टों में 15 से अधिक गलत या तकनीकी रूप से अमान्य प्रश्न आए। उन्होंने प्रश्न बैंक की पूर्व-जांच न होने और अप्रत्याशित वेंडर के चयन पर सवाल उठाए गए।

जेएनयू : स्कूल जीबीएम में हुआ हंगामा

नई दिल्ली। जेएनयू में स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) में हंगामा हो गया। यह हंगामा स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में हुआ। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर चुनाव समिति के गठन के लिए अलग-अलग स्कूल में जीबीएम आयोजित की जा रही है।

एबीवीपी समर्थित छात्र संघ की एससीएनएस संयोजक मनीषा डाबला ने छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार और सचिव मुंतेहा फातिमा पर हंगामे का आरोप लगाया है। इसमें उन्होंने अपमानजनक भाषा का उपयोग करने, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा के आरोप लगाए है। मनीषा ने कहा, छात्र संघ अध्यक्ष और सचिव ने अपनी अक्षमता और विफलता को छिपाने के लिए आम छात्रों और एक निर्वाचित पार्षद के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया है। इस हंगामे के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। वहीं, संयोजक रिपोर्ट भी पेश नहीं कर पाई।

आरोप पर जेएनयू सचिव मुंतेहा फातिमा ने कहा कि स्कूल जीबीएम के दौरान छात्र उनसे रिपोर्ट मांग रहे थे लेकिन उन्होंने खुद से रिपोर्ट पेश नहीं की बल्कि जीबीएम के एजेंडे की प्रति को फाड़ दिया। संयोजक की तरफ से जो आरोप लगाए गए है वह पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है। पहले उनकी तरफ से जीबीएम में शामिल होने का अनुरोध किया गया था। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए रिपोर्ट को पेश नहीं किया। ब्यूरो

General Knowledge : हर संवाद हर परीक्षा और बेहतर कॅरिअर की बुनियाद

Amar Ujala National Olympiad (AUNO) इसी क्षमता को निखारने का करता है प्रयास

अमर उजाला NATIONAL OLYMPIAD 2025-2026

नई दिल्ली। छात्र जब किसी समसामयिक विषय पर विचार स्पष्ट रूप से रख पाता है, तो वह एक मजबूत और प्रभावशाली छाप छोड़ता है। कई छात्र सामान्य ज्ञान को पर्याप्त महत्व नहीं देते और जरूरी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। आज के दौर में सामान्य ज्ञान केवल जानकारी जुटाने का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता का प्रतीक है। हर निर्णय, हर अवसर और हर संवाद इसी पर निर्भर करता है कि हम अपने समाज और घटनाओं को कितनी गहराई से समझते हैं।

अखबार पढ़ना, घटनाओं पर चर्चा करना, तकनीकी या सामाजिक बदलावों को समझना यही आदतें वास्तविक सामान्य ज्ञान को जन्म देती हैं। यह केवल परीक्षा की तैयारी नहीं, बल्कि एक सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने की शुरुआत है।

यही कारण है कि सामान्य ज्ञान हर बड़ी परीक्षा तंत्र और पेशेवर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, CUET, CLAT, NDA और राज्य सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका दायरा परीक्षा से कहीं आगे तक है। सामान्य ज्ञान व्यक्ति में तर्कशीलता, आत्मविश्वास और संवाद कौशल का विकास करता है। यह हमें न केवल अच्छे उत्तर देने में, बल्कि सही सवाल पूछने में सक्षम बनाता है। बच्चों में जब छोटी उम्र से अपने आसपास की दुनिया को समझने की जिज्ञासा पलती है, तो उनमें जिम्मेदारी, नेतृत्व और विचारशीलता जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। यही वह आधार है जिस पर सशक्त समाज खड़ा होता है।

Amar Ujala National Olympiad (AUNO) 2025 है इसका माध्यम : Amar Ujala का विश्वास है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि दृष्टिकोण विकसित करना है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए Amar Ujala National Olympiad (AUNO) 2025 में 'सामान्य ज्ञान' को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी तथ्यों से आगे बढ़कर सोचने की आदत विकसित कर सकें।

AUNO General Knowledge Olympiad के लाभ:

- **राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग जानने का मौका :** इसमें छात्र केवल स्कूल स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि देशभर में अपनी स्थिति जान पाएंगे।
- **नेतृत्व, तर्कशक्ति और जिम्मेदार नागरिकता की नींव :** सामान्य ज्ञान याद रखने का विषय नहीं, बल्कि दृष्टिकोण विकसित करता है।
- **व्यक्तिगत तैयारी डैशबोर्ड में हर छात्र को मिलेगा :** मुफ्त MCQ अभ्यास, मॉक टेस्ट से परीक्षा पैटर्न समझने में मदद।
- सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट से अपनी ताकत और कमजोरी समझने का मौका।

विषय सूची (कक्षा-वार)

- **कक्षा 3-5:** इंग्लिश, गणित, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग
- **कक्षा 6-10:** इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक और AI
- **कक्षा 11-12:** इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, टेक और AI

परीक्षा संरचना

- **लेवल 1 फेज 2 (स्कूल स्तर):** 16 दिसंबर – 23 दिसंबर 2025
- **लेवल 2 (राष्ट्रीय स्तर):** टॉप 20% चयनित छात्र
- **चयन प्रक्रिया:** लेवल 1 में शीर्ष 20% प्रदर्शन करने वाले छात्र लेवल 2 के लिए चुने जाएंगे

पुरस्कार

- **जिला स्तर:** मेडल + प्रमाण पत्र
- **राज्य स्तर:** नकद पुरस्कार + शील्ड + प्रमाण पत्र
- **राष्ट्रीय स्तर:** नकद पुरस्कार + ट्रॉफी + प्रमाण पत्र

संपर्क और आवेदन

हेल्पलाइन
1800-121-1166

पंजीकरण
amarujalaolympiad. com पर जाएं या QR को स्कैन करें।

कार्यालय नगर पालिका परिषद अनूपशहर (बुलन्दशहर)

पत्रांकः-582/न0पा0प0अ0/2025-26 | दिनांकः- 10.10.2025

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद अनूपशहर शासन से प्राप्त अनुदान/राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड की धनराशि से कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला के आयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य कराना चाहती है जिसके लिए क्र0सं0 01 से 07 तक के कार्यो के निविदा प्रपत्र दिनांक 17.10.2025 तक निर्धारित शुल्क जमा कराकर नगर पालिका परिषद अनूपशहर कार्यालय से क्रय किये जा सकते है, निविदा/कुटेशन दिनांक 17.10.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक डाली जायेगी जो दिनांक 17.10.2025 को सायं 4.00 बजे अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा खोली जायेगी। एक लाख रूपये से कम धनराशि के कराये जाने वाले कार्यो को करने के लिए भी जो भी व्यक्ति इच्छुक हो वे नगर पालिका परिषद अनूपशहर से कुटेशन प्रपत्र को क्रय करके दिनांक 17.10.2025 को समय दोपहर 2.00 बजे तक भरकर दे सकते है। अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पालिका परिषद अनूपशहर से की जा सकती है। उक्त कार्यो को दिनांक 29.10.2025 की दोपहर तक पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि 02 प्रतिशत	निविदा राशि 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित
1	अस्थाई प्रकाश व्यवस्था एवं सजावट कार्य	4,53,308.00	9,066.00	550.00
2	नाव/नाविक/गोताखोर (यदि आवश्यक हो तो)	4,03,305.00	8,066.00	500.00
3	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र व अन्य रास्तों पर गडढों को मिटटी भराव व कूडा निस्तारण हेतु ट्रैक्टर व ट्राली लगाया जाना	1,15,375.00	2,307.00	150.00
4	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में सफाई कर्मचारी (उपकरण सहित)	1,90,700.00	3,814.00	225.00
5	कार्तिक पूर्णिमा मेला क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 कैमरा व ड्रोन कैमरा की व्यवस्था	2,24,802.00	4,496.00	270.00
6	विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु पण्डाल, लाईट, साउण्ड की व्यवस्था	3,41,020.00	6,820.00	400.00
7	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में गंगा रेती में जंगल सफाई का कार्य	1,50,804.00	3,016.00	200.00

सार्वजनिक कुटेशन सूचना

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत जी0एस0टी0 सहित	कुटेशन प्रपत्र शुल्क
1	बोर्ड/बैनर/बैज की व्यवस्था	90,800.00	100.00
2	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था	82,600.00	100.00
3	अस्थाई शौचालय/यूरिनल की व्यवस्था	80,240.00	100.00
4	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में आवश्यकतानुसार गंगा जी के खादर व पहाडे में अस्थाई नल व गंगा जी की रेती में पुल के नीचे 02 समर लगाया जाना	91,568.00	
5	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वस्त्र बदलने हेत चेजिंग रूम बनवाया जाना	93,098.00	100.00
6	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई हेतु क्लीनिंग कैमिकल की आपूर्ति	70,564.00	100.00
7	कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आये कलाकारों को सम्मानित व पुरूस्कृत करने हेतु शील्ड आदि की व्यवस्था	19,824.00	100.00

शर्त

1. उक्त सभी निविदाओं/कुटेशनों के लिए आधार कार्ड, मो0नं0, जी0एस0टी0 पंजीकरण, पैन नम्बर लगाना अनिवार्य है।
2. जैनरेटर द्वारा प्रकाश व्यवस्था के लिए फर्म के नाम से सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा बुलन्दशहर से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि नकद/एफ0डी0आर0 जमा करनी अनिवार्य है तथा निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त 08 प्रतिशत की धरोहर धनराशि नकद/एफ0डी0आर0 जमा करनी अनिवार्य होगी।
4. निविदा/कुटेशन खोले जाने के समय निविदादाता/कुटेशनदाता चाहे तो उपस्थित रह सकते है।
5. नगर पालिका परिषद अनूपशहर को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क/कुटेशन राशि नकद जमा करना होगा।
6. अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में श्री राजकिशोर प्रकाश निरीक्षक से कर सकते है।

(गार्गी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद अनूपशहर,
बुलन्दशहर

(ब्रजेश गोयल)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद अनूपशहर
बुलन्दशहर

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
(आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के तत्वावधान के तहत
भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
9वां तल, 'बी' विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
फोन : 23717249/23355408/23322192, ई-मेल : cgewho@nic.in, वेबसाईट : www.cgewho.in

विभिन्न शहरों में हाऊसिंग प्रोजेक्ट हेतु मांग सर्वे

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सीजीईडब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 1990 में अपनी शुरुआत से भारतवर्ष में 34 आवास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सीजीईडब्ल्यूएचओ केंद्र सरकार, केंद्रीय पीएसयू'ज, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों, निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए अनन्य रूप से किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीजीईडब्ल्यूएचओ निम्न भूखंडों में अभिरुचि की अभिव्यक्ति दर्शायी है और मांग का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है ताकि यह संगठन संदर्भित शहरों में आवास परियोजनाओं को ले सके।

महत्वपूर्ण जानकारी :-

क्रम सं.	शहर का नाम	क्षेत्रफल	स्थान
1	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	11.04 एकड़	मध्यम ग्राम टीई, मौजा-उदयराजपुर, जे.एल. नं. 43, पीओ बड़सत, जिला नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
2	रायपुर छत्तीसगढ़	2.2 एकड़	विधानसभा रोड जैक एण्ड जिल स्कूल के समीप, खमारदीह, रायपुर छत्तीसगढ़।
3	पुड्डूचेरी	2.67 एकड़	बीएसएनएल स्टाफ क्वार्टर कंपाऊंड, जय नगर, रेड्डीयारपलायम, पुड्डूचेरी
4	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2.28 एकड़	विकास नगर सेक्टर-II, वार्ड लोहिया नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226022
5	लुधियाना, पंजाब	2.27 एकड़	बरेवाल रोड, लुधियाना, पंजाब 141012

- **पात्रता :** यह सर्वे केवल केंद्र सरकार, केंद्रीय पीएसयू'ज, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों, स्वायत्त निकायों, निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए खुला है।
- **आरक्षण :** निवास इकाइयों (डीयू'ज) में 50% आरक्षण मांग सर्वे के प्रतिवादियों के लिए आरक्षित होगा, जो सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमों के अनुसार प्राथमिकता आधार पर आवंटित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें :

- विस्तृत जानकारी, शर्तों व नियमों के लिए तथा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए सीजीईडब्ल्यूएचओ की वेबसाईट www.cgewho.in पर जाएं।
- संपूर्ण फार्म 30.11.2025 को या इससे पूर्व डाक या-ईमेल के द्वारा निम्न पते पर जमा करवाए जाने चाहिए :-

उप निदेशक (प्रशासन) सीजीईडब्ल्यूएचओ
'बी' विंग, 9वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
ईमेल : marketingcgewho@gmail.com

किसी भी पूछताछ हेतु निम्न व्यक्तियों को संपर्क करें :-
श्री रोशन किशोर (मो.) 9560022232, श्री नीतिश गर्ग (मो.) 8826461114
सीईओ-सीजीईडब्ल्यूएचओ बिना कोई कारण बतलाए मांग सर्वे या स्कीम को त्यागने का अधिकार रखता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीईडब्ल्यूएचओ

CBC 20105/12/0012/2526

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

शांति का नोबेल

मारिया कोरिना मचाडो को शांति क्षेत्र में नोबेल की घोषणा सुखद और अनुकरणीय है। यह ऐसी राजनीति का सम्मान है, जो सदैव शांति और लोकतंत्र के पक्ष में समर्पित रहती है। जिस दौर में अधिकतर सत्ताधारी नेता तानाशाही करने लगे हैं, उस दौर में मारिया जैसे कुछ स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता भी हैं, जो लोकतंत्र का झंडा बुलंद किए हुए हैं। यह वेनेजुएला में संघर्षरत लोकतंत्र का सम्मान है, इससे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को भी बल मिलेगा। विशेष रूप से अमन-चैन के पक्ष में महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। वेनेजुएला की 58 वर्षीय विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने शुक्रवार को जब नोबेल सम्मान की खबर सुनी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पूरा श्रेय स्वयं न लेते हुए कहा कि यह नोबेल शांति पुरस्कार पूरे आंदोलन और समाज की जीत है। विनम्र नेता ने यह भी कहा है कि वह इस पुरस्कार की हकदार नहीं हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति हैं। दरअसल, यह एक स्वाभाविक नेता की पहचान है कि वह अपने सम्मान का श्रेय समाज को देता है।

दूसरी ओर, नोबेल के लिए जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति लालायित थे, उससे पता चलता है कि वह कैसे नेताओं का दौर है। अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर मांग रहे थे कि उन्हें शांति का नोबेल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बीते महीनों में कथित रूप से करीब सात युद्धों को समाप्त कराया है। यह भी दर्ज करने लायक पहलू है कि ट्रंप के समर्थकों ने नोबेल न मिलने पर नाराजगी का भी इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में यहां तक कहा है कि नोबेल समिति ने शांति पर राजनीति को प्राथमिकता दी है। नोबेल की घोषणा से ठीक पहले इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और एक संभावित शांति समझौते के साथ इन अटकलों को बल मिला था कि ट्रंप को नोबेल मिल सकता है। रूस, इजरायल, पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, थाईलैंड और कंबोडिया सहित कई देशों ने ट्रंप का पक्ष लिया था। खुद ट्रंप भी हर संभव जगह संपर्क साधते हुए नोबेल पाना चाहते थे, पर नोबेल समिति के निर्णय ने तमाम प्रयासों पर पानी फेर दिया। ध्यान रहे, इस वर्ष 338 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल थे। यह बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में इतने लोग और संगठन शांति प्रयासों में लगे हैं, उनके प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। ट्रंप के प्रयासों में भी तेजी आनी चाहिए और जरूरी ईमानदारी भी। विशेषकर उन्हें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे आतंकी-पोषक देश की निगाह में शांति दूत होना वास्तव में खुद को धोखा देने के समान है।

मारिया कोरिना को मिला नोबेल सम्मान मात्र सांकेतिक नहीं रहना चाहिए। अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की उनकी यात्रा यहीं थमनी नहीं चाहिए।

बहरहाल, मारिया कोरिना को मिला सम्मान मात्र सांकेतिक नहीं रहना चाहिए। अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की उनकी यात्रा यहीं थमनी नहीं चाहिए। हमने अतीत में देखा है, अनेक सम्मानित हस्तियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। अपने पड़ोस में ही अगर देखें, तो नोबेल सम्मानित आंग सान सू की म्यांमार में रोहिंग्याओं के संहार के समर्थन में नजर आई थीं। नोबेल सम्मानित मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए। मलाला यूसुफजई अपने ही देश पाकिस्तान में आजादी से रह नहीं सकतीं और विदेश में रहने को मजबूर हैं। नोबेल का सम्मान तो तब है, जो नोबेल पाने वाला हकीकत में अपनी जमीन पर अपनी सार्थकता सिद्ध करे। मारिया कोरिना से ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए कि तानाशाही के खिलाफ उनके स्वप्न साकार हों और उनकी सफलता का प्रकाश तमाम देशों तक पहुंचे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
11 अक्तूबर, 1950

बम्बई की हड़ताल

समाजवादियों द्वारा प्रेरित बम्बई के मिल-मजदूरों की हड़ताल को, जो 14 अगस्त को शुरू हुई थी, दो मास पूरे होने को आये। इस बीच देश का कितना नुकसान हुआ, इसका आभास हड़ताल के 57वें दिन प्रकट किये गये कुछ अंकों से मिलता है। इनके अनुसार लगभग दो लाख मजदूर हड़ताल से प्रभावित हुए हैं और इक्कीस करोड़ से अधिक गज कपड़े का बनना रह गया है, यानी उतने कपड़े की हानि हुई है। अठारह करोड़ काम के घण्टे बरबाद गये हैं और मजदूरी या तनखाह के रूप में पैंतीस करोड़ रुपये मजदूरों ने गंवाया है। यह तो हुई आर्थिक हानि, इसके अलावा उपद्रवों और दमन की कहानी अलग दुखदायी है। पुलिस व हड़तालियों के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं, जिनके कारण अश्रु गैस के अलावा पुलिस को चार बार लाठी प्रहार और तीन बार गोली प्रहार भी करना पड़ा। सभा-जलूसों पर प्रतिबंध और प्रतिबंध-भंग की स्थिति भी है। यह सब उस समय है, जब देश में शान्ति-व्यवस्था और उत्पादन- वृद्धि की आवश्यकता असंदिग्ध है और सभी पक्ष वाले इन पर जोर देते रहते हैं।

हड़ताल का कारण मजदूरों को मिलने वाला बोनस है। मालिक-मजदूरों के बीच किसी प्रश्न पर झगड़ा हो, तो उसे औद्योगिक अदालत द्वारा तय कराने का कानून बम्बई राज्य में है। झगड़ा इस बात पर उठा कि मजदूरों को बोनस कितना मिलना चाहिए और जिन मिलों को घाटा या नुकसान हुआ है, उन्हें भी क्या बोनस देना चाहिए? आपस में जब फैसला नहीं हुआ, तो मामला औद्योगिक अदालत में गया और उसने दो महीने के बोनस का निर्णय दिया। मजदूरों को यह निर्णय इसलिए पसन्द नहीं हुआ कि वे तीन महीने का बोनस चाहते थे और उसे देने में भेदभाव करने के पक्ष में नहीं थे, मालिकों को लगा कि जितना लाभ उन्हें हुआ है, उसके हिसाब से वह अधिक है और जिन मिलों में लाभ नहीं है या कोई क्षति हो गई है, उनमें तो वह दिया ही नहीं जाना चाहिए। फलतः दोनों ओर से औद्योगिक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपीलें हुईं, लेकिन चूंकि अपील-अदालत का निर्माण ही विलम्ब के बाद अगस्त में हुआ इसलिए उसमें देरी हुई। जबकि मामला अपील-अदालत के विचाराधीन था, समाजवादियों के श्रम-संगठन ने मजदूरों को उकसाने का अनुकूल अवसर देखा और हड़ताल कराने के रूप में अपनी शक्ति का परिचय दिया।

फलस्तीन में शांति के लिए हमास और इजरायल फिर राजी हो गए हैं। इसकी खुशी पूरी दुनिया में है, पर यह विवाद बहुत पुराना है। रह-रहकर संघर्ष छिड़ता रहा है। एक समय था, जब भारतीय सैनिक भी संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास में तैनात थे। तब भी भारत में इस समस्या और इसमें भारत की भूमिका की खूब चर्चा होती थी। कैसा था वह दौर? पेश है, 6 जून, 1967 को लोकसभा में हुई एक रोचक बहस...

आमने-सामने

पश्चिमी एशिया में युद्ध को रोकना जरूरी

यहां स्कैन करें

इंदिरा गांधी | तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत

- इजरायल ने इस सशस्त्र झगड़े को पूरी लड़ाई में बदल दिया है।
- गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह कभी नहीं रहा कि हमें तटस्थ रहना चाहिए।
- हमने वहां भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से दूर हटाने का अनुरोध किया है।

लगभग दो सप्ताह हुए मेरे सहयोगी वैदेशिक कार्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया और पश्चिमी एशिया की भयंकर स्थिति के बारे में सरकार का मत व्यक्त किया। उसके बाद से सुरक्षा परिषद तथा उससे बाहर हमारा प्रयत्न यहां तनाव को कम करने तथा शांति बनाए रखने में रहा है। हमारे प्रतिनिधि के प्रयत्नों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई और यह आशा जगी कि सुरक्षा परिषद की अगली बैठक में इस मामले में काफी प्रगति हो जाएगी।

अभी ऐसे प्रयास जारी थे कि कल इजरायल तथा संयुक्त अरब गणराज्य और अन्य अरब देशों के बीच संघर्ष के समाचार मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सुरक्षा परिषद की आपात कालीन बैठक में सारा ब्यौरा दिया और यह भी बताया कि इजरायली वायुयानों ने संयुक्त अरब गणराज्य तथा सीरिया के क्षेत्रों पर आक्रमण किया।

मैं कठोर शब्द नहीं प्रयोग करना चाहती, परंतु जो सूचना मिली है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें कुछ संदेह नहीं है कि इजरायल ने इस सशस्त्र झगड़े को पूरी लड़ाई में बदल दिया है। संसार को पश्चिमी एशिया में एक भयानक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां इजरायल तथा अरब सेना एक-दूसरे के खिलाफ हैं और यदि यह लड़ाई रोकी नहीं गई, तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। हमारे अपने राष्ट्रीय हित भी पश्चिमी एशिया की मजबूती से जुड़े हैं। हम सबका कर्तव्य है कि इस खतरनाक स्थिति में पुनः शांति स्थापित की जाए।

सुरक्षा परिषद में हमारा यह पूरा प्रयास है कि सारी सशस्त्र सेनाएं 4 जून के स्थानों पर आ जाएं। यहां सदस्यों ने इजरायली तोपखाने द्वारा अकारण गाजा स्थित संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के भारतीय सैनिकों की मृत्यु के समाचार पढ़े होंगे। यह आक्रमण जान-बूझकर किया गया तथा बिना उत्तेजना के किया गया, क्योंकि हमारे दल पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निशान थे। इस संबंध में मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक पत्र भेजा है, जिसमें इन घटनाओं पर अपना दुःख तथा रोष प्रकट किया है और कहा है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा तथा लड़ाई क्षेत्र से शीघ्र बाहर निकालने के बारे में कारगर कदम उठाए जाएं।

सरकार उन पांच सिपाहियों (या सैनिकों) के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देगी, जिन्होंने पश्चिम एशिया में अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह रकम उससे कम नहीं होगी, जो उनके परिवारों को उस समय मिलती, यदि वह किसी युद्ध में मारे जाते। इसी बीच में प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये तात्कालिक सहायता के रूप में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहायता निधि से भेज रही हूं। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन शांति- सिपाहियों पर जो आक्रमण किए गए, उसकी भर्त्सना करेगा। महासचिव ने इजरायल सरकार से कड़ा विरोध जताया है। सारे सदन की ओर से मैं इन दुःखी परिवारों को सहानुभूति संदेश भेजना चाहती हूं कि उन बहादुरों ने मानवता तथा शांति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ...

जहां तक भारत में अनाज लाने का संबंध है, स्वेज नहर बंद होने से विलंब तथा कठिनाई होगी, परंतु इससे चावल के संभरण पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। ... अनाज लाने में विलंब हो जाएगा, क्योंकि स्पेन के जहाजों को बहुत घूमकर आना पड़ रहा है। इस संघर्ष का गेहूं तथा मक्के के आयात पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहां सदन में इजरायल की तबाही का बहुत उल्लेख किया गया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम किसी भी राष्ट्र के विनाश के पक्ष में नहीं हैं। ...

अब भारत लगभग 20 वर्षों से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में है। हमने दुनिया में अपनी पहचान सावधानी से नहीं बनाई है। हमने न्याय और शांति के मामले में दृढ़ रुख अपनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह कभी नहीं रहा कि हमें तटस्थ रहना चाहिए। वास्तव में, दुनिया के सभी मंचों पर हमने गुटनिरपेक्षता की परिभाषा के रूप में 'तटस्थ' शब्द के प्रयोग की निंदा की है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। कोई भी विचारशील व्यक्ति, जो दुनिया में हो रहा है, उससे अछूता नहीं रह सकता। इससे हम भी अछूते नहीं रह सकते। जब हम स्वतंत्र नहीं थे, जब हम अन्य राष्ट्रों की मदद करने की स्थिति में नहीं थे, तब भी हमने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ... मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण पूरी स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप स्वयं यहां थे, आपने दूसरे पक्ष के भाषण सुने हैं और आपने देखा है कि उन्होंने एक स्वर में बात नहीं की है। इसलिए, वे यह नहीं कह सकते कि यह विभाजित राष्ट्र की आवाज है। मेरा मानना है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को राष्ट्र का पूरा समर्थन प्राप्त था। इसने निश्चित रूप से हमें विश्व में एक स्थान दिलाया है। इसने हमें कई परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने और उस तरह से शांति स्थापित करने में सक्षम बनाया है, जैसा मुझे लगता है कि कोई अन्य राष्ट्र नहीं कर पाया है। विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ भी कहें, ये इतिहास के तथ्य अब नहीं बदल सकते।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसमें भाग लेने वाले सात देशों में हुए समझौते के अनुसार, गाजा में तैनात किए गए भारतीय सैनिकों की वापसी का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर था। महासचिव के साथ तय हुआ था कि वहां से हटाए गए सैनिकों की वापसी के लिए एक विमान 8 जून को भेजा जाएगा। भारत अपने सैनिकों को पहले ही वापस बुलाने के लिए उत्सुक था, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी विमान द्वारा वापसी में सहमत होने में असमर्थता व्यक्त की। मैंने एक बार फिर महासचिव को भेजे गए अपने संदेश में भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से दूर हटाने का अनुरोध किया है। यदि वे भारत नहीं आ सकते, तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से यथाशीघ्र हटाया जा सकता है। ... मुझे आशा है कि हम अपना प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित कराने में सफल होंगे। हम किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करेंगे, जिससे युद्ध बंद हो और शांति स्थापित हो सके।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

अरब में अमन के लिए हम क्या कर रहे हैं?

यहां स्कैन करें

राम मनोहर लोहिया | वरिष्ठ राजनेता व सांसद

- एक तरफ, पांच करोड़ अरब हैं और दूसरी तरफ, 15 लाख इजरायली।
- सरकार शरीर के हिसाब से अमेरिका की हो गई है और मन के हिसाब से रूस की।
- गाजा से हमारे सैनिक आखिर क्यों भागें? उन्हें लड़ाई में भी साथ रहना चाहिए।

महोदय, सुबह मैंने सोचा था कि आज जिंदगी के उन कम मौकों में से एक दिन होगा, जब भारत सरकार के किसी काम की तारीफ करूंगा। तारीफ कर रहा हूं, जो कुछ सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि ने किया- उसके लिए, लेकिन जो भारत सरकार ने यहां किया, उसकी मैं निंदा करता हूं। मालूम होता है कि भारत सरकार एक ऐसी मूर्ति की तरह है, जिसके एक तरफ आप मुरुगन (गणेश के बड़े भाई) को देख सकते हो, सुंदर मूर्ति है और दूसरी तरफ, भैरव या काली को देखते हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है। यह कहने से पहले मैं इतनी बात जरूर हिन्दुस्तान की तरफ से कह देना चाहता हूं कि नासिर साहब अफ्रेशिया के राजनीतिज्ञों में बहुत आगे और अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक कर्म से यह करके दिखाया है- स्वेज के राष्ट्रीयकरण से- कि अफ्रीका और एशिया में राजनीतिज्ञ कैसे होने चाहिए। ...लेकिन मालूम होता है कि यह सफलता जरा उनके सिर पर ज्यादा चढ़ गई है।

उधर दूसरी तरफ, मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि इजरायल के खत्म होने की बात अक्सर कही जाती है। इजरायल खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बहस को नहीं छेड़ना चाहता। दुनिया में क्या-क्या चीजें खत्म हो गईं और वह बेचारा तो 20 लाख का है, खत्म हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना, अक्सर कहा जाता है कि कोई राष्ट्र आखिरी दम तक लड़ा, इतिहास में ऐसे राष्ट्र कभी हुए नहीं, शायद इजरायल भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 18-20 वर्ष के बच्चे, जिनसे मैंने पूछा- एक तरफ, पांच करोड़ अरब हैं और दूसरी तरफ, तुम 15 लाख आदमी हो, यह मैं 1949 की बात कर रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया, मुस्कराते हुए, उन्होंने आस्तीनें नहीं चढ़ाईं, बहुत गंभीरता से कहा, क्या करें, कहां जाएं? इस यहूदी कौम को हिटलर और आइचमैन का अनुभव हो चुका है, 50 लाख को गैस चैंबर के अंदर बंदकर मार डाला गया...।

लंबा किस्सा है। मैंने एक बार कोशिश की थी, जब मैं जवान था कि इजरायल और मिस्र की दोस्ती कराई जाए, पर जो आज बैठे हैं, इनके पूर्वजों ने इसे पसंद नहीं किया था, खैर जाने दीजिए। उस वक्त भी इजरायल ने कुछ घमंड दिखाया था, कुछ चीजें जो मुझे आजम पाशा ने बताई थीं, उससे कुछ बात बढ़ सकती थी। खैर, जैसा नासिर साहब के लिए मैंने अभी कहा, उसी तरह से इजरायल के राजनीतिज्ञों के लिए भी कहना चाहता हूं। उनको भी अपने बारे में कुछ घमंड हो गया है कि हम आखिरी सिपाही तक लड़कर मर सकते हैं, यह घमंड कम होना चाहिए।

अब भारत में यह जो सरकार है, वह क्यों दो मूर्तियां रखती है- एक तरफ मुरुगन और दूसरी तरफ काली। एक तरफ, सुरक्षा परिषद प्रतिनिधि और दूसरी तरफ, भारत सरकार का यह बयान। इसका सबब यह मालूम होता है कि यह सरकार शरीर के हिसाब से अमेरिका की हो गई है और मन के हिसाब से रूस की ओर। जब शरीर और मन अलग-अलग हो जाया करते हैं, तब शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः सुरक्षा परिषद में भारत ने जो काम किया, वह कुछ थोड़ा-बहुत नजदीक था शरीर के और यहां यह अपने मन की बात कर रहे हैं, यह कमी दूर होनी चाहिए। भारत सरकार को आत्मसम्मान के साथ अपनी एक नीति ऐसी बनानी चाहिए, जिससे न सिर्फ अरब और इजरायल, बल्कि ऐसे जितने इलाके हैं, जिनको साम्राज्यवादियों ने तोड़ा है, उनको जोड़ा जाए।

अक्सर यहां पर जिक्र किया जाता है, मैं डांगे साहब से बहस नहीं करना चाहता, वह एक मायने में मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनसे कहूंगा कि साम्राज्यशाहियों द्वारा ही इजरायल नहीं बना था, बल्कि रूस ने भी इजरायल को बनाया था और इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि ये जॉर्डन या इराक या सऊदी अरेबिया, ये सब साम्राज्यशाहियों के बनाए हुए हैं, वे लड़ा सकते हैं। अमेरिका और रूस आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे हम सब अश्वेतों का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद अपने को उन अश्वेतों में शामिल नहीं रखती हैं।

आखिर में येरूशलम के बारे में जो पोप साहब की अपील है, उसके बारे में कह देना चाहता हूं। पोप साहब ने चाहा है कि येरूशलम का किसी तरह से बहुत नाश न हो। इस शहर का नाम है येरूशलम- शांति का शहर, लेकिन दुनिया का और कोई शहर नहीं है, जहां इतने युद्ध, इतना घमासान, इतना सत्यानाश हुआ हो। यह शहर है, जहां से इतने धर्म निकले हैं। मैं पोप साहब से अपील करना चाहता हूं, जरा वह कभी बैठें, सोचें इस बात पर, धर्म में वह कौन-सा गुण या अवगुण है, जो लोगों को आपस में इतना ज्यादा लड़ाया करता है। शायद उनके सोचने से हमें फायदा हो जाए। मैं पोप साहब की अपील पर जोर डालना चाहता हूं और चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से अगर येरूशलम को खुला शहर घोषित करने की प्रतिक्रिया प्रकट कर दी जाती, तो बड़ा अच्छा होता।

हर हालत में जो कुछ सुरक्षा परिषद में किया गया है, वह यह है कि फिजूल के झगड़े में मत पड़ो। हो सकता है कि इजरायल झगड़ा कर रहा हो, हो सकता है कि अरब लोग कर रहे हों। ऐसे मौके पर यदि किसी ने पहली गोली चला दी, तो यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन एक बात याद रखिए - कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आज के मौके पर यह फैसला नहीं करना चाहिए कि कौन आक्रमणकारी है। आज के मौके पर यह फैसला करना चाहिए, जैसा कि अक्सर कर चुके हैं कि अरब और इजरायल, दोनों के बीच में युद्ध-विराम हो, गोली चलना बंद हो। वह 4 जून वाली बात मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, लेकिन मैं अपने संदेह को इस वक्त नहीं बताऊंगा। इस वक्त यही कहे देता हूं कि 4 जून वाली बात हो जाए और कुछ शांति के लिए शुरुआत कर दी जाए। ...

अभी प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के नाम को तबाह कर रही हैं। ... इधर के झगड़े देखकर प्रधानमंत्री जी खुश हो रही हैं। ...थोड़ा झगड़ा और हो, तो और खुश होंगी। ... गाजा से हमारे सैनिक आखिर क्यों भागें? वहां उन्हें लड़ाई में भी साथ रहना चाहिए...।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

मनसा वाचा कर्मणा

निष्ठा की आवश्यकता

निष्ठा एक परिपक्व और एकत्रित मन की अभिव्यक्ति है। यह चेतना की अखंड पूर्णता को इंगित करती है और मन की संपन्नता को दर्शाती है। जब मन एकत्रित नहीं होता, तब वह व्यग्र, निष्ठाहीन और अवसरवादी होता है। अनिष्ठा अवसरवादिता से आती है, जो अपने ही भाग्य के प्रति अदूरदर्शिता व्यक्त करता है। स्वास्थ्य के लिए समग्रता और संपूर्णता आवश्यक है। एक विभाजित मन धीरे-धीरे दिमागी बीमारी की ओर ले जाता है और शारीरिक व मानसिक विकार लाता है। निष्ठा ही सच्चा बल है और आखिरकार सृष्टि भी इसी का साथ देती है।

भय और महत्वाकांक्षा निष्ठा के लिए बाधक हैं। निष्ठा की आवश्यकता दोनों स्तरों पर है- भौतिक और आध्यात्मिक। किसी भी संस्था, वर्ग या समाज के निर्माण या संरक्षण के लिए निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रतिबद्धता को सम्मान देना निष्ठा है। यह तुम्हें राग और द्वेष के द्वंद्व से परे ले जाती है। जिम्मेदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता निष्ठा के अंग हैं। एक निष्ठावान मन 'हां' मन है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है उत्तर पाना। सभी उत्तरों का उद्देश्य है 'हां' की स्थिति लाना। 'हां' ज्ञान की स्वीकृति है। हां मन शांत और प्रसन्न मन है। 'नहीं' मन विचलित, संदेहशील और दुखी मन है। निष्ठा हां मन से शुरू होती है और नहीं मन से खत्म होने लगती है।

आध्यात्मिकता में निष्ठा का स्थान प्रथम है, फिर ज्ञान होता है। जैसे, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योगासन और ध्यान। इनमें पहले तुम्हें विश्वास होता है, फिर ज्ञान होता है। यदि तुम पूर्ण निष्ठा से प्राणायाम करते हो, तो तुम्हें प्राण शक्ति का ज्ञान होता है; यदि तुम विश्वास के साथ ध्यान करो, तो चेतना का ज्ञान होता है। निष्ठा से अनपढ़ को भी गहन ज्ञान की प्राप्ति होती है।

श्री श्री रविशंकर

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

गाजा में युद्ध-विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता इजरायलियों व फलस्तीनियों, दोनों के लिए राहत की एक किरण है। इस किरण को अब शांति की सुबह बनाई जानी चाहिए।

अनुलोम-विलोम
दलित उत्पीड़न

आज भी न्याय की बाट जोह रहे दलित

आत्महत्या करने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता, ऐसा कानून भी मानता है। समय-समय पर ऐसे मामले न्यायपालिका के सामने भी आए और आत्महत्याओं व दहेज उत्पीड़न के मामलों में न्यायपालिका ने निर्णय भी दिए हैं। इसलिए, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले की गहन जांच और कार्रवाई होनी चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके उचित ही रिपोर्ट तलब की है। खुदकुशी करने से पहले अनुसूचित जाति के इस अधिकारी ने सुसाइड नोट में जिन-जिन का नाम दर्ज किया है, उन सबसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। इस अधिकारी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। अगर हम पिछले कुछ मामलों का गहराई से अध्ययन करें, तो पाएंगे कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत आज भी अनेक पीड़ित परिवार न्याय के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। अनुसूचित जाति के मामले में तो जांच और कार्रवाई की स्थिति और भी बदतर है। इनकी तो रिपोर्ट ही अक्सर नहीं लिखी जाती है। सरकार को इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार के मामलों में केवल लीपापोती होती है।

मीना धानिया, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय दलित संगठन परिसंघ की बिहार चुनावों के पहले जारी रिपोर्ट बताती है कि राज्य के दलित शिक्षा, नौकरी और जमीन के मामले में पिछड़ गए हैं। हालांकि, कांग्रेस, राजद और बाद में जदयू के रूप में दलितों के हितों का समर्थन करने वाली पार्टियां राज्य की सत्ता में बनी हुई हैं, मगर ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर पड़े इस समुदाय को इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 'लोजपा' और 'हम' जैसी जाति-आधारित पार्टियों के उदय और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग ने दलित वोटों को विभाजित कर दिया है। परिणामस्वरूप, यह समुदाय और कमजोर होता गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर राष्ट्रीय 66 प्रतिशत से कम 56 प्रतिशत थी। मुसहरों की स्थिति अधिक गंभीर है, जिनकी साक्षरता दर तब 20 प्रतिशत से भी कम थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 5.6 प्रतिशत, तो सरकारी नौकरियों में 1.3 प्रतिशत थी, जो उनके निर्धारित कोटे से काफी कम है। क्या पार्टियां इनके लिए कुछ ठोस काम करेंगी?

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

शिक्षा और रोजगार में बढ़ रही भागीदारी

आजादी के बाद देश में जब से संविधान के आधार पर कानून का शासन लागू हुआ, तब से अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए कई बड़े कार्य हुए हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की गारंटी संविधान में दी गई। हालांकि, पहले इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में से ज्यादातर खाली रह जाती थीं, या आवेदक न मिलने पर इन्हें सामान्य वर्ग को दे दिया जाता था। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के बाद चली बहसों के बाद अदालत के आदेश से एससी-एसटी कोटे की सीटों को इन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों से भरने या खाली रखने की व्यवस्था शुरू हुई। इसके बाद अधिकांश सीटों पर इन वर्गों के अभ्यर्थी नियुक्त किए जाने लगे हैं। इसी तरह शिक्षा, रोजगार, कर्ज आदि में आरक्षण मिलने से भी उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग को सिर्फ सरकारी नौकरियों (सरकारी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों सहित) में आरक्षण प्राप्त है। हालांकि, सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियां खत्म होने से इन वर्गों को आरक्षण के तहत मिलने वाली नौकरियों में कमी आई है, फिर भी दलित-आदिवासियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही शिक्षा का विकास होने से निजी क्षेत्र की नौकरियों और अन्य रोजगार में भी इन वर्गों के स्त्री-पुरुष अपने उद्यम खड़े कर रहे हैं और दूसरे रोजगार अपना रहे हैं।

कुल मिलाकर देखें, तो दलितों की विकास की कथा भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की है, जिसमें शिक्षा व जागरूकता से वे सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। यह संघर्ष 18वीं और 19वीं सदी के समाज सुधारकों जैसे- अय्यंकाली से शुरू होकर 20वीं सदी के बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नेतृत्व में बौद्ध धर्म अपनाने जैसे आंदोलनों तक फैला। आजादी के बाद शिक्षा तक बढ़ी पहुंच से दलितों में चेतना जागी और उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए साहित्य, खासकर आत्मकथाओं का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने उत्पीड़न का विरोध किया और अपनी पहचान स्थापित की। 1960 और 1970 के दशक से दलित साहित्य सशक्तीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम बने। इनकी आत्मकथाओं ने जाति व्यवस्था, उत्पीड़न व सामाजिक अन्याय को उजागर किया। आज भी उनका संघर्ष जारी है, पर अपनी उपलब्धियों से इन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई है और वे अपने अधिकारों के लिए खूब लड़ रहे हैं।

निलेश कुमार मिश्र, टिप्पणीकार

संकट : दीपावली से पहले यूपी के सर्राफा बाजार में चांदी गायब !

■ आशीष दीक्षित

कानपुर। चांदी की रिकॉर्ड कीमतों ने निवेशकों को तो तगड़ा मुनाफा करा दिया लेकिन अब सर्राफा बाजार परेशानी में पड़ता दिख रहा है। इस बार निवेश के लिए चांदी इतनी खरीद ली गई है कि बाजार यह लगभग गायब हो गई है। त्योहारी सीजन में यूपी के हर बड़े शहर का सर्राफा शुद्ध चांदी की किल्लत से जूझ रहा है। हालत यह है कि प्रदेश में चांदी मांग 100 टन तक पहुंच गई है लेकिन आपूर्ति सिर्फ 35 से 40 टन हो पा रही है।

सर्राफा बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस असर दीवाली पर दिख सकता है और चांदी के सिक्कों, मूर्तियों, बर्तनों की कमी बाजार में दिख सकती है। हर साल धधकने वाली सर्राफों की भट्टियां ठंडी पड़ रही हैं। कारीगरों के औज़ार थमे हुए हैं। कानपुर महानगर बुलियन एंड सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष आशू शर्मा के अनुसार बाजार में चांदी की आपूर्ति मांग के मुकाबले काफी कम हो गई है। इसके चलते धनतेरस, दीवाली को लेकर चांदी के सिक्के, मूर्तियां और पूजन सामग्री बनाने का काम पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इनके निर्माण में 50 फीसदी तक की गिरावट आई है।

कानपुर में मांग तीन टन, आपूर्ति सिर्फ आधी

बाजार में शुद्ध चांदी की कमी का संकट अचानक नहीं आया है। भाव में लगातार रिकॉर्ड तेजी से निवेशकों ने चांदी में भारी निवेश किया है। ज्वेलर बताते हैं कि स्थानी बाजार में तीन टन की मांग है लेकिन डेढ़ टन चांदी मिल पा रही है। वहीं,

कानपुर की नील वाली गली में ज्वेलरी कारीगर सौमित्र बनर्जी और रोहन सरकार का कहना है कि पहली बार दीपावली से पहले शुद्ध चांदी को लेकर ऐसी कमी देखी है। हमारे पास हर साल की अपेक्षा केवल 40 फीसदी काम है।

प्रदेशभर में चांदी की कमी, कारोबारी बेचैन

प्रदेश के प्रमुख शहरों में शुद्ध चांदी की भारी किल्लत की बात सामने आ रही है। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बरेली से सर्राफा कारोबारियों के अनुसार, तेज निवेश, सीमित आयात और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों से घरेलू आपूर्ति चरमरा गई है। बैंकों से शुद्ध चांदी की आपूर्ति आधी हो रही है।

सोने-चांदी की चमक

चांदी		सोना	
10 अक्तूबर 2024	91,000 रुपये	10 अक्टूबर 2024	76,850
11 अक्टूबर 2025	1,71,500 रुपये	10 अक्टूबर 2025	1,26,000
उछाल	80,500	उछाल	49,150

दुनिया भर में कम आपूर्ति

1. भारत में हर साल लगभग 700 टन चांदी का उत्पादन होता है, जबकि खपत सात हजार टन से अधिक।
2. दुनियाभर में चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ी है लेकिन आपूर्ति स्थिर।
3. इंडोनेशिया और चिली जैसी जगहों पर चांदी की खदानें बंद होने दबाव और बढ़ा।
4. सरकार ने आसियान देशों से चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया।
5. केंद्रीय बैंकों और निवेशकों ने सोने-चांदी जैसे सुरक्षित विकल्प में भारी निवेश बढ़ाया।

दस दिनों में 21 हजार चढ़ी

चांदी कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि का दौर जारी है। बीते 10 दिनों में इसकी कीमतों में 21,000 रुपये का रिकॉर्ड उछाल आ चुका है। यह किसी भी कारोबारी सत्रों में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। पिछले तीन लगातार कारोबारी सत्रों में चांदी की कीमतें 17,500 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है। कीमतों में तेजी का दौर आगे भी संभव है।

> 70 फीसदी कारोबार निवेश पर टिका है। इसकी वजह से शुद्ध चांदी की किल्लत बाजार में है। मांग का 50 फीसदी आपूर्ति बाजार में हो रही है।
>
> –पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन

देश 30s

मुथूट समूह के एमडी से हुई पूछताछ

कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को केरल स्थित मुथूट समूह के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट से निवेशकों से मनी लॉड्रिंग के आरोप में पूछताछ की। ईडी ने केरल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों का संज्ञान लेते हुए मनी मनी लॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी के शाखा प्रबंधकों ने ज्यादा रिटर्न का वादा कर निवेशकों को ठगा।

जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे पर जवाब तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक समेत कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सोशल मीडिया पर रोक संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया खातों पर रोक के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे किसी भी उपयुक्त मंच पर कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने काबुल में धमाकों को लेकर पड़ोसी मुल्क को चेतावनी दी

हमारे साथ खेल न खेले पाकिस्तान: मुत्ताकी

ई दिल्ली, एजेंसी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कई जगहों पर धमाकों के बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अफगानों की हिम्मत को परखने की कोशिश न करें। अगर किसी को शक है, तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछ लें कि अफगानिस्तान से खेलना कितना भारी पड़ सकता है।

काबुल में हुए धमाकों के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हैं। मुत्ताकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद दिल्ली में अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सीमा के पास हुए हमले को हम पाकिस्तान की गलती मानते हैं। समस्याओं का हल ऐसे नहीं होता। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। अफगानिस्तान में 40 साल बाद शांति आई है, किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता।

निवेश-खनन के लिए आमंत्रण: मुत्ताकी ने कहा, भारत और अफगानिस्तान ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापार समिति गठित करने पर सहमति जताई है। अफगानिस्तान में निवेश और खनन एवं ऊर्जा क्षेत्रों में नए अवसरों के के लिए आमंत्रित किया है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अफगानी समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक से पहले मुलाकात करते हुए। ● एजेंसी

भारतीय परियोजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं: जयशंकर

मुत्ताकी के साथ बैठक में जयशंकर ने कहा, आपकी यात्रा हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने और स्थायी मित्रता की पुष्टि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक निकट पड़ोसी और अफगान जनता के शुभचिंतक के रूप में भारत को आपके विकास और प्रगति में गहरी रुचि है। जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा चलाई जा रही कई परियोजनाओं को फिर से शुरू किया गया है, जिससे दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी का नवीनीकरण हुआ है। हम पूरी हो चुकी परियोजनाओं के रखरखाव साथ ही पहले से स्वीकृत नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाएंगे।

भारत ने अफगानिस्तान की मदद का पिटारा खोला

1. 20 एंबुलेंस जाएगी, जिनमें से पांच जयशंकर व्यक्तिगत रूप से सौंपेंगे
2. एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, टीकाकरण और कैंसर की दवाइयां भी भेजेंगे
3. नशा मुक्ति सामग्री भी मुहैया कराई है और आगे भी ऐसा करने को तैयार है।
4. भूकंप प्रभावित इलाकों में आवास निर्माण में सहयोग देने और खाद्य सहायता की एक नई खेप भेजने की घोषणा
5. स्वदेश लौटे अफगान शरणार्थियों की मदद, सिंचाई क्षेत्र में तकनीकी सहयोग

मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार नहीं

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत-अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी के बीच शुक्रवार को दिल्ली में एक तालिबानी हरकत भी हुई। भारत यात्रा पर आए तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया। इस पर विदेश मंत्रालय कवर करने वाली महिला पत्रकारों ने सोशल मीडिया और विदेश मंत्रालय के मंच पर नाराजगी जाहिर की है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ग्रुप पर एक महिला पत्रकार ने लिखा कि उन्होंने ईरान, सऊदी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों को दिल्ली में कवर किया लेकिन कभी ऐसा नही हुआ। एक पत्रकार यक्षी शैली ने एक्स पर लिखा कि कोई भी महिला पत्रकार मुत्ताकी की प्रेस कांफ्रेंस में नही बुलाई गई थीं। सूत्रों के अनुसार, अफगानिस्तान दूतावास द्वारा सिर्फ 16 पुरुष पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। दो और पुरुष पत्रकारों को मौके पर एंट्री दे दी गई लेकिन वहां पर कुछ टीवी से जुड़ी महिला पत्रकार भी पहुंचीं लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई।

इससे पहले सुबह मुत्ताकी की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई थी तथा उसके बाद दोपहर में यह प्रेस वार्ता हुई। हालांकि, अफगानिस्तान से रिश्ते सुधार रहे विदेश मंत्रालय ने इस प्रकरण पर छुप्पी साध ली है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इस पर कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। वे इसे तालिबान की फितरत मान रहे हैं। मंत्रालय ने एक तरफ इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों का दावा है कि महिला पत्रकारों को नहीं बुलाए जाने की जानकारी विदेश मंत्रालय को थी।

अफगान राजनयिक दिल्ली में तैनात होंगे

मुत्ताकी ने कहा, काबुल जल्द ही भारत में अपने राजनयिक तैनात करेगा। भारत में अफगान मिशन में स्थायी राजनयिक नियुक्त होंगे, जबकि अब तक वहां कार्यरत अधिकारी ज्यादातर पूर्व अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त थे। भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा जो भारत के हितों के लिए खतरा बन सके। यह भी कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य छावनी नहीं होगी।

भारत में एआई हब बनने की क्षमता: नीति आयोग

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एआई क्षेत्र में रणनीतिक रूप आगे बढ़ता है तो वह दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन सकता है। इसके साथ ही एआई के जरिए नई तकनीक और नई भूमिकाओं के अवसर भी पैदा होंगे।

आयोग ने शुकवार को 'एआई इकोनॉमी में रोजगार सृजन के रोडमैप' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार, भारत का आईटी और बीपीओ क्षेत्र करीब 250 अरब डॉलर का है, जिसमें वर्ष 2023 के आंकड़ों के हिसाब से करीब 75 लाख लोग कार्यरत हैं। एआई के बढ़ते प्रभाव से यह क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होगा। मौजूदा रुझानों के हिसाब से आईटी क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या वर्ष 2031 तक घटकर 60 लाख हो सकती है। वहीं, बीपीओ के क्षेत्र में यह संख्या 25 लाख से घटकर 18 लाख रहने के आसार हैं।

छोटे कर मामले अपराध की श्रेणी से बाहर हों

आयोग ने अपने कर नीति कार्यपत्र में आयकर अधिनियम-2025 में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इसमें छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, अनिवार्य न्यूनतम सजा को हटाने और जेल की अवधि कम करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान आयकर अधिनियम में 13 प्रावधानों के तहत 35 अलग-अलग कार्यों या लापरवाहियों को अपराध माना गया है। इन सभी मामलों में जेल और जुर्माने व दोनों का प्रावधान है। वहीं, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान रखा गया है।

उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर कड़ाके की सर्दी शुरू

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। दिन और रात के तापमान में आठ से 10-12 डिग्री तक का अंतर देखने को मिला है। रात को ठंड में इजाफा हो गया है।

पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में न्यूनतम सात डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। केदारनाथ धाम में सुबह तापमान दो डिग्री के आसपास रह रहा है, जबकि रात को तापमान एक डिग्री पर पहुंच गया। पिछले पांच दिनों से बदरीनाथ, औली में रात को 5-7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मानसून की विदाई के बाद बारिश ने मौसम दिया है।

हेमकुंड साहिब के कपाट बंद

ज्योतिर्मठ, संवादाता। सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए शुक्रवार को दोपहर डेढ़ बजे वर्ष की अंतिम अरदास और हुक्मनामे के बाद बंद कर दिए गए हैं। चारों ओर पसरी बर्फ के बावजूद कपाट बंद होते समय मौजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। कपाट बंद होते समय करीब दो हजार श्रद्धालु हेमकुंड में मौजूद रहे। हेमकुंड में इस वर्ष रिकार्ड दो लाख 76 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं।

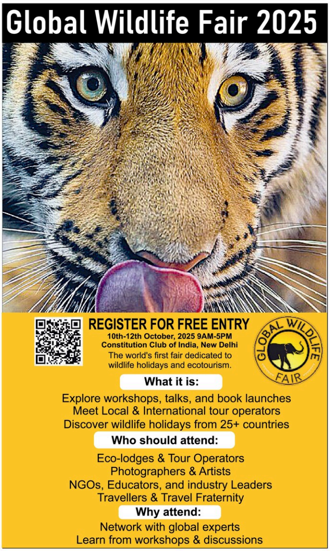

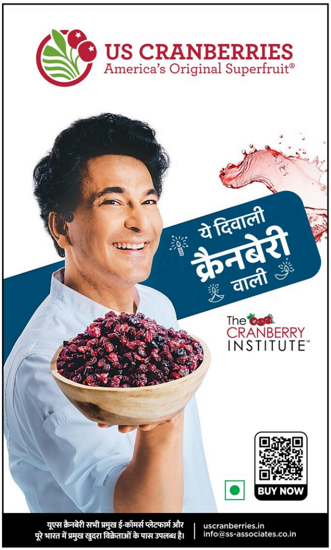

संपादकीय

राखेतून शांतता उगवेल?

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या युद्धात अक्षरशः राखरांगोळी झालेल्या गाझा पट्टीत पुन्हा एकदा 'शांती' हा शब्द कानावर पडत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता प्रस्तावाच्या पहिल्या टप्प्याला इस्रायल आणि हमासने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रक्तरंजित संघर्षाची अखेर आणि हमासच्या ताब्यातील इस्रायली ओलीस व इस्रायली तुरुंगातील पॅलेस्टिनी युद्धकैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शांतता प्रस्तावापासून मोठ्या अपेक्षा आहेत; पण संशयांचे सावट अजूनही कायम आहे. प्रदीर्घकाळापासून सुरू असलेला इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी हा प्रस्ताव नवी दिशा देऊ शकेल का, हा प्रश्न कायमच आहे. भूमध्य समुद्राच्या पूर्व किनाऱ्यावरील केवळ ४४ किलोमीटर लांबीच्या गाझा पट्टीत वीस लाखांहून अधिक लोक राहतात. द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार अस्तित्वात आलेल्या इस्रायलसोबतच पॅलेस्टाइन हा देशही उभा राहणे अपेक्षित होते. पॅलेस्टाइनच्या वाट्याला एकमेकांपासून विभक्त असलेले गाझा पट्टी आणि वेस्ट बँक हे दोन प्रदेश आले होते; परंतु लगेच झालेल्या अरब-इस्रायल युद्धात जॉर्डनने वेस्ट बँक, तर इजिप्तने गाझावर ताबा मिळवला. पुढे १९६७ मध्ये अवघ्या सहा दिवसांच्या युद्धात इस्रायलने पाच अरब देशांना लोळवले आणि गाझा व वेस्ट बँकवरही नियंत्रण मिळवले. त्यानंतर त्या भूमीने आजतागायत बघितला तो रक्तरंजित संघर्षच! इस्रायलने २००५ मध्ये गाझातून सैन्य मागे घेतले; पण सीमांचे नियंत्रण, हवाईक्षेत्र आणि समुद्री नाकेबंदी मात्र कायम ठेवली. परिणामी स्वतंत्र असूनही गाझा पट्टी जगापासून वेगळी, बंदिस्त झाली. हमासने २००७ मध्ये सत्ता मिळवल्यानंतर गाझा इस्रायलसाठी सततच्या सुरक्षा चिंतेचा केंद्रबिंदू बनला. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलमध्ये घुसखोरी करत, अनेक नागरिकांची हत्या केली, महिलांवर शारीरिक अत्याचार केले आणि अनेकांना बंदी बनवून गाझात नेले. त्यानंतर इस्रायलने आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली गाझावर अभूतपूर्व हल्ला चढवला. तेव्हापासून आतापर्यंत गाझा पट्टी अक्षरशः भाजून निघाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, या युद्धात आतापर्यंत साठ हजारांहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले, पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आणि लाखो लोक बेघर झाले. शांततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी प्रयत्न केले; पण इस्रायल आणि हमासच्या हटवादी भूमिकेमुळे गाझातील सर्वसामान्य जनतेची प्रचंड होरपळ झाली. या पार्श्वभूमीवर, नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी धडपडणाऱ्या ट्रम्प यांनी शांतता प्रस्ताव मांडला होता. त्यांच्या योजनेत, तत्काळ संघर्षविराम, इस्रायली सैन्याची टप्प्याटप्प्याने माघार, इस्रायली ओलिसांची सुटका, पॅलेस्टिनी युद्धकैद्यांची मुक्तता आणि गाझात आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या नियंत्रणाखाली हंगामी सरकार, हे प्रमुख मुद्दे आहेत. हमासला प्रशासनापासून दूर ठेवण्याची अट या योजनेत आहे. हमासच्या सशस्त्र शाखेला शस्त्रास्त्र समर्पणही करावे लागेल. मानवी मदत, पुनर्रचना आणि उद्ध्वस्त भागांचे पुनर्वसन हेदेखील योजनेचे घटक आहेत. ओलीस व युद्धकैद्यांच्या सुटकेमुळे किमान रक्तपात थांबू शकेल; परंतु हा प्रस्ताव परिपूर्ण नाही. हमासला औपचारिक मान्यता न दिल्याने हा करार अपूर्ण राहतो. फतह, इस्लामिक जिहादसारख्या इतर गटांना बाजूला ठेवणेही घातक ठरू शकते. संघर्ष संपुष्टात येण्यासाठी राजकीय स्वीकार आवश्यक असतो; केवळ सैनिकी दबावाने शांती टिकत नाही. इस्रायलने प्रस्तावाला मान्यता दिली असली, तरी नेतन्याहू सरकारवर अंतर्गत दबाव आहे. जहालमतवादी राजकीय पक्ष 'हमासचा पूर्ण नाश' एकमेव पर्याय मानतात. हमासच्या राजकीय आघाडीने चर्चेला संमती दिली असली, तरी सशस्त्र शाखेने नकार दिला आहे. म्हणजेच, दोन्ही बाजूंनी दोन मतप्रवाह आहेत. ही दरी भरून न निघाल्यास प्रस्ताव पहिल्याच टप्प्यात कोसळू शकतो. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय दबावाला जुमानत नाही, हे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शांतता नको असलेल्या कोणत्याही घटकाने पुन्हा एखादी कुरापत काढल्यास, करार संपुष्टात यायला वेळ लागणार नाही. गाझातील संघर्षात दोन्ही बाजूंनी मानवी हक्कांच्या सीमा तुडवल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी झालेल्या अतिरेकामुळे सर्वसामान्य पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जीवनच उद्ध्वस्त झाले आहे. सध्याच्या घडीला गाझातील सर्वसामान्यांची शांततेची व्याख्या फार वेगळी आहे.... त्यांना फक्त जगायचे आहे!

'अर्‌-ट्टाय' काय आहे? ते व्हॉट्सॲपला पर्याय ठरेल?

झोहो या भारतीय कंपनीने व्हॉट्सॲपला पर्याय म्हणून तयार केलेलं ॲप वापरायला सोपं आहे; पण ते स्वीकारलं जाईल?

प्रसाद शिरगावकर
मुक्तस्रोत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षक आणि वक्ते

अर्‌-ट्टाय (Arattai) नावाचं मेसेजिंग ॲप सध्या जोरदार चर्चेमध्ये आहे. झोहो नावाच्या भारतीय कंपनीने व्हॉट्सॲपला पर्याय म्हणून हे ॲप तयार केलं आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दोनच आठवड्यांपूर्वी देशातील जनतेला स्वदेशी ॲप्सचा वापर करायचं आवाहन करताना अर्‌-ट्टाय ॲपचा उल्लेख केल्यामुळे अर्‌-ट्टायविषयी प्रचंड उत्सुकता निर्माण होऊन लाखो लोकांनी ते डाउनलोड केलं.

व्हॉट्सॲप हे जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप. भारत ही व्हॉट्सॲपसाठीची जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ. भारतात व्हॉट्सॲपचे पन्नास कोटी वापरकर्ते आहेत. व्हॉट्सॲप हे भारतीयांच्या आयुष्याचं अविभाज्य अंग बनलं आहे.

व्हॉट्सॲप हे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम हे दोन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ज्यांच्या मालकीचे आहेत अशा 'मेटा' या अमेरिकन कंपनीच्या मालकीचं आहे. वापरकर्त्यांच्या वावराचा सर्व डेटा स्वतः वापरण्याचे आणि तो पार्टनर कंपन्यांना वापरू देण्याचे हक्क व्हॉट्सॲपने स्वतःकडे ठेवले आहेत. या डेटाचा वापर आपल्याला फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर टार्गेटेड जाहिराती दाखवण्यासाठी केला जातो. इतर कंपन्यांना हा डेटा कशा प्रकारे उपलब्ध केला जातो याविषयी कसलीही पारदर्शकता नाही. व्हॉट्सॲपच्या वापराचा आपल्याला कधीही न दिसलेला हा सगळ्यात मोठा धोका आहे.

त्यावर मात करण्याकरिता झोहो या भारतीय कंपनीने अर्‌-ट्टाय हे ॲप तयार केलं. अर्‌-ट्टाय हा तमिळ शब्द आहे, त्याचा अर्थ होतो गप्पा! झोहो कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेंबू म्हणतात, भारतीयांसाठी भारतीय भाषांमध्ये व्यवस्थित चालेल असं हे मेसेंजर ॲप आहे. या ॲपच्या वापरकर्त्यांचा डेटा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही जाहिरातीसाठी व अन्य कारणांसाठी वापरणार नाही.

अर्‌-ट्टाय ॲपमध्ये व्हॉट्सॲपमध्ये असलेल्या सर्व सुविधा, म्हणजे टेक्स्ट, ऑडिओ आणि व्हिडीओ मेसेजेस, कॉल्स, स्टेटस अपडेट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट्स, ग्रुप्स, चॅनल्स इत्यादी आहेतच. त्याचबरोबर, दोन लक्षणीय अशा सुविधाही आहेत. त्यातली एक म्हणजे पाकीट नावाची सुविधा. या सुविधेनुसार आपण आपल्याला हव्या त्या फाइल्स किंवा मेसेजेस अर्‌-ट्टायच्या पाकीट विभागात साठवून ठेवू शकतो. या गोष्टी अर्‌-ट्टायच्या क्लाउडवर सुरक्षित राहतात.

दुसरी लक्षणीय सुविधा म्हणजे 'मीटिंग्ज'. या सुविधेनुसार आपण वन-टू-वन किंवा ग्रुपबरोबरच्या मीटिंग्जचं अर्‌-ट्टाय ॲपमधूनच नियोजन करू शकतो आणि प्रत्यक्ष मीटिंगदेखील अर्‌-ट्टाय ॲपमधूनच घेता येऊ शकते. म्हणजे हे काहीसं गुगल मीट किंवा झूम यांच्यासारखं फीचर आहे.

गेल्या तीन-चार आठवड्यांमध्ये अर्‌-ट्टायचे सुमारे पन्नास लाख डाउनलोड झाले आहेत. अर्‌-ट्टायबद्दल वापरकर्त्या लोकांच्या बऱ्यावाईट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. बहुसंख्य लोकांना हे वापरायला खूप सोपं वाटतं. पॉकेट आणि मीटिंगसारख्या नव्या सुविधांचं लोक स्वागत करत आहेत. मात्र 'हे ॲप वारंवार क्रॅश होतं' अशी अनेकांची तक्रार आहे. सगळ्यांत मोठी तक्रार टेक्स्ट मेसेजेसना Encryption नसणे ह्याबद्दल आहे. अर्‌-ट्टायमध्ये सध्या ऑडिओ आणि व्हिडीओ मेसेजेस इंक्रिप्टेड आहेत, मात्र टेक्स्ट मेसेजेस मात्र इंक्रिप्टेड केलेले नसतात. वापरकर्त्यांना हे अत्यंत धोक्याचं वाटतं. असे मेसेजेस झोहो कंपनीला वाचता येणं आणि त्याचा गैरवापर होणं हे शक्य आहे. त्यामुळे encryption असल्याशिवाय अर्‌-ट्टाय वापरण्याला अनेक तज्ज्ञांचा विरोध आहे. 'या फीचरवर आम्ही काम करत आहोत आणि लवकरच ते ॲपमध्ये उपलब्ध होईल', असं झोहो कंपनीचं म्हणणं आहे.

इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप्सच्या विश्वात सध्या व्हॉट्सॲप, वुईचॅट, टेलिग्राम, सिग्नल, डिस्कॉर्ड, स्नॅपचॅट ही आघाडीची ॲप्स आहेत. जगभरात शेकडो कोटी लोक ही ॲप्स वापरतात. व्हॉट्सॲपचे सध्या जगभरात तीन अब्ज वापरकर्ते आहेत, तर वुई चॅटचे सव्वा ते दीड अब्ज! या तुलनेत अर्‌-ट्टायचे पन्नास लाख युजर्स नगण्य आहेत. सर्व आघाडीच्या ॲप्सना टक्कर देऊन स्वतःचं नवं स्थान निर्माण करणं हे अर्‌-ट्टायसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. कोणतीही व्यक्ती नियमितपणे वापरत असलेलं मेसेजिंग ॲप तिच्या रोजच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनलेलं असतं. ते ॲप सोडून नव्या ॲपवर जायचं तर आपले कॉंटॅक्ट्स आणि ग्रुप्स तिथे असावे लागतात. शिवाय, जुनं सोडून नवं मेसेजिंग ॲप वापरायचं तर त्यासाठी अत्यंत प्रबळ कारण असावं लागतं. अर्‌-ट्टाय हे स्वदेशी आहे, आपल्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर करणार नाही असं त्यांनी वचन दिलं आहे आणि इतर मेसेजिंग ॲपमध्ये नसलेल्या एक-दोन अधिकच्या सुविधा त्यात आहेत या तीन गोष्टी, आपलं रोजच्या सवयीचं मेसेजिंग ॲप सोडून अर्‌-ट्टाय वापरण्यासाठीची प्रबळ कारणं लोकांना वाटतात का, याचं उत्तर येणाऱ्या काळात आपल्याला मिळेल.

prasad@aadii.net

प्रासंगिक

नोबेल नायतर नाय, तात्यांना थेट 'महा-नोबेल'च!

तात्या म्हणजे लई बेणं. पंचक्रोशीतल्या शांतता पुरस्काराची त्याला हाव सुटली. मग त्यानं गावातच भांडणं लावायला आणि ती 'मिटवायला' सुरुवात केली..

सुमंत अयाचित
उप वृत्तसंपादक,
लोकमत, छ. संभाजीनगर

भांडण लावणं-सोडवणं आणि त्याचं श्रेय लाटणं, हा आमच्या तात्याचा नाद खुळाच होऊन बसला आहे. गावातला धनदांडगा माणूस ! पैसाअडका चिक्कार, त्यामुळे गावभरच्या उचापती करण्यात फार रस. गावात कुठे रिकामी जागा दिसली किंवा कोणती जागा वादात असली की, याचा डोळा गेलाच म्हणून समजा. पैसा खर्च करील, बारा भानगडी करील, पण जागेच्या मालकाला धमकावून ती जागा ताब्यात घेणार म्हणजे घेणारच.

मध्यंतरी तात्याचं टक्कुरच सरकलं. गावात नवखा माणूसच येऊ देत नव्हता. म्हणायचा, आधीच आमच्या गावात जागा नाही आणि त्यात तुम्ही येऊन कुठं गर्दी करता? बाहेरगावच्या काही लोकांना तर त्यांना हाकलूनही लावलं. गावातले लोक वैतागले, कारण तात्या दुसऱ्या गावातल्या लोकांना गावात येऊ देत नाही म्हटल्यावर बाहेरच्या गावचे लोक तरी या गावच्या लोकांना त्यांच्या गावात कशाला येऊ देतील?, पण तात्याला एवढी कुठली समज? अखेर त्याच्या गावच्या लोकांना इतर गावांनी बंदी घातली, तेव्हा कुठं तात्याचं डोकं ताळ्यावर आलं.

दुसऱ्यांदा गावाची सत्ता हाती आल्यावर तर तात्या चेकाळलाच. त्याला पंचक्रोशीतल्या सगळ्यात मोठ्या पुरस्काराची हाव सुटली. पंचक्रोशीत चांगलं, शांततेचं काम करणाऱ्या माणसाला हा पुरस्कार दरवर्षी दिला जायचा. पण, उपटसुंभ्या तात्याला काहीही करून हा पुरस्कार हवाच होता. त्यासाठी त्यानं लटपटी, खटपटी सुरू केल्या. तो म्हणे, अशांतता असल्याशिवाय, भांडणं, मारामाऱ्या झाल्याशिवाय शांतता निर्माण करण्यात काय मजा आहे? मग त्यासाठी त्याने आधीच कुरबुरी असलेल्या शेजाऱ्यांमध्ये भांडणं लावायला सुरुवात केली. त्यांनी एकमेकांची डोके फोडून झाली की, तात्या तिथे जायचा आणि दोघांची समजूत घालून त्यांना ॲम्ब्युलन्समध्ये घालून, भांडण मिटवल्याचं परस्पर जाहीरही करून टाकायचा. मग, हॉस्पिटलमध्ये शेजारी-शेजारी उपचार घेत असलेले दोघेजण या भांडणाचं मूळ शोधू लागत, तेव्हा 'तात्यानंच तेल टाकून आग लावली आणि शांतसुद्धा केली', हे त्यांच्या लक्षात यायचं. पण, तोवर फार उशीर झालेला असायचा.

तात्यानं गावात चार-पाच भांडणं लावून सोडवल्यावर गावकरीच हुशार झाले. या तात्यानं गावची शांतताच घालवली, त्यालाच गावातून हाकलून दिलं पाहिजे, असाही विचार पुढं आला. पण, पुढच्याच क्षणी सर्वजण शांत झाले. कारण, तात्या म्हणजे लई बेणं होतं. शिवाय गावातला प्रतिष्ठित आणि पैसेवाला माणूस. त्याला गप्प तर करायचं, पण पंचक्रोशीतला शांततेचा पुरस्कारही मिळू द्यायचा नाही, यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करू लागले.

मग गावकऱ्यांनीच अफलातून डोकं चालवून आयडियाची भन्नाट कल्पना मांडली. तात्या पुरस्कारासाठी फारच पेटलाय. त्यासाठी आपणच एखाद्या पुरस्काराची घोषणा करू. पंचक्रोशीतल्या मोठ्या पुरस्कारापेक्षाही हा मोठा आहे, महान आहे, असंही जाहीर करू आणि तात्याची पुरस्काराची हौस एकदाची भागवून टाकू. आपल्या गावात महा-नोबेल पुरस्कार जाहीर करू, तात्याला देऊ आणि त्याचं तोंड गप्प करून टाकू... असं ठरलं.

कार्यक्रम ठरला. गाजावाजा केला. मंडप टाकला, स्टेज उभारलं. पंचपक्वान्नाचा बेतही ठरला. तात्या तर जाम खूश होता. नोबेलपेक्षा मोठा पुरस्कार आपल्याला मिळतोय आणि तोही पहिलाच पुरस्कार आपल्याला मिळतोय, या विचारानं त्याला काहीच सुचत नव्हतं. पुरस्कार वितरणाची वेळ जवळ आली. लोक जमले. हार-तुरे आणले आणि तात्या एकदाचा व्यासपीठावर विराजमान झाला. पण, इथंच गडबड झाली.

तात्याच्या सन्मानार्थ (?) बोलण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या एका वक्त्यानं 'तात्याला हा पुरस्कार का देतोय', हे खरंखरं सांगून टाकलं आणि तात्या जाम भडकला.

'माझ्या समाधानासाठी हा कार्यक्रम करतात का? थांबा, मी तो पंचक्रोशीचा पुरस्कार घेऊनच येतो. सन्मानानं दिला नाही, तर धमकावून, हिसकावून, पळवून आणतो'... असं म्हणून तात्या स्टेजवरून उडी मारून खाली उतरला आणि गाडी घेऊन गेलासुद्धा.

इकडं गावाकडचे लोक म्हणाले, मरू दे तात्याला. आपण आपली जेवणं उरकून घेऊ!

- पण तात्याचं नशिबच खोटं. हा त्या गावात जाईपर्यंत तिथल्या लोकांनी खरंखुरं काम करणाऱ्या एका सच्च्या बाईला तो पुरस्कार देऊनही टाकला होता. ते बघून तर तात्या पहिल्यापेक्षा संतापानं ५० टक्के जास्त लालबुंद झाला.

तेवढ्यात त्याच्या गावचे लोक मागून आलेच. त्यांनी तात्याला उचललं आणि गाडीत घालून गावी आणलं आणि गावातला 'महा-नोबेल' पुरस्कार तात्याच्या गळ्यात मारला. एवढे दिवस सगळीकडं ऐटीत फिरणाऱ्या तात्याचा चेहरा मात्र बघण्यासारखा झाला होता...

जगभर

घटस्फोटासाठी प्रियकराला दिले ₹ ४ कोटी

ऐतराज हा चित्रपट पाहिलाय? राज मल्होत्रा (अक्षय कुमार), प्रिया (करिना कपूर) आणि सोनिया (प्रियंका चोप्रा) या 'प्रेम त्रिकोणावर' आधारित हा चित्रपट. सोनिया ही राजची पूर्वीची प्रेयसी. श्रीमंतीच्या हव्यासापायी सोनिया राजला नाकारून एका श्रीमंत व्यावसायिकाशी लग्न करते, तर राज नंतर प्रियाशी लग्न करतो. एके दिवशी राजच्या ऑफिसमध्ये नवीन बॉसची पत्नी म्हणून सोनियाचा प्रवेश होतो. सोनिया पुन्हा राजला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करते, पण आता राज तिला नाकारतो. अपमानित झालेली सोनिया राजवर लैंगिक छळाचा खोटा आरोप करते. केस कोर्टात जाते. नंतर राजची पत्नी प्रिया वकील म्हणून आपल्या नवऱ्याच्या बाजूने उभी राहते आणि सोनियाचं पितळ उघडं पाडते...

चित्रपटाला साजेशी अशीच एक घटना नुकतीच चीनमध्ये घडलीय. त्यामुळे सोशल मीडियावर नेटकरी यावरून चर्चेचा किस पाडताहेत. चीनमधील 'शू' ही एका बड्या कंपनीची मालकीण. गर्भश्रीमंत. कंपनीतीलच एक कर्मचाऱ्यावर तिचं प्रेम जडतं. या कर्मचाऱ्याचं नाव 'ही'. पण, हा कर्मचारी आधीच विवाहित. त्याला एक मुलगाही आहे. पण, शू मागे हटायला तयार नसते.

तिला ही याच्याशीच लग्न करायचं असल्यानं ती आपल्या या कर्मचाऱ्याला त्याच्या पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी तगादा लावते. शेवटी ही देखील तिची मागणी मान्य करतो आणि आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी दावा दाखल करतो. घटस्फोटासाठी त्याला आपल्या पत्नीला तीन दशलक्ष युआन (सुमारे ३ कोटी ७२ लाख रुपये) द्यावे लागणार असतात. आता एवढी मोठी रक्कम तो कुठून आणणार? पण, पैशाचा प्रश्न नसतोच. कारण आपल्या या प्रियकराशी लग्न करण्यासाठी शू स्वतःच हे पैसे देणार असते. त्याप्रमाणे ती हे पैसे आपल्या कर्मचाऱ्याला देतेही आणि त्याला आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घ्यायला लावते. सगळं काही शूच्या मनासारखं होतं. शू आणि ही हे दोघंही सोबत राहायला लागतात.

कहाणीत इथे एक नवा ट्विस्ट येतो. सुरुवातीचे काही दिवस तर मजेत जातात. पण, वर्षभरानंतर दोघांत खटके उडायला सुरुवात होते. शूला वाटायला लागतं, आपल्या ज्या कर्मचाऱ्यावर; ही याच्यावर आपण जिवापाड प्रेम केलं, हे प्रेम मिळविण्यासाठी अक्षरश: वाट्टेल ते केलं, त्याच्यावर, त्याच्यासाठी लाखो, करोडो रुपये खर्च केले, पण तो तर आपल्या लायकीचाच नाही! आपण चुकीचा लाइफ पार्टनर निवडला याचा तिला आता पस्तावा व्हायला लागतो.

काहीही झालं तरी ती एक यशस्वी 'व्यावसायिक'! या 'सौद्यात' आपल्याला मोठा 'घाटा' झाला आहे, हे लक्षात आल्यानंतर ही याला दिलेले पैसे ती परत मागायला सुरुवात करते.

ही मूळचाच फाटका. तो एवढे पैसे कुठून आणणार? कहाणीत पुन्हा नवा ट्विस्ट येतो. आपल्या 'नवऱ्या'वर खर्च केलेले पैसे परत मिळविण्यासाठी शू कोर्टात जाते. शू ला आपले पैसे परत हवे असतात, तर ही मुळातच कंगाल असतो. त्याच्याकडे आपल्या नव्या बायकोला देण्यासाठी फुटकी कवडीही नसते. तिच्याच पैशांवर तर तो आता जगत असतो! कोर्टानंही ही याची बाजू उचलून धरली आणि शूला काहीही 'नुकसानभरपाई' मिळणार नाही, असा आदेश दिला! यावरुन जगभरात मतमतांतरं मांडली जात आहेत..

जनमन

चिंपांझींवरील संशोधन लक्षवेधी

'आफ्रिकेतील टांझानियाच्या घनदाट जंगलांतली जादूगर' (लोकमत, दि. ६ ऑक्टोबर) हा डॉ. सुनील देशपांडे यांचा माहितीपूर्ण लेख वाचला. आपल्या देशात क्रिकेटपटू आणि सिनेकलाकार यांना मिळणारी प्रसिद्धी अफाट आहे. मात्र आपले आयुष्य संशोधनासाठी देणाऱ्या शास्त्रज्ञांबद्धल मात्र लोकमानस खूपच उदासीन दिसून येते. एका महिला संशोधकाने आपल्या 'चिंपांझी'वरच्या संशोधनाने साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले. मूळच्या ब्रिटनच्या असलेल्या जेन गुडाल यांनी आपले आयुष्य टांझानियात जाऊन 'चिंपांझी 'वर संशोधनाला वाहिले. त्यांच्या संशोधनाने अनेक गृहीतके कोलमडली आणि प्रचलित समजांना चांगलाच धक्का दिला. जेन गुडाल यांच्या संशोधनाने प्राण्यांबाबत विचार करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. प्राण्यांच्या वागण्यावरच्या त्यांच्या आगळ्या वेगळ्या संशोधनाने जगभरच्या अनेक संशोधकांना आपली वैचारिक बैठक पक्की करण्याची प्रेरणा मिळाली. 'चिंपांझी 'हा माणूसच आहे हे स्वीकारले जावे या टप्प्यावर त्यांचे संशोधन पोहोचले. त्यांनी आपल्या संशोधनाने 'चिंपांझी'च्या वागण्याचे रहस्य उलगडले. चिंपांझी हे खूप सभ्य आणि काळजी घेणारे, कुटुंबवत्सल असतात हे त्यांनी समोर आणले. गुडाल यांच्या संशोधनाने प्राण्यांना भावना असतात, त्यांची अशी संस्कृती असते हे सिद्ध झाले. माकड, उंदीर, डॉल्फीन, पक्षी आणि अगदी ऑक्टोपस यांच्याकडे वागण्याचे तारतम्य असते आणि हुषारीही असते. आपण नेहमीच माणसाचे विश्व हे प्राण्यांच्या विश्वापेक्षा एकदम वेगळे आहे हे अगदी ठामपणे समजत आलो आहोत; पण त्या समजाला मोठा धक्का गुडाल यांच्या संशोधनाने दिला.

- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८९८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

क्विक Update

गुरुकुंज आश्रमात आज मौन श्रद्धांजली

तिवसा(अमरावती) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथीनिमित्त शनिवारी दुपारी ४ वाजून ५८ मिनिटांनी गुरुकुंजातील महासमाधीस्थळी मौन श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येणार आहे. राष्ट्रसंतांचे महापरिनिर्वाण ११ ऑक्टोबरला याच वेळी झाले होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती राहील.

कांदा दरात घसरण; शेतकरी रस्त्यावर

नाशिक : कांदा दरात सातत्याने होणाऱ्या घसरणीमुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.१०) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निफाड तालुक्यातील विंचूर येथे रास्ता रोको आंदोलन करत वाहतूक रोखून धरली. कांद्याला २०० ते १ हजार रुपये, तर जास्तीत जास्त १२०० रुपयांचा दर मिळत आहे. केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनएसएफडूारे कांदा खरेदी करत तो बाजारात विक्रीसाठी आणला आहे. त्यामुळेही दरावर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

मेडिकलमध्ये नशेच्या इंजेक्शनची विक्री

श्रीरामपूर (जि. अहिल्यानगर) : तालुक्यातील खंडाळा येथे नशेच्या इंजेक्शनची विक्री करताना मेडिकल चालकाला स्थानिक गुन्हे शाखेने रंगेहाथ पकडले आहे. यापूर्वी शहर पोलिसांनी नशेच्या इंजेक्शन विक्रीविरुद्ध कारवाया केल्या आहेत. मात्र, हा प्रकार तालुक्यात सर्रासपणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. पोलिसांकडून अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव पंकज चव्हाण असे आहे. श्रीरामपूर-बाभळेश्वर मार्गावर खंडाळा गावच्या शिवारात चव्हाण याचे मेडिकल आहे.

बाथरूममध्ये 'मांजऱ्या'; 'रेस्क्यू'कडून जीवदान

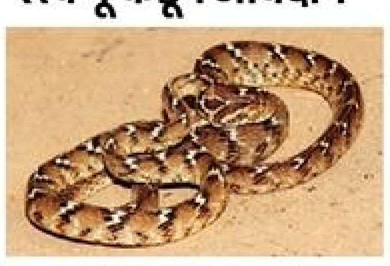

कोल्हापूर : काळा अन् राखाडी रंग, पांढरे चट्टे असलेला, झाडांवर राहणारा अडीच फुटांचा मांजऱ्या साप कोल्हापूर शहरातील बोंद्रेनगर येथे एका घराच्या बाथरूममध्ये आढळला. निमविषारी असलेला हा साप वन्यजीव रेस्क्यू टीमने पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडला.

तलवारीने कापला केक, ७ जणांवर गुन्हा

सोलापूर : जोरजोरात गाणी वाजवत नागरिकांच्या मनात दहशत निर्माण होईल, अशा पद्धतीने तलवार फिरवून ४ ऑक्टोबरला साठे पाटील वस्ती येथे वाढदिवसाचा केक कापणाऱ्यासह सात जणांवर गुरूवारी गुन्हा दाखल झाला. आरोपींनी दुचाकीवर ट्रिपलसीट बसून बाईक रॅली काढली. गाणी वाजवत शांतता भंग केली.

हवालदाराच्या चहाच्या दुकानात छापल्या १ कोटीच्या नोटा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मिरज (जि. सांगली) : मिरजेत एक कोटी रुपये किमतीच्या बनावट नोटा जप्त करून कोल्हापुरातील पोलिस हवालदारासह पाच जणांना पोलिस पथकाकडून अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून ५०० व २०० रुपयांच्या बनावट नोटा, कलर झेरॉक्स मशीन, स्कॅनर प्रिंटर, वाहन असा तब्बल १ कोटी ११ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी शुक्रवारी दिली आहे. कारवाईत पकडण्यात आलेल्या या सर्व नोटांची छपाई कोल्हापूर शहरातील एका पोलिस हवालदाराच्या चहाच्या दुकानात झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.

पाचशे रुपयांच्या खऱ्या नोटेच्या बदल्यात तीन बनावट नोटा देण्यात येत होत्या. ही कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक घुगे यांनी सांगितले.

आरोपींना दिली पोलिस कोठडी

मुख्य सूत्रधार पोलिस हवालदार इब्रार आदम इनामदार (४५, रा. कसबा बावडा), सुप्रीत काडापा देसाई (रा. गडहिंग्लज), राहुल राजाराम जाधव (३३, कोरोची), नरेंद्र जगन्नाथ शिंदे (५०, टाकाळा), सिद्धेश जगदीश म्हात्रे (३८, रा. मालाड पूर्व, मुंबई) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. न्यायालयाने सर्वांना १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

कलर झेरॉक्स मशिनवर नोटांची होत होती छपाई

मिरजेत कोल्हापूर रस्त्यावर नीलजी बामणी येथे पुलाखाली बनावट नोटा विक्रीसाठी आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पथकाने छापा टाकून सुप्रीत काडापा देसाई यास ४२ हजार रुपये किमतीच्या नोटांसह ताब्यात घेतले.

चौकशीत हवालदार इब्रार आदम इनामदार याच्या कसबा बावडा येथे असलेल्या सिद्धकला चहा या दुकानात कलर झेरॉक्स मशीनवर नोटा छापण्यात येत असल्याचे निष्पन्न झाले. इब्रार हा पोलिस दलात वाहनचालक म्हणून कार्यरत असून, कारवाईचा अहवाल कोल्हापूर पोलिसांना पाठवण्यात आल्याचे घुगे यांनी सांगितले.

पेट्रोल पंपावर दरोडा, ५ संशयित ताब्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) : केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या मालकीच्या रक्षा ऑटो फ्युएल्स या मुक्ताईनगरातील पेट्रोल पंपावर दरोड्याप्रकरणी पाच संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. आणखी संशयितांच्या शोधासाठी सात पथके रवाना करण्यात आली आहेत. दोन दुचाकीवरील पाच जणांनी बंदुकीचा धाक दाखवत प्रकाश माळी व दीपक खोसे या दोन कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत तोडफोड केली आणि एक लाख ३५ हजार रुपयांची रोकड लंपास केली होती. ही घटना गुरुवारी रात्री १०:४५ वाजण्याच्या सुमारास घडली होती.

बनावट दिव्यांग शोधण्यात आरोग्य विभागाचाच अडसर

नियमात हवी सुधारणा : प्रमाणपत्राचे अधिकार एकट्या आरोग्य यंत्रणेकडे एकवटले

लोकमत ★ विशेष

सुधीर लंके
लोकमत न्यूज नेटवर्क

अहिल्यानगर : राज्यातील सर्व दिव्यांग शासकीय कर्मचाऱ्यांची तीन महिन्यांत पडताळणी करा, असा शासन आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काढला. पण, दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे अधिकार एकट्या आरोग्य यंत्रणेच्या हातात एकवटले असल्याने ते आपलीच प्रमाणपत्र कशी खोटी ठरविणार? याबाबत साशंकता आहे.

आरोग्य विभागाच्या शासन आदेशानुसार, दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार जिल्हा रुग्णालये, महापालिकांची रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये व केंद्र शासनाच्या संस्थांना आहे. या रुग्णालयांतील तीन सदस्यीय मंडळाने व्यक्तीची तपासणी करून त्याला ऑनलाइन प्रमाणपत्र द्यायचे असते. मात्र, या मंडळातील केवळ सदरच्या दिव्यांग प्रवर्गाशी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरच व्यक्तीची तपासणी करतात. इतर दोन डॉक्टरांसमोर ही व्यक्ती जातच नसल्याचा प्रकार अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात समोर आला आहे.

रुग्णालयाने दिलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेरपडताळणीची तरतूद कायद्यात नाही. काही आस्थापनांना संशय आल्यास त्या दिव्यांगांना फेरपडताळणीसाठी ससून अथवा अन्य रुग्णालयात पाठवतात. पण, तेथेही पुन्हा तीन सदस्यीय मंडळच तपासणी करते. त्या तपासणीवर अन्य विभागांचे नियंत्रण नसते. या तपासणीची वैद्यकीय कागदपत्रे सरकारी रुग्णालये माहिती अधिकारातही देत नाहीत. अशी सर्व एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याच्या व पडताळणीच्या प्रक्रियेत बिगरवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आवश्यक बनला आहे.

काय करायला हवे?

१. दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर वैद्यकीय मंडळातील तीनही सदस्यांची नावे व त्यांचे रुग्णासोबतचे छायाचित्र हवे. कारण तपासणीत काही डमी व्यक्ती उभ्या केल्याचे प्रकार घडले आहेत.

२. **व्यक्ती अथवा विद्यार्थी प्रथमदर्शनी दिव्यांग दिसतो, असे शिफारसपत्र स्थानिक रुग्णालये, लोकप्रतिनिधी, शासकीय आस्थापनांचे प्रमुख, शाळा-कॉलेजचे मुख्याध्यापक यांच्याकडून आल्यानंतरच जिल्हा रुग्णालयात तपासणी व्हायला हवी. तशी नोंद प्रमाणपत्रावर हवी.**

३. जात प्रमाणपत्र देताना तीन-चार पुरावे तपासले जातात. तसे दिव्यांग प्रमाणपत्र देतानाही सरकारी डॉक्टरांच्या तपासणीशिवाय अन्य पुराव्यांचीही जोड हवी.

४. **जात प्रमाणपत्राच्या धर्तीवर आजवरच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सक्तीने पडताळणी हवी. पडताळणी समितीत आरोग्याशिवाय अन्य अधिकारीही हवेत.**

" दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे अद्याप विचाराधीन नाही. शासकीय संकेतस्थळाचा गैरवापर करून प्रमाणपत्र काढली गेली किंवा धडधाकट व्यक्तींना दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचे पुरावे समोर आल्यास कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या सूचना आल्यास बदलांबाबत विचार केला जाईल.

विलास बेद्रे, उपसचिव, आरोग्य विभाग

दिव्यांगांची यादी संकेतस्थळावर द्यायला हवी

आरोग्य विभागाकडून लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सविस्तर यादी ही रुग्णालयांच्या संकेतस्थळावर असायला हवी.

'यूडीआयडी' क्रमाकांच्या सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे दस्तावेज शासकीय रुग्णालयात आहेत का? याचीदेखील राज्यभर तपासणी हवी.

जेथे जेथे महायुती शक्य तेथे प्रयत्न करणार : मुख्यमंत्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : जिथे शक्य आहे, तेथे महायुतीच होणार असून, जिथे शक्य नाही तिथे प्रयत्न करू. अन्यथा मैत्रीपूर्ण लढती लढू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी शहरात नियोजन बैठक झाली.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, या बैठकीत नाशिकसह अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील स्थानिक राजकीय परिस्थिती जाणून घेतली. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या निवडणुकीत चांगले यश मिळेल, अशी ग्वाही दिली. पुण्यातील गुंड घायवळ याला कोणताही शस्त्र परवाना दिला नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

मृत्यूनंतर होणारे हाल आता संपणार; स्मशानभूमी समिती घेणार आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील हजारो गावांमध्ये आजही कायमस्वरूपी स्मशानभूमी नसणे, त्यामुळे शेतशिवारात, पडीक जमिनीवर केले जाणारे अंत्यसंस्कार आणि त्यातून बरेचदा निर्माण होणारे सामाजिक ताणतणाव यांची दखल अखेर राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे मृत्यूनंतरही होणारे हाल संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही. त्यामुळे अंत्यसंस्कारात अनेक अडचणी येतात. काही समाजांनी खासगी जमीन खरेदी करून आपापल्या समाजबांधवांच्या अंत्यसंस्कारांची सोय केली आहे. काही गावांमध्ये सरकारी मालकीच्या जमिनींवर वर्षानुवर्षे अंत्यसंस्कार केले जातात. अनेक गावांमध्ये हिंदू, मुस्लिमांसाठी वेगवेगळ्या स्मशानभूमी नाहीत. मृत्यूनंतरही जातीपातीची भावना संपत नाही याचा विदारक अनुभव येतो.

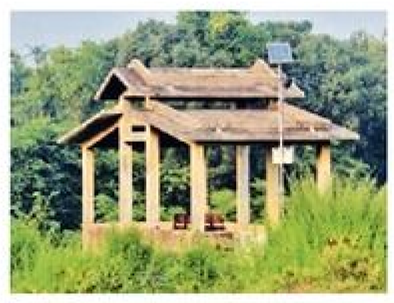

जाती-जातीत संघर्ष, मृतदेह नेला जातो पोलिस ठाण्यात

मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीच्या निधनानंतर गावात अंत्यसंस्कारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेवर त्यांना अंत्यसंस्कार करू देण्यास मनाई केली जाते. एखाद्या गावात स्थायी स्वरूपाची स्मशानभूमी असली तरी विशिष्ट समाजाबांधवांना तेथे अंत्यसंस्कार करण्यापासून रोखले जाते. त्यातून मग जातीजातींमध्ये संघर्ष उभा राहतो. मृताचे नातेवाइक मृतदेह घेऊन थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचले अशा घटनाही यापूर्वी बऱ्याच ठिकाणी घडल्या आहेत.

मंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेत नेमण्यात आली समिती

१. स्मशानभूमीचा अभाव व जातीय तणाव याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने एक समिती शुक्रवारी स्थापन केली. समिती ग्रामीण भागातील स्थितीचा अभ्यास करेल.

२. **ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हे समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये अभिमन्यू पवार, देवेंद्र कोठे, अमित गोरखे हे तीन आमदार, मनीष मेश्राम नागपूर, अशोक राणे बुलढाणा, ऋषिकेश सकनूर परभणी, गुरुप्रीतसिंग अहलुवालिया, अश्विनी चव्हाण सोलापूर, जयवंत तांबे मुंबई हे आहेत.**

३. स्मशानभूमींबाबत उपाययोजना, हिंदू दहनभूमी, दफनभूमीवर स्वतंत्र अभ्यास, गावातील सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी हिंदू स्मशानभूमी सर्व जातींना खुल्या करण्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना सुचविणे ही समितीची कार्यकक्षा असेल.

इंदिरा गांधीच म्हटल्या होत्या 'स्वातंत्र्यवीर'

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : सावरकर यांना स्वातंत्र्यवीर ही पदवी यांना कोणी पदवी दिली, असा प्रश्न काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला होता. मात्र, राहुल गांधी यांच्या आजी आणि माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी एका पत्रात तसा उल्लेख केला होता, हे पत्र नाशिकच्या न्यायालयात सावरकरप्रेमींनी सादर केले आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबरला होणार आहे.

खा. राहुल गांधी यांनी हिंगोली येथे एका सभेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर माफीवीर अशा स्वरूपाची टीका केली होती. त्यावर देवेंद्र भुतडा यांनी येथील न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात दावा दाखल केला आहे. यासंदर्भात भुतडा यांच्यावतीने ॲड. मनोज पिंगळे यांनी बाजू मांडली. स्वातंत्र्यवीर सावकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सचिवांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सावरकर यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे पत्र ८ मे १९८० रोजी पाठवले होते. त्यावर गांधी यांनी २० मे १९८० रोजी उत्तर पाठवले, त्याची सुरुवातच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे शौर्य अतुलनीय असल्याचा उल्लेख केला होता.

'शासनाचा आदेश हैदराबाद गॅझेटपुरताच मर्यादित'

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य शासनाने काढलेला आदेश हा हैदराबाद गॅझेटपुरता मर्यादित असून ओबीसींची माथी भडकवून संभ्रम निर्माण करू नये, असे आवाहन महसूलमंत्री व मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केले.

ते म्हणाले, जीआर काढताना कुणबी व्यक्ती ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहू नये, ही काळजी घेतली. सरकार ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, हेतू लक्षात न घेता निर्णयाविरुद्ध आकांडतांडव करून ओबीसींवर अन्याय होत आहे, असा संभ्रम निर्माण केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ओबीसी समाजाच्या रक्षणासाठी प्रभावीपणे काम करत आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन दिले.

मराठवाड्यात उद्धवसेनेतर्फे काढल्या जाणाऱ्या हंबरडा मोर्चाबाबत बावनकुळे म्हणाले, ज्यांनी मराठवाड्याच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून निजामासारखे व्यवहार केले; ते विकासाच्या गप्पा मारत आहेत.

एनडीएतील कॅडेटचा मृत्यू; न्यायालयीन चौकशीचे आदेश

पुणे : राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए), खडकवासला येथील पहिल्या वर्षाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेटचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

चार्ली (सी) स्क्वॉड्रनमध्ये नियुक्त असलेला प्रशिक्षणार्थी कॅडेट अंतरिक्षकुमार सिंह (वय १८) हा वसतिगृहात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृत आढळला. याबाबत चौकशीसाठी न्यायालयाची नियुक्त करण्यात आली असून, त्यानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे.अंतरिक्षकुमार सिंह हा मूळ उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील रहिवासी असून, त्याची निवड अकादमीच्या १५४ व्या कोर्ससाठी झाली होती.

प्रियकरासंगे पळाली; भिवंडीमध्ये सापडली

नागपूर : पारडीत राहणारी अल्पवयीन मुलगी २४ सप्टेंबरला कुणालाही काहीच न सांगता प्रियकरासोबत निघून गेली होती. पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी शोध घेतला असता ती ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे असल्याची माहिती कळाली. ती पोलिसांना अल्पवयीन मुलासोबत आढळली. पोलिसांनी तिला पालकांच्या हवाली केले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्र. उपमुख्य अभियंता/एस ओ/टीआर/१५२९, दि. ०९.१०.२०२५

ई-निविदा सूचना

विभाग:	सांडपाणी संचालन
उपविभाग:	उपमुख्य अभियंता (सांडपाणी संचालन) टीआर/ कार्यकारी अभियंता (खरेदी) सांडपाणी संचालन
निविदा क्रमांक:	०४/२०२५-२६
ई-निविदा आयडी क्रमांक:	२०२५_एमसीजीएम_१२२७७७५_१
विषय:	मुख्य अभियंता (सांडपाणी संचालन) विभागा अंतर्गत मुख्य सांडपाणी विभागांकरिता आवश्यक क्रोमोफ्लेक्स लवचिक स्टील रॉड्सचा पुरवठा करणे.
निविदा विक्री कालावधी:	दिनांक ११.१०.२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ते दिनांक ३१.१०.२०२५ रोजी दुपारी ०४.०० वाजेपर्यंत.
संकेतस्थळ:	https://mahatenders.gov.in
संपर्क व्यक्ती:	
अ) नाव:	सौ. स्मिता झोरे, सहाय्यक अभियंता (खरेदी), सांडपाणी संचालन
आ) मोबाईल क्रमांक:	९९८७१७३००७
इ) ई-मेल :	seproc01.so@mcgm.gov.in

निविदा सादर करण्याच्या किंवा उघडण्याच्या तारखांमध्ये व वेळांमध्ये काही बदल झाल्यास तसेच तांत्रिक तपशीलांमध्ये काही दुरुस्ती अथवा सुधारणा झाल्यास, त्यासंबंधी आवश्यक जोडपत्रक/शुद्धिपत्र मुंबई महानगरपालिकेमार्फत जारी केले जाईल. त्यासंबंधी माहिती बृन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळ http://portal.mcgm.gov.in वर प्रसिद्ध केली जाईल.

स्वाक्षरी/-
कार्यकारी अभियंता (खरेदी)
सांडपाणी संचालन विभाग

पीआरओ/१८७४/जाहिरात/२०२५-२६

खिडक्यांसाठी जाळ्यांचा व मच्छरदाण्यांचा वापर करा.

मस्ट READ

केवायसीसाठी नेटवर्क नाही, मग 'बहिणी' सातपुडा पर्वत चढून घेतात सिग्नलचा शोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

धडगाव (जि. नंदुरबार) : तालुक्याच्या नर्मदा काठावरील खर्डी खुर्द गावात महिलांना सध्या दररोज डोंगरावर चढाई करावी लागत आहे. ही चढाई पाणी किंवा सरपणासाठी नव्हे, तर लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवर अर्ज भरुन केवायसी करता यावी यासाठी आहे.

विशेष म्हणजे जीव धोक्यात घालून डोंगराची वाट चढल्यानंतरही मोबाईलचे नेटवर्क मिळत नाही. त्यामुळे केवायसी करता यावी यासाठी महिलांना तासन् तास डोंगरावर ऊन, वारा पाऊस झेलत बसावे लागत आहे. सातपुड्याच्या अनेक गावांत इंटरनेट सेवा नसल्याने माता-बहिणींवर ही स्थिती ओढावली आहे.

अनेक महिला मोबाइल झाडाच्या फांद्यांवर किंवा काठीला बांधून ठेवतात, जेणेकरून नेटवर्क मिळून ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.